चौथी दुनिया

www.chauthiduniya.com

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

मूल्य 5 रुपये

1986 से प्रकाशित

04 मई–10 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

संजय जोशी से किसे ख़तरा है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

“पिछले साल लोकसभा चुनाव में भारी-भरकम बहुमत हासिल करके केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी के अंदरखाने सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. वरिष्ठ और निष्ठावान नेताओं-कार्यकर्ताओं की अनदेखी संगठन के अंदर असंतोष पैदा कर रही है, जो दिनोंदिन गहराता जा रहा है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कार्यकर्ता संजय जोशी के जन्मदिन का मसला इसका ताजा उदाहरण है. आख़िर कौन है, जो भाजपा के आंतरिक लोकतंत्र को छिन्न-भिन्न करना चाहता है और अपनी मर्जी थोपना चाहता है, यह जानते हुए भी कि ऐसा करना संगठन के हित में नहीं होगा? और, इसके पीछे असल मकसद क्या है?”

संतोष भारतीय

नाम संजय विनायक जोशी. भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं या नहीं, पता नहीं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं, यह निश्चित है. आरोप है कि इनसे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता ज़्यादा मिलने आते हैं. इनके ऊपर यह भी आरोप है कि इनसे केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकारों के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशों के संगठन से जुड़े बड़े नाम अक्सर मिलने आते हैं. आख़िरी आरोप यह है कि संजय विनायक जोशी भारतीय जनता पार्टी में बहुत छोटा, लेकिन समानांतर सत्ता का केंद्र बनते जा रहे हैं.

अब इस व्यक्ति के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं. संजय विनायक जोशी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी में संजय भाई जोशी के नाम से जाना जाता है. यह नाम भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के स्तर पर बहुत आदर से लिया जाता है. आईआईटी से शिक्षा प्राप्त कर यह संघ के स्वयंसेवक बने और फिर भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री बन गए.

सारे देश में जाना जाता है कि इस व्यक्ति ने उस समय के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी से पंगा लिया और बाद में जब नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री बने, तब भी इन्होंने नरेंद्र भाई का विरोध तो नहीं किया, लेकिन अपनी बात पर हिमालय की तरह अडिग रहे. इसी छह अप्रैल को नॉर्थ एवेन्यू में इनके निवास स्थान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सादगी भरी भव्यता से इनका जन्मदिन मनाया. संजय जोशी का यह 54वां जन्मदिन था, जिसमें लगभग चार हज़ार कार्यकर्ता बिना किसी निमंत्रण और बिना आयोजन के संजय जोशी के निवास स्थान पर पहुंचे. इन चार हज़ार लोगों में सामान्य स्वयंसेवक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कॉरपोरेटर, एमएलए, सांसद, यहां तक कि कई मंत्री भी शामिल हुए. संजय जोशी को बधाई देने वालों में राजनाथ सिंह, मनोज तिवारी, ब्रह्म सिंह तंवर, रमेश बिधूड़ी, संजीव बालियान जैसे लोग शामिल थे. बधाई देने वालों में कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल थे. दरअसल, पिछले 11 महीने के शासनकाल में संजय जोशी ने नरेंद्र मोदी का खुलकर समर्थन किया और उनके कामों की भूरि-भूरि प्रशंसा भी की, लेकिन यह जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी में एक महत्वपूर्ण घटना की तरह देखा गया.

भारतीय जनता पार्टी में एक ऐसा समूह है, जो नरेंद्र मोदी के लिए ऐसे काम करना चाहता है, जिससे वही नरेंद्र मोदी के आस-पास दिखाई दे. भारतीय जनता पार्टी से जुड़े बाकी लोगों का नरेंद्र मोदी के आस-पास दिखने वालों में कोई स्थान न हो. इस समूह को सबसे बड़ी चिंता इस बात से हुई कि उसके सारे प्रयासों के बावजूद न संजय जोशी को कुचला जा सका, न संजय जोशी का चरित्र हनन किया जा सका, न संजय जोशी की हत्या की जा सकी. बल्कि इसके उल्टे संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच पहले से ज़्यादा लोकप्रिय होते दिखाई दिए और यह छह अप्रैल उसकी एक प्रतीकात्मक घटना के रूप में इस समूह द्वारा देखा गया. इस समूह को यह भी लगा कि जब सरकार नरेंद्र भाई मोदी की है, जो संजय भाई जोशी को पसंद नहीं करते, तब इसके बावजूद इतने लोग संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई देने क्यों आए? और, इस समूह ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को यह सफलतापूर्वक समझा दिया कि संजय जोशी को अगर तत्काल न रोका गया या उन्हें स्टैच्यू की मुद्रा में नहीं लाया गया, तो वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में उनकी शिकायतें सुनने वाला न केवल केंद्र बन जाएंगे, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को सही रास्ते पर लाने की मुहिम भी छेड़ सकते हैं.

संघ के वरिष्ठ लोगों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अहंकार आ गया है और उसी अहंकार में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन प्रमुख लोगों को फोन करना शुरू किया, जो लोग संजय भाई जोशी को बधाई देने वहां पहुंचे थे या जिन्होंने फोन से संजय भाई जोशी को बधाई दी थी. दरअसल, संघ का यह स्पष्ट मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अहंकार का समावेश हो गया है. सिर्फ़ फोन ही नहीं किए गए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को नोटिस भी दिए गए और यह जानने की कोशिश की गई कि आख़िर संजय जोशी के समर्थन वाले पोस्टर किसने लगाए, किसने छपवाए और सारे देश में वे कैसे लग गए? अभी किसी को पता नहीं है कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के साधारण सदस्य हैं भी या नहीं. लेकिन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मानना है कि संजय जोशी ने कभी पार्टी विरोधी काम नहीं किया. संजय जोशी उन कुछ गिने हुए लोगों में हैं, जो देश के सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की कार्यशैली, उनकी क्षमता और उनके क्रियाकलापों से परिचित हैं तथा लगभग हर नेता के अच्छे-बुरे कर्मों का हिसाब उनके पास है.

भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संजय जोशी की तीव्र बुद्धिमता के कायल हैं. वह उनसे हमेशा सलाह लेते रहते हैं. संघ को इस बात पर बड़ा अफ़सोस है कि जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन संगठन को दे दिया हो और जो हमेशा संगठन के हित में काम करता रहा हो, वह आज कुछ व्यक्तियों की जिद की वजह से हाशिये पर पड़ा हुआ है. संघ को इस बात पर भी गुस्सा है कि जब संजय जोशी से भाजपा के संगठन मंत्री के पद से इस्तीफ़ा देने के लिए नरेंद्र मोदी की जिद की वजह से कहा गया, तब संजय जोशी ने बिना कोई देर किए अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन उस समय पार्टी के प्रवक्ता प्रकाश जावेडकर ने मीडिया के सामने आकर घोषणा की कि संजय जोशी ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया. प्रकाश जावेडकर नरेंद्र मोदी के प्रिय पात्र बन गए और बिना चुनाव लड़े राज्यसभा में होने की वजह से महत्वपूर्ण मंत्री भी बन गए हैं. पर संघ को उनके इस आचरण के ऊपर न केवल दुःख है, बल्कि क्षोभ भी है.

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता संजय जोशी की तीव्र बुद्धिमता के कायल हैं. वह उनसे हमेशा सलाह लेते रहते हैं. संघ को इस बात पर बड़ा अफ़सोस है कि जिस व्यक्ति ने अपना सारा जीवन संगठन को दे दिया हो और जो हमेशा संगठन के हित में काम करता रहा हो, वह आज कुछ व्यक्तियों की जिद की वजह से हाशिये पर पड़ा हुआ है.

आधार कार्ड योजना : सरकार देश को भ्रमित कर रही है | P-3

डीएनडी : महाघोटाले का सेतु | P-5

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश सियासत जारी है | P-7

संजय जोशी से किसे ख़तरा है

पृष्ठ 1 का शेष

संघ का जब हम नाम लेते हैं, तो आप यह मान लें कि संघ के सात बड़े लोगों में से हम कुछ लोगों की समझ को आपके सामने रख रहे हैं. संघ का यह मानना है कि संजय जोशी गुरु गोलवलकर जी यानी गुरुजी और दीन दयाल उपाध्याय के आदर्शों पर बनी पार्टी का काम सबसे अच्छे से करने वाले लोगों में से एक हैं. संघ को इस बात का एहसास भी हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी अब गुजरात के चार महान पुत्रों की इच्छा से चलने के रास्ते पर चल पड़ी है. इनमें पहला नाम स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है, दूसरा नाम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह का है और तीसरा नाम श्री गौतम अडानी का है और चौथा नाम श्री मुकेश अंबानी का है. संघ को इस बात का एहसास है कि ये चारों महान गुजरातियों की टोली को जो पसंद नहीं आएगा, वह कालांतर में भारतीय जनता पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा. और इसीलिए, भारतीय जनता पार्टी में एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है कि इन चारों में से कोई न कोई उसका चेहरा पहचाने, उसके बारे में कुछ कहे, तभी वह भारतीय जनता पार्टी में या सरकार से जुड़ी हुई समितियों में कोई महत्वपूर्ण स्थान पा सकता है. संघ के भीतर अनौपचारिक तौर पर कई बार यह चर्चा चली है कि भारतीय जनता पार्टी को दस करोड़ सदस्यों की पार्टी बनाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया गया, वह ग़लत है. मिस्डकॉल के ज़रिये दस करोड़ की सदस्य संख्या वाली पार्टी में संजय जोशी जैसा व्यक्ति सदस्य नहीं है, यह बात संघ को सबसे ज़्यादा खल रही है. लेकिन, संघ ने यह तय किया है कि वह एक वर्ष तक श्री नरेंद्र भाई मोदी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा, पार्टी को लेकर यानी अमित शाह के क्रियाकलापों को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेगा. और, वह साल मई में पूरा हो रहा है. मई के बाद संघ मोदी सरकार पर अपना आकलन जारी करेगा. संघ को इस बात के ऊपर भी अफ़सोस है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी पार्टी यानी दस करोड़ की सदस्य संख्या वाली पार्टी बनाने में संजय जोशी का किसी से कम योगदान नहीं है, लेकिन अमित शाह संजय जोशी को किनारे रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. तब भी संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

संघ संजय जोशी की बातों को महत्व भी देता है और संघ के वरिष्ठ लोग समय-समय पर संजय जोशी से मिलते रहते हैं. जनवरी में अहमदाबाद में संघ की बैठक हुई, जिसमें गणवेश में संजय जोशी शामिल हुए. वहां पर पत्रकारों ने सर संघचालक श्री मोहन भागवत और श्री एमजी वैद्य से पूछा कि संजय जोशी का भविष्य क्या है, संजय जोशी के बारे में आपकी राय क्या है? इस पर दोनों ने कहा, संजय जोशी हमारे थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे. इसका मतलब संघ ने देश को साफ़ किया और संघ ने भारतीय जनता पार्टी को भी साफ़ किया कि संजय जोशी का स्थान संघ की नज़रों में जैसा था, वैसा ही है. संघ का यह मानना है कि संजय जोशी का कार्यकर्ताओं में बड़ा सम्मान है. इसका उदाहरण दिल्ली विधानसभा चुनाव है. दिल्ली विधानसभा चुनाव से कुछ हफ्ते पहले दिल्ली के कैंटोनमेंट का चुनाव हुआ, जिसमें भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीती. लेकिन, 20 दिनों में बिना संघ से मशविरा किए और बिना संजय जोशी से मशविरा किए भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण बेदी को पार्टी में ले आए और अचानक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह चुनाव में धीमा हो गया और उनकी रुचि समाप्त हो गई. संघ को यह जानकारी संजय जोशी ने उसी समय दे दी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब मन से चुनाव में नहीं लगे हैं. संघ की सारी कोशिशों के बावजूद कार्यकर्ता चुनाव में नहीं लगे और भारतीय जनता पार्टी की चुनाव में इतिहास की सबसे बुरी हार हुई. आज संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं और कार्यकर्ताओं की आशा का केंद्र बन गए हैं, जिनसे आज नेता या मंत्री नहीं मिल रहे हैं.

यह चिंता अब संघ को भी होने लगी है, पर ज़्यादा चिंता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में हो रही है कि जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, उन्हें किनारे किया जा रहा है. चाहे वह लालकृष्ण आडवाणी हों या मुरली मनोहर जोशी हों. लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के पास अब कार्यकर्ता जा नहीं रहा है. संगठन को चिंता इसीलिए हुई कि संजय जोशी के घर पर इतनी भीड़ कैसे हो गई और इसलिए संगठन ने सख्त क़दम उठाए. वहां जो मंत्री आए थे, उन्हें चेतावनी मिली, जिनमें श्रीपद नायक, सर्वानंद सोनेवाल, संजीव बालियान शामिल हैं. श्रीपद नायक के निजी सचिव नितिन सरदारे को फौरन निकाल देने का आदेश दिया गया और श्रीपद नायक ने नितिन सरदारे को तत्काल अपने पीए के पद से बर्खास्त कर दिया. यह चेतावनी शायद संगठन ने सभी लोगों को दी कि उनके ख़िलाफ़ भी ऐसी ही कार्रवाई हो सकती है. नितिन सरदारे का दोष सिर्फ़ इतना था कि वह कुछ स्वयंसेवकों के साथ संजय जोशी को बधाई देने छह अप्रैल को उनके घर चले गए. जब टेलीविजन पर यह मसला उछला कि नितिन सरदारे को श्रीपद नायक ने पार्टी के आदेश पर अपने निजी सचिव के पद से हटा दिया है, तो फौरन संघ के कान खड़े हुए और संघ ने पार्टी से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हो? संघ के इस नोटिस के बाद बाकी लोगों को निकालने की कार्रवाई फिलहाल रोक दी गई. पर हमारे सूत्र बताते हैं कि 84 लोगों की सूची (लिस्ट) भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने बनाई है और उन 84 लोगों के ऊपर धीरे-धीरे कार्रवाई होने वाली है. कुछ नाम सामने हैं, जिनसे सख्ती से पूछताछ हुई, जिनमें रमेश विधूड़ी, ब्रह्म सिंह तंवर, कैलाश विजयवर्गीय, चिंतामणि मालवीय, धर्मेंद्र प्रधान, नड्डा साहब और प्रवेश वर्मा प्रमुख हैं. इनमें श्रीपद नायक, सर्वानंद सोनेवाल, संजीव बालियान का नाम भी जोड़ लेना चाहिए. और, सबको चेतावनी दी गई कि भविष्य में यह हरकत न दोहराई जाए. लेकिन, एक और शख्स संजय जोशी को बधाई देने वालों में शामिल रहे हैं, देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह. राजनाथ सिंह से सवाल-जवाब करने की ताकत अभी पार्टी में किसी में नहीं है. लेकिन, ऐसा लगता है कि जिन 84 लोगों की सूची बनाई गई है, उनमें से कुछ के ख़िलाफ़ पार्टी धीरे-धीरे सख्त कार्रवाई करेगी और उन्हें संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई देने का इनाम अनुशासनात्मक दंड के रूप में मिलेगा.

संजय जोशी की कहानी पार्टी में तेजी से चिंता का विषय बन रही है, क्योंकि संघ के लोग कह रहे हैं कि श्रीनगर में पाकिस्तानी करेंसी चलाने का समर्थन करने वाले पीडीपी के साथ मौजूदा संगठन सरकार बना रहा है, अयोध्या में कारसेवकों पर गोली चलाने वाले मुलायम सिंह के पड़ोस में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष घंटों बैठे रहते हैं, आडवाणी जी को गिरफ्तार करने वाले लालू प्रसाद की बेटी की शादी और रिसेप्शन में प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष जाते हैं, आरएसएस को आतंकवादी संगठन कहने वाले शरद पवार के घर पार्टी के बड़े लोग नाश्ते पर जाते हैं और दूसरी तरफ़ आरएसएस के निष्ठावान प्रचारक संजय जोशी को उनके जन्मदिन पर बधाई देने वाले लोगों को पार्टी प्रताड़ित कर रही है. संघ के लोगों में यह सबसे बड़ी चिंता पैदा हुई है कि भारतीय जनता पार्टी जागकर सोए जा रही है और यह कहां पहुंचेगी? संघ को इस बात की चिंता है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के तौर पर और संगठनात्मक रूप से कमजोर हो रही है. पार्टी को यह लगता है कि वह दिल्ली में चुनाव हार चुकी है, बिहार में संपूर्ण विपक्ष एकजुट हो गया है, इसलिए वहां उसकी जीत के आसार कम नज़र आते हैं. संघ के इस बड़े नेता को यह भी चिंता है कि जब-जब कांग्रेस के ख़िलाफ़ विपक्ष ने एक होकर लड़ाई लड़ी, कांग्रेस हारी और आज वह स्थिति भारतीय जनता पार्टी के सामने आकर खड़ी हो गई है. इसलिए उन्हें डर है कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की जीत असंभव नहीं, तो महा-मुश्किल अवश्य है. और, संघ के इस वरिष्ठ नेता को यह भी लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी मायावती को अपने साथ नहीं ले पाई, तो वहां पर भी उसकी जीत में वैसा ही संदेह पैदा होगा, जैसा बिहार में है. वह यह भी कहते हैं कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो आगे किसी राज्य में उसके जीतने की संभावना बहुत धूमिल हो जाएगी.

जब मैंने संघ के इस वरिष्ठ नेता से जानना चाहा कि आख़िर इस कार्रवाई के पीछे कौन हो सकता है, जो यह जानते हुए भी कि संघ को यह पसंद नहीं आएगा और उसने यह काम किया? इस पर उनका कहना था, मैं साफ़ तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अमित शाह ने अपने सलाहकारों के कहने पर यह काम किया और ये वे सलाहकार हैं, जो संजय जोशी को लेकर नरेंद्र मोदी के गुस्से को अपने हक़ में घुमाना चाहते हैं. हालांकि, संघ के लोगों का अंदाज़ा है कि यह क़दम उठाने से पहले अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से अवश्य बातचीत की होगी. लेकिन क्या नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कह दिया होगा, कार्रवाई करो. ऐसा इन लोगों को नहीं लगता है. इन्हें लगता है कि यह सारी कार्रवाई एक छोटी सोच की वजह से की गई और संघ को इस बात का भी एहसास है कि इस कार्रवाई से उसके कार्यकर्ताओं में बड़ा गुस्सा है. मजे की बात यह है कि जो लोग संजय जोशी के जन्मदिन के समारोह में आए थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के ज़रिये से उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराई गई और उस रिकॉर्डिंग को भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में एनालाइज किया गया और पहचाना गया कि कौन-कौन है और जो लोग पहचाने गए, उनके साथ डांट-डपट की गई.

संघ को इस बात की जानकारी है कि पहले संगठन में यह बात हुई कि 4,000 लोगों को पार्टी से निकाल दिया जाए, पर फिर वहां यह सवाल उठा कि अगर 4,000 लोगों की जगह 40,000 संख्या हो गई, तो क्या होगा? इसलिए, जो भी जहां पद पर है, उसे पद से हटाओ और पार्टी का साधारण सदस्य बना रहने दो. हरियाणा में पार्टी के मंत्री एवं कार्यकारिणी के सदस्य जसवंत यादव को उदाहरण के लिए, उनके पद से हटा दिया गया और वह वहां पर साधारण सदस्य हैं. इस बात की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि संगठन को डर था कि इससे मीडिया में काफी शोर-शराबा होगा. संघ के इस वरिष्ठ नेता का यह भी कहना है कि जब आप पीडीपी के साथ मिल सकते हैं, मुलायम सिंह के घर जा सकते हैं, लालू यादव के घर जा सकते हैं, शरद पवार के घर जा सकते हैं, तो ऐसा कौन-सा आपराधिक काम संजय जोशी ने कर दिया है कि उनके घर जाने वाले कार्यकर्ताओं को आप सजा देते हैं, संजय जोशी को पार्टी से निकालने की बात करते हैं? उस कार्यकर्ता को, जो संघ के सबसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में से एक है और जिससे लगातार संघ के सारे वरिष्ठ लोग मिलते रहते हैं. और, यहीं पर संघ के लोगों का कहना है कि सबका साथ, सबका विकास का आधार लेकर इतने लोगों से मिला जा सकता है, तो सबका साथ-सबका विकास का आधार संजय जोशी के ऊपर पार्टी क्यों नहीं लागू करती?

अमित शाह के दो मुख्य सलाहकार हैं, पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल और पार्टी के सचिव श्याम जाजू. सारे राज्यों और सारे कार्यकर्ताओं से फोन पर डांट-डपट और पूछताछ श्याम जाजू ने की. संघ के इस वरिष्ठ नेता का कहना है कि श्याम जाजू क्या अपने मन से यह सारी कार्रवाई कर रहे थे या उन्हें रामलाल जी या अमित शाह जी ने ऐसा करने के लिए कहा था. ये सात्विक स्वभाव के संघ के लोग भारतीय जनता पार्टी में चल रही राजनीति से बहुत दु:खी हैं. संघ मई में अपनी राय पार्टी के बारे में रखेगा और संघ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकलापों से खुश नहीं है. इसका एक उदाहरण संघ के सारे आनुषांगिक संगठन हैं, जिनसे संघ ने कहा है कि वे अपनी मांगों के लिए अपने स्वर तेज करें या मांगें उठाते रहें. उदाहरण के लिए, भारतीय मज़दूर संघ सरकार के सुर में सुर नहीं मिला रहा है. संघ से जुड़े बाकी आनुषांगिक संगठन भी सुर में सुर नहीं मिला रहे हैं और यह इशारा पार्टी के बुद्धिमान कार्यकर्ता सीधे-सीधे समझ रहे हैं.

जो पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने, आडवाणी जी के घर के बाहर, प्रधानमंत्री के रास्ते में लगे थे, वे बहुत मजेदार हैं, जिसका पहला नारा है-सबका साथ, सबका विकास, फिर क्यों नहीं संजय जोशी का साथ. अब इसमें एक कहानी और है. भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्र है. वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं. वह कौन शख्स है, भारतीय जनता पार्टी का इतना ताकतवर, जिसने भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सारे सीसीटीवी कैमरे उस समय बंद करा दिए, जब संजय जोशी के पोस्टर भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के सामने लगाए गए? और यह एक बार नहीं, दो बार हुआ. एक बार पोस्टर हटाए गए, फिर दोबारा पोस्टर लगे और दोनों समय सीसीटीवी कैमरे बंद नज़र आए. उसी तरह आडवाणी जी का घर जेड प्लस सिक्योरिटी के अंदर आता है, वहां पर किसने पोस्टर लगवाए? वहां का भी कुछ पता नहीं चला. और, यहीं पर याद आती है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में बने स्ट्रांग रूम से दो करोड़ रुपये की चोरी. उस चोरी का आज तक पता नहीं चला कि वह पैसा कहां गया और उस चोरी को लेकर कोई एफआईआर भी नहीं लिखवाई गई.

भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के भीतर एक कमाल की बात है कि जब कोई ऐसी घटना होती है, तो वहां के सीसीटीवी कैमरे बंद हो जाते हैं और भारतीय जनता पार्टी को चलाने वाले लोग उसका कारण नहीं तलाश पाते. इसका मतलब कोई छिपा हुआ शख्स है, जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर चल रही बहुत सारी चीजों से खुश नहीं है. इसका दूसरा पहलू यह है कि पुलिस ने टोका नहीं पोस्टर लगाने वालों को, जबकि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय कार्यालय सर्वाधिक सुरक्षित क्षेत्रों में आता है. चौबीस घंटे वहां पुलिस की गाड़ियां खड़ी रहती हैं. जब ये पोस्टर टेलीविजन पर दिखाए जाने लगे, तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उन्हें दीवारों से हटाया. इतना ही नहीं. पोस्टर सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय और आडवाणी जी घर पर या प्रधानमंत्री के रास्ते के आसपास नहीं लगे, पोस्टर लगे अहमदाबाद में, राजकोट में, गुजरात के कम से कम सात शहरों में, लखनऊ में, पटना में, दक्षिण के कुछ राज्यों में. लखनऊ में संजय जोशी के जन्मदिन पर मिठाइयां बांटी गईं. यह सब कैसे हुआ, कैसे इतना ऑर्गनाइज्ड तरीके से हुआ? इसके पीछे ज़रूर भारतीय जनता पार्टी के भीतर का तंत्र या और उस तंत्र का कोई ताकतवर शख्स या ताकतवर ग्रुप शामिल है.

संजय जोशी का प्रकरण यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है. भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ा वर्ग संजय जोशी को पार्टी में लेना चाहता है. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ चल रहा है, उससे खुश नहीं है, क्योंकि संघ के कुछ वरिष्ठ नेताओं का यह भी कहना है कि अमित शाह संकीर्ण मानसिकता या अभी तक वह स्वयं को गुजरात के मनोविज्ञान से ऊपर उठा ही नहीं पाए. पर जो भी हो, भारतीय जनता पार्टी में पहली बार एक पर्दा उठा है और पता चला है कि इतने कड़े अनुशासन, इतने सख्त प्रधानमंत्री, इतने सख्त पार्टी अध्यक्ष के होते हुए भी कोई है, जो इन सब चाल-चरित्र से सहमत नहीं है. वह व्यक्ति भी हो सकता है, वह ग्रुप भी हो सकता है, पर है वह शक्तिशाली. वह कौन है, इसका पता भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं. ■

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

वर्ष 07 अंक 09
दिल्ली, 04 मई–10 मई 2015
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

एडिटर (इंवेस्टिगेशन)
प्रभात रंजन दीन

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार-झारखंड)
सरयू भवन, वेस्ट बोरिंग केनाल रोड,
हरीलाल स्वीट्स के निकट, पटना-800001
फोन: 0612 3211869, 09431421901

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210-211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के- 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय
के-2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ-2, सेक्टर -11, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश-201301

फोन न.

संपादकीय	0120-6451999
	6450888
विज्ञापन व प्रसार	022-42296060
	+91-8451050786
	+91-9266627379
फैक्स न.	0120-2544378

पृष्ठ-16+4 (बिहार-झारखंड, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड) हर शुक्रवार को प्रकाशित

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुन: प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

editor@chauthiduniya.com

आधार कार्ड योजना

सरकार देश को भ्रमित कर रही है

मनीष कुमार

जदयू सांसद केसी त्यागी ने आधार कार्ड योजना से होने वाले ख़तरे पर सरकार से सवाल पूछे. इन सवालों पर सरकार की ओर से मिले जवाब भ्रमित करने वाले हैं. सरकार की तरफ़ से योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने अपने पत्र में उन्हीं दलीलों को दोहराया है, जो पिछले कई सालों से कांग्रेस सरकार देती रही. सरकार ने अपने जवाब में लिखा कि आधार कार्ड योजना सरकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए शुरू की गई है. इससे ग़रीबों का फ़ायदा होगा. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना ग़लत है और इसके अभाव में किसी का नुक़सान नहीं होना चाहिए. कहने मतलब यह कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश और सरकार की दलीलों में विरोधाभास है. एक तरफ़ सरकार कह रही है कि आधार कार्ड को सरकारी योजनाओं में इस्तेमाल किया जाएगा, वहीं अदालत कह रही है कि इसे किसी योजना से जोड़ना और अनिवार्य करना ग़लत है. दरअसल, सच्चाई यह है कि कई सालों से सरकार की तरफ़ से भ्रम फैलाया जा रहा है. जनता को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि आधार कार्ड बनते ही देश में सरकारी काम आसान हो जाएगा, सारी योजनाएं सफल होने लगेंगी. जो योजना ग़रीबों तक नहीं पहुंच पाती, वह पहुंचने लगेगी और सभी लोगों को बीज एवं खाद की सब्सिडी मिलने लगेगी. सवाल तो केवल इतना ही है कि अगर यह सब नहीं हुआ, तो इसके लिए किसे ज़िम्मेदार माना जाएगा?

राज्यसभा में सांसद केसी त्यागी ने जो सवाल पूछा था, उसका सार यह था कि क्या आधार कार्ड से जुड़ी बायोमीट्रिक जानकारियां किसी विदेशी कंपनी या एजेंसी के साथ साझा की जा रही हैं या नहीं? लेकिन सरकार ने अपने जवाब में इस सवाल को ही गायब कर दिया. सरकार ने जो जवाब दिया, उसमें यह कहा गया कि आधार को जब किसी योजना से जोड़ा जाता है, तो डाटा साझा नहीं किया जाता. साथ ही यह बताया गया कि किसी भी व्यक्ति की पहचान की प्रामाणिकता यूआईडीएआई के सेंट्रल सर्वर द्वारा ही सत्यापित होती है. लेकिन, सवाल यह है कि अगर यूआईडीएआई का सेंट्रल सर्वर ही विदेशी कंपनियों के हाथ में हो, तो इसे क्या कहा जाएगा? केसी त्यागी के सवाल के जवाब में सरकार को यह बताना चाहिए कि सेंट्रल सर्वर में किन-किन कंपनियों और लोगों का एक्सेस है. हक़ीक़त यह है कि मनमोहन सरकार के दौरान यूआईडीएआई ने आधार की कार्यप्रणाली के संचालन के लिए तीन कंपनियों को चुना था. ये कंपनियां हैं एसेंचर, महिंद्रा सत्यम-मोर्फो और एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन. इन तीनों कंपनियों पर ही इस कार्ड से जुड़ी सारी ज़िम्मेदारियां हैं.

दरअसल, कई सालों से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने विदेशी कंपनियों के साथ हुए समझौते को छिपाकर रखा. कई लोगों ने आरटीआई के तहत जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन कभी जवाब नहीं मिला. प्राधिकरण ने यह कभी नहीं बताया कि एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन, एसेंचर और दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ क्या समझौता हुआ है. हक़ीक़त यह है कि एक सितंबर, 2010 को भारत सरकार और एसेंचर कंपनी के बीच करार हुआ था. हालांकि, इस बात का ख़ुलासा नहीं किया गया कि एसेंचर सर्विस लिमिटेड एक अमेरिकी कंपनी की सहायक कंपनी है, जो आयरलैंड के डबलिन से ऑपरेट होती है. एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन भी एक अमेरिकी कंपनी है, जिसमें अमेरिका के ख़ुफ़िया और सैन्य अधिकारी बोर्ड मेंबर हैं और यह कंपनी अमेरिकी ख़ुफ़िया एजेंसी के साथ काम करती आई है. अब इस कंपनी का फ्रांस के साफ्रान ग्रुप में विलय हो चुका है. देश में लोगों का सारा बायोमीट्रिक डाटा इन्हीं दोनों कंपनियों को सौंपा जाएगा, क्योंकि करार के मुताबिक़ यूआईडी डाटा का ऑपरेशन इन्हीं कंपनियों के हाथों में है. हैरानी की बात यह है कि साफ्रान ग्रुप में फ्रांस सरकार की हिस्सेदारी है और साथ-साथ अगले चालीस सालों तक चीन के साथ उनकी पार्टनरशिप है.

यूआईडी और एसेंचर कंपनी के बीच हुए समझौते का अनुच्छेद 15.1 कहता है कि इस अनुबंध के तहत एसेंचर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड या एसेंचर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की टीम भारत के किसी भी निवासी की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकती है.

चौथी दुनिया

आधार कार्ड ख़तरनाक है

मोदी सरकार इन सवालों का जवाब दे

आधार कार्ड वह सच, जो छिपा दिया गया P-2

आधार कार्ड यूआईडी कार्ड नाज़ियों की याद दिलाता है P-2

आधार कार्ड देश को गिरवी रखने का षड्यंत्र P-9

कहने का मतलब यह कि जो डाटा यूआईडी के नाम पर इकट्ठा किया जा रहा है, वह सुरक्षित नहीं है. यह डाटा अमेरिका, फ्रांस और चीन के हाथ लग सकता है. इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इसे किसी और देश को नहीं बेचा जा सकता है. इन जानकारियों का ग़लत इस्तेमाल हो सकता है. इसमें एक और ध्यान देने वाली बात है. सरकार को बताना चाहिए कि क्या यह बात सही नहीं है कि फरवरी, 2014 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की साइबर सिक्योरिटी पर एक रिपोर्ट आई थी और उसमें यह चेतावनी दी गई कि आधार कार्ड योजना न सिर्फ़ राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता है, बल्कि नागरिकों की संप्रभुता एवं निजता के अधिकार पर हमला भी है. क्योंकि, जिस तरह से लोगों का बायोमीट्रिक डाटा क्लाउड टेक्नोलॉजी के तहत स्टोर किया जा रहा है, उस पर देश की सरकार का कोई अधिकार नहीं है. देश का क़ानून उस पर लागू नहीं हो सकता है. अगर लोगों की जानाकरियां कॉपी भी हो गईं या कोई उन्हें हैक करके हासिल कर लेता है, तो उसके ख़िलाफ़ भारत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगा. अब तो यह बात देश का बच्चा-बच्चा जानता है कि जो डाटा एक बार देश के बाहर चला गया, उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रह जाता. डिजिटल डाटा की कॉपी बनाना न सिर्फ़ आसान है, बल्कि उसमें समय भी नहीं लगता.

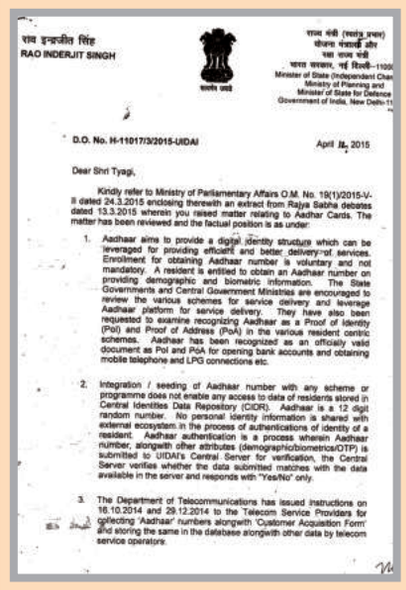

राव इन्द्रजीत सिंह
RAO INDERJIT SINGH

Minister of State (Independent Charge) Ministry of Planning and Minister of State for Defence Government of India, New Delhi

D.O. No. H-11017/3/2015-UIDAI

April 2015

Dear Shri Tyagi,

Kindly refer to Ministry of Parliamentary Affairs O.M. No. 19(1)/2015-V-II dated 24.3.2015 enclosing therewith an extract from Rajya Sabha debates dated 13.3.2015 wherein you raised matter relating to Aadhar Cards. The matter has been reviewed and the factual position is as under:

1. Aadhaar aims to provide a digital identity structure which can be leveraged for providing efficient and better delivery of services. Enrollment for obtaining Aadhaar number is voluntary and not mandatory. A resident is entitled to obtain an Aadhaar number on providing demographic and biometric information. The State Governments and Central Government Ministries are encouraged to review the various schemes for service delivery and leverage Aadhaar platform for service delivery. They have also been requested to examine recognizing Aadhaar as a Proof of Identity (PoI) and Proof of Address (PoA) in the various resident centric schemes. Aadhaar has been recognized as an officially valid document as PoI and PoA for opening bank accounts and obtaining mobile telephone and LPG connections etc.

2. Integration / seeding of Aadhaar number with any scheme or programme does not enable any access to data of residents stored in Central Identities Data Repository (CIDR). Aadhaar is a 12 digit random number. No personal identity information is shared with external ecosystem in the process of authentications of identity of a resident. Aadhaar authentication is a process wherein Aadhaar number, alongwith other attributes (demographic/biometrics/OTP) is submitted to UIDAI's Central Server for verification, the Central Server verifies whether the data submitted matches with the data available in the server and responds with "Yes/No" only.

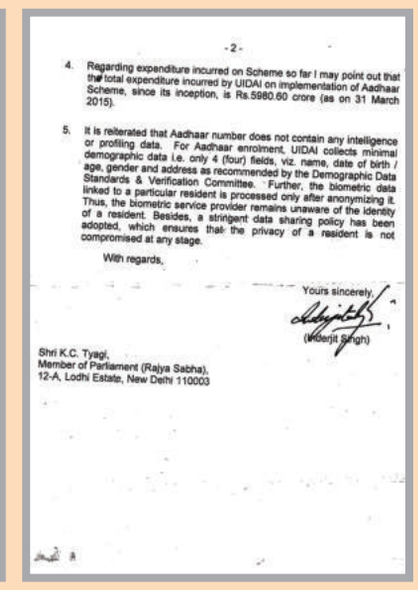

3. The Department of Telecommunications has issued instructions on 16.10.2014 and 29.12.2014 to the Telecom Service Providers for collecting 'Aadhaar' numbers alongwith 'Customer Acquisition Form' and storing the same in the database alongwith other data by telecom service operators.

-2-

4. Regarding expenditure incurred on Scheme so far I may point out that the total expenditure incurred by UIDAI on implementation of Aadhaar Scheme, since its inception, is Rs.5980.60 crore (as on 31 March 2015).

5. It is reiterated that Aadhaar number does not contain any intelligence or profiling data. For Aadhaar enrolment, UIDAI collects minimal demographic data i.e. only 4 (four) fields, viz. name, date of birth / age, gender and address as recommended by the Demographic Data Standards & Verification Committee. Further, the biometric data linked to a particular resident is processed only after anonymizing it. Thus, the biometric service provider remains unaware of the identity of a resident. Besides, a stringent data sharing policy has been adopted, which ensures that the privacy of a resident is not compromised at any stage.

With regards,

Yours sincerely,

(Inderjit Singh)

Shri K.C. Tyagi,
Member of Parliament (Rajya Sabha),
12-A, Lodhi Estate, New Delhi 110003

यूआईडी और एसेंचर कंपनी के बीच हुए समझौते का अनुच्छेद 15.1 कहता है कि इस अनुबंध के तहत एसेंचर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड या एसेंचर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड की टीम भारत के किसी भी निवासी की व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग कर सकती है. कहने का मतलब यह कि इस करार के तहत विदेशी कंपनियां देश के लोगों के बायोमीट्रिक डाटा का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र हैं. समझौते के अनुच्छेद 15.1 में यह भी कहा गया कि एसेंचर कंपनी इस डाटा को सात सालों तक अपने पास रख सकती है. सात सालों में तो भारत के लोगों की बायोमीट्रिक जानकारियों की इतनी कॉपियां बन जाएंगी कि कोई यह भी पता नहीं लगा पाएगा कि ओरिजनल यानी असली किसके पास है. इसी तरह का समझौता एल-1 आईडेंटिटी सोल्यूशन ऑपरेटिंग कंपनी के साथ कर लिया गया. इसके अलावा, यूआईडी/आधार कार्ड फॉर्म के कॉलम नंबर 9 में एक अजीबोग़रीब बात लिखी हुई है. इसे एक शपथ के रूप में लिखा गया है. कॉलम नंबर 9 में लिखा है कि यूआईडीएआई को उसके (आवेदक) द्वारा दी गई सारी जानकारियां किसी कल्याणकारी सेवा में लगी एजेंसियों को देने में उसे कोई ऐतराज़ नहीं है. इस कॉलम के आगे हां और ना के बॉक्स बने हैं. दरअसल, इस हां और ना का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फॉर्म भरने वाले लोग हां पर टिक लगा देते हैं.

बंगलुरु में यूआईडीएआई के डिप्टी चेयरमैन ने यह घोषणा की कि यूआईडीएआई पुलिस जांच में लोगों की जानकारी मुहैया कराएगा. सवाल यह है कि क्या पुलिस एक कल्याणकारी सेवा करने वाली एजेंसी है? समस्या यह है कि इस फॉर्म पर कल्याणकारी सेवा में लगी एजेंसियों के नाम ही नहीं हैं. इसका मतलब यह है कि यूआईडीएआई जिसे भी कल्याणकारी सेवा में लगी एजेंसी मान लेगी, उसके साथ वह लोगों की जानकारियां साझा कर सकती है. यानी एक बार लोगों ने अपनी जानकारियां दे दीं, तो उसके बाद उन जानकारियों के इस्तेमाल पर उनका कोई अधिकार नहीं रह जाएगा. ■

manishbph244@gmail.com

व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट

पहले पास हुआ, फिर खो गया और अब संशोधन

शशि शेखर

अशोक खेमका, दुर्गाशक्ति नागपाल, संजीव चतुर्वेदी जैसे अधिकारियों का नाम तो आपने सुना ही होगा. कई साल पहले राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के एक इंजीनियर थे सत्येंद्र दूबे. उन्हें बिहार के गया सर्किट हाउस में गोली मार दी गई थी. उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को सीधे पत्र लिखकर एनएचएआई में भ्रष्टाचार के संबंध में जानकारी दी थी, लेकिन पीएमओ ने उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की. उल्टे यह ख़बर भी आई थी कि पीएमओ से ही इस शिकायत की जानकारी लीक की गई थी. इसी तरह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में व्याप्त भ्रष्टाचार को सामने लाने वाले आईओसी के अधिकारी मंजूनाथ की भी हत्या कर दी गई. मंजू आईआईएम लखनऊ के पूर्व छात्र थे. आरटीआई क़ानून 2005 में लागू हुआ था, तबसे अब तक सैकड़ों आरटीआई कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है. कुल मिलाकर यह कि जो भी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएगा, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा.

बहरहाल, 2010 में यूपीए-2 सरकार एक बिल लेकर आई. नाम था, पब्लिक इंटरेस्ट डिसक्लोज़र एंड प्रोटेक्शन फॉर पर्सन्स मेकिंग डिसक्लोज़र बिल 2010. संक्षेप में कहें, तो व्हिसल ब्लोअर बिल 2010. व्हिसल ब्लोअर बिल 2010 में सरकारी धन के दुरुपयोग और सरकारी संस्थाओं में हो रहे घोटालों की जानकारी देने वाले व्यक्ति को व्हिसल ब्लोअर माना गया यानी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाला. इस बिल में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) को अतिरिक्त अधिकार दिए गए. सीवीसी को दीवानी अदालत जैसी शक्तियां भी देने की बात कही गई. सीवीसी भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वालों के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक कार्रवाई रोक सकता है. भ्रष्टाचार की जानकारी देने वाले की पहचान गुप्त रखने की ज़िम्मेदारी सीवीसी की है. अगर पहचान उजागर होती है, तो ऐसे अधिकारियों के ख़िलाफ़ शिक़ायत भी की जा सकेगी.

इस विधेयक के दायरे में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी भी शामिल हैं. बहरहाल, इस विधेयक में सीवीसी को जितनी ज़िम्मेदारी सौंपी गई, सीवीसी उसे पूरा कर पाने में सफल होगा या नहीं, यह एक सवाल था. जैसे, क्या सीवीसी की सांगठनिक संरचना इतनी बड़ी है, जिससे वह भारत जैसे बड़े देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की समस्या से लड़ पाए? राज्यों, ज़िलों और पंचायतों में फैले भ्रष्टाचार से कैसे निबटेगा सीवीसी? यह विधेयक 2011 में ही लोकसभा से पारित हो गया था, लेकिन उच्च सदन से पारित होने में इसे लंबा समय लगा. खैर, यूपीए-2 ने अंतिम समय में जब इस विधेयक को पारित कराने के लिए राज्यसभा में पेश किया, तो भाजपा ने कुछ संशोधन पेश किए थे. यूपीए-2 सरकार ने इन संशोधनों को ज़रूरी बताते हुए स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन उच्च सदन में बहस के दौरान यूपीए ने भाजपा से इस बिल को दोबारा निचले सदन में भेजने का दबाव न बनाने का आग्रह भी किया था. संसद ने इस विधेयक को पारित कर दिया था, जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी.

राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर 9 मई, 2014 को हस्ताक्षर किए जाने के बावजूद सरकार ने अब तक इसे क़ानून के तौर पर लागू नहीं किया है. सवाल है कि एक साल बीतने के बाद भी इस बहुप्रतिक्षित क़ानून को (पारित किए जाने के बाद भी) लागू क्यों नहीं किया गया, जबकि पिछले कई सालों से पूरे देश के सामाजिक कार्यकर्ता सरकार से मांग करते रहे हैं कि भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ बिगुल बजाने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाए. एक ऐसा क़ानून बनाया जाए, जिससे इस तरह के लोगों की पहचान गुप्त रखी जा सके. अब जब क़ानून बना भी, तो उसे लागू नहीं किया गया. अब, इस क़ानून को लागू करने की जगह एक बार फिर मौजूदा केंद्र सरकार इसमें संशोधन की बात कह रही है. केंद्र की एनडीए सरकर ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों को व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्टशन एक्ट के दायरे से बाहर रखने के लिए क़ानून में संशोधन का प्रस्ताव रखा है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के प्रस्ताव के मुताबिक, एक ऐसी प्रणाली भी होनी चाहिए, जिसके तहत यह तय किया जा सके कि इस क़ानून के अंतर्गत कौन-सी जानकारी सार्वजनिक की जा सकती है. सरकार क़ानून में संशोधन कर देश की संप्रभुता और अखंडता से जुड़ी जानकारियों को इसके दायरे से बाहर करना चाहती है.

अब सवाल यह है कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में किस तरह का संशोधन करना चाहती है? आख़िर भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने से राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को किस तरह से ख़तरा हो सकता है? अगर इस क़ानून में संशोधन करना ही है, तो होना यह चाहिए था कि इस क़ानून की संस्थागत संरचना पर विचार हो. यह सोचना चाहिए कि आरटीआई क़ानून के लिए तो केंद्रीय सूचना आयोग के साथ राज्य सूचना आयोग भी हैं. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए तो ज़िला स्तर तक आयोग गठित किए गए हैं. फिर भ्रष्टाचार जैसी संवेदनशील समस्या से निपटने के लिए सिर्फ़ सीवीसी ही क्यों?

अब सवाल यह है कि सरकार भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में किस तरह का संशोधन करना चाहती है? आख़िर भ्रष्टाचार के मामले उजागर होने से राष्ट्र की अखंडता और सुरक्षा को किस तरह से ख़तरा हो सकता है? अगर इस क़ानून में संशोधन करना ही है, तो होना यह चाहिए था कि इस क़ानून की संस्थागत संरचना पर विचार हो. यह सोचना चाहिए कि आरटीआई क़ानून के लिए तो केंद्रीय सूचना आयोग के साथ राज्य सूचना आयोग भी हैं. उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए तो ज़िला स्तर तक आयोग गठित किए गए हैं. फिर भ्रष्टाचार जैसी संवेदनशील समस्या से निपटने के लिए सिर्फ़ सीवीसी ही क्यों? वह भी सिर्फ़ केंद्रीय स्तर पर? यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे में सीवीसी के काम का दायरा कितना बड़ा हो जाएगा और वह अपने तीन सदस्यों के बूते कितना बोझ ढो पाएगा. देखते हैं, व्हिसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्टशन एक्ट में अब किस तरह के संशोधन होते हैं और उनके क्या मायने निकल कर सामने आते हैं. ■

shashishekhar@chauthiduniya.com

बिहार

धान घोटाला बनेगा चुनावी मुद्दा

सरोज सिंह

पूरे देश में किसानों के बीच अभी भले ही भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर बहस छिड़ी है, लेकिन बिहार के किसान धान की खरीद, उसमें हुए घपले और फिर उस पर हो रही राजनीति को लेकर तबाह हैं. राज्य सरकार कहती है कि किसी भी हाल में किसानों का अहित नहीं होने देंगे, केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये के चलते कुछ परेशानी हो रही है, लेकिन हालात नियंत्रण में हैं और किसानों को उनका वाजिब हक़ मिलेगा. उधर केंद्र सरकार में बैठे बिहार कोटे के मंत्री किसानों को हो रही परेशानियों का ठीकरा राज्य सरकार के सिर फोड़ रहे हैं. उनका कहना है कि राज्य सरकार चीजों को सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रही है और उसकी नीयत ठीक नहीं है. इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय की अथक मेहनत से यह मामला पटना हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच गया और अदालत ने इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए कहा है कि धान खरीद की जांच किसी बड़ी एजेंसी से कराना ज़रूरी लग रहा है.

शिव प्रकाश राय बताते हैं कि चारा घोटाला तो इस घोटाले के सामने कुछ भी नहीं है. पिछले तीन सालों में चावल मिलों को दिया गया 2,673 करोड़ रुपये का धान छू-मंतर हो गया है. ये आंकड़े आरटीआई के तहत मांगी गई सूचना में उजागर हुए हैं, जबकि सरकार के मुताबिक, केवल 1,581 करोड़ रुपये की वसूली होनी है, जिसमें से 162 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है. इसके अलावा बेस गोदाम में 2011-12 से लेकर 2013-14 तक 219 करोड़ रुपये का धान बर्बाद हो गया. इस संबंध में 122 पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हुई है और 17 के ख़िलाफ़ प्राथमिकी भी दर्ज की गई है. आरटीआई कार्यकर्ता शिव प्रकाश राय के मुताबिक, चावल मिलों को धान देने से पहले उसके एवज में चावल ले लेने का प्रावधान है. इस प्रावधान के उल्लंघन के कारण ही यह स्थिति पैदा हुई.

बेस गोदाम से संबंधित आंकड़े उपलब्ध कराते हुए राय ने कहा कि सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. यह बड़ा घोटाला है और इसमें बड़े-बड़े लोग शामिल हैं. हम 2012 से ही निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखते रहे हैं, मगर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. अब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है और पूरी उम्मीद है कि वहां से न्याय ज़रूर मिलेगा. अदालत को बताया गया है कि बीएसएफसी द्वारा धान की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां की जा रही हैं. केवल एक साल में ही चार सौ करोड़ रुपये की गड़बड़ी सामने आई है. मिल मालिकों, अधिकारियों एवं बिचौलियों की मिलीभगत से घोटाले का खेल जारी है. एक अनुमान के अनुसार, अगर जांच हो, तो घोटाले की राशि दो हज़ार करोड़ का आंकड़ा पार कर जाएगी. सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2011-12 में चावल मिलों से वसूली न होने के कारण 433.94 करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ.

धान खरीद में जो खेल होता है, उसे पहले सीधे शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं. बिहार में धान की खरीद पैक्स और बिहार राज्य खाद्य निगम के क्रय केंद्रों में होती है. वर्ष 2014-15 के लिए राज्य सरकार ने 1,350 रुपये प्रति क्विंटल और उसके साथ केंद्र सरकार का 300 रुपये बोनस यानी 1,650 रुपये प्रति क्विंटल का रेट तय कर रखा है. अब किसानों को पहली दिक्कत आती है अपनी फसल को खलिहान से पैक्स और क्रय केंद्र तक पहुंचाने में. अक्सर देखा गया है कि किसान ट्रैक्टर या किसी दूसरे साधन से धान उन केंद्रों तक ले जाते हैं, लेकिन अगर वहां सेटिंग नहीं है, तो उनकी फसल गुणवत्ता या फिर किसी और आधार पर दो-तीन दिनों तक रोक दी जाती है. नतीजा यह होता है कि किसानों को वाहन के किराये के रूप में ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं. बेचारे किसान इस तबाही से बचने के लिए सेटिंग का सहारा लेते हैं और अपनी फसल औने-पौने दामों पर बिचौलियों को बेच देते हैं. जो किसान अपने बलबूते पर धान बेचने में सफल हो जाते हैं, उन्हें भुगतान को लेकर कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और फिर सेटिंग तकनीक से ही उनका काम हो पाता है.

असली खेल शुरू होता है धान खरीद के बाद. कागज पर बने यानी फर्जी मिल मालिकों को भी धान दे देने का मामला सामने आया है. जबकि

नियम यह है कि पहले मिल मालिक से चावल लेना है और फिर बाद में उसे धान देना है, लेकिन सूबे में उल्टी गंगा बहा दी गई है. एक क्विंटल धान के एवज में 67 किलो चावल देने का प्रावधान है. घोटाले का आलम यह है कि करोड़ों रुपये का धान बेस गोदाम में सड़ा हुआ दिखा दिया जाता है. सूत्र बताते हैं कि ऐसा इसलिए किया जाता है, क्योंकि वह धान औने-पौने दामों में मिलों को दे दिया जाता है. रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए धान को सड़ा हुआ दिखाना ज़रूरी हो जाता है. ऐसे अनेक रास्ते हैं, जिनके माध्यम से किसानों को परेशान कर उनका धान मिल मालिकों को दे दिया जाता है. इस तरह किसानों को बर्बाद किया जा रहा है. अब यह तो जांच से पता चलेगा ही कि आख़िर किसानों का असली गुनहगार कौन है, लेकिन चुनावी साल होने के कारण राजनीतिक दल इस मामले को जोर-शोर से सदन से लेकर सड़क तक उछाल रहे हैं.

जदयू का कहना है कि केंद्र सरकार को बिहार के किसानों की कोई चिंता नहीं है. पहले तो वह धान खरीद के समय को लेकर राजनीति करती है और अब बोनस को लेकर ग़लतबयानी कर रही है. पार्टी प्रवक्ता नीरज सिंह कहते हैं कि मोदी सरकार ने तो किसानों को बर्बाद करने की कसम खा ली है. भूमि अधिग्रहण बिल इसका ताजा उदाहरण है. जहां तक धान खरीद का सवाल है, तो शुरू से ही केंद्र सरकार की नीयत साफ़ नहीं है. नरेंद्र मोदी के मंत्री ग़लतबयानी करके किसानों को गुमराह कर रहे हैं, लेकिन नीतीश सरकार किसी भी हाल में किसानों का अहित नहीं होने देगी. दूसरी तरफ़ भाजपा इसे लेकर काफी आक्रामक हो गई है. विधानसभा सत्र में भी भाजपा ने यह मामला जोर-शोर से उठाया और जांच की मांग की. भाजपा को लगता है कि किसानों का समर्थन हासिल करने के लिए धान खरीद के मामले को ज़िंदा रखना और उसे जांच के दायरे में पहुंचाना ज़रूरी है. भाजपा की रणनीति है कि चुनावी भाषणों में धान घोटाले का मामला जोर-शोर से उठाया जाए. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कौन-सा दल अपनी रोटी ज़्यादा अच्छी तरह से सेंक पाता है, क्योंकि किसानों को भरोसा तो अब केवल अदालत पर रह गया है.

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्याम रजक ने बताया कि डिफाल्टर चावल मिलों से 162 करोड़ रुपये की वसूली की जा चुकी है और 1,418 करोड़ रुपये की वसूली अभी बाकी है. डिफाल्टर 2,058 चावल मिलों में से 293 ने धनराशि जमा कर दी है. 1,525 मिलों के ख़िलाफ़ सर्टिफिकेट केस किए गए हैं, जबकि 203 के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज की गई है. उन सभी 1,525 मिलों के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है, जिनके ख़िलाफ़ सर्टिफिकेट केस किए गए हैं. श्याम रजक ने बेस गोदाम के संबंध में बताया कि 122 पदाधिकारियों पर कार्रवाई शुरू की गई है और उनसे 1.25 करोड़ रुपये वसूले गए हैं, जबकि 17 के ख़िलाफ़ प्राथमिकी दर्ज हुई है. बरामद किए गए धान की नीलामी से 12.01 करोड़ रुपये हासिल हुए हैं. वहीं बरामद किया गया 1.44 लाख मीट्रिक टन धान अभी बेस गोदाम में रखा हुआ है. पूरे प्रकरण पर सीएजी रिपोर्ट में कहा गया कि 2011-12 में चावल मिलों से वसूली से 43.94 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

बेस गोदाम में धान की स्थिति

वर्ष 2011-12	
कुल अधिप्राप्ति	21,59,087 मीट्रिक टन
मिलों को दिए गए	21,41,938 मीट्रिक टन
बर्बाद हो गए	17,149 मीट्रिक टन
बर्बाद हुए धान की क़ीमत	19.61 करोड़ रुपये
वर्ष 2012-13	
कुल अधिप्राप्ति	19,46,612 मीट्रिक टन
मिलों को दिए गए	18,87,823 मीट्रिक टन
बर्बाद हो गए	58,588 मीट्रिक टन
बर्बाद हुए धान की क़ीमत	89.35 करोड़ रुपये
वर्ष 2013-14	
कुल अधिप्राप्ति	14,04,837 मीट्रिक टन
मिलों को दिए गए	13,35,817 मीट्रिक टन
बर्बाद हो गए	69,020 मीट्रिक टन
बर्बाद हुए धान की क़ीमत	110.49 करोड़ रुपये

चावल का हिसाब-किताब

वर्ष 2011-12	
मिलने थे	2.14 करोड़ क्विंटल
मिले	1.88 करोड़ क्विंटल
नहीं मिले	25.58 लाख क्विंटल
नुक़सान	433.94 करोड़ रुपये
वर्ष 2012-13	
मिलने थे	13,04,436 मीट्रिक टन
मिले	8,33,123 मीट्रिक टन
नहीं मिले	4,71,313 मीट्रिक टन
नुक़सान	1058 करोड़ रुपये
वर्ष 2013-14	
मिलने थे	9,41,241 मीट्रिक टन
मिले	4,82,383 मीट्रिक टन
नहीं मिले	4,58,858 मीट्रिक टन
नुक़सान	1192 करोड़ रुपये

सीपीएम को सीताराम का सहारा

राजीव रंजन

सीताराम येचुरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नए महासचिव चुने गए हैं. पार्टी के इस सबसे अहम पद के लिए रामचंद्रन पिल्लई द्वारा अपना नाम वापस लेने के बाद येचुरी को यह मौक़ा मिला. वह पार्टी के पांचवें महासचिव हैं. महासचिव बनने के बाद येचुरी के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वह पार्टी को दोबारा उस मुकाम तक पहुंचा सकेंगे, जहां पार्टी के शिखर पुरुष रहे कॉमरेड ज्योति बसु और हरकिशन सिंह सुरजीत ने छोड़ा था? क्या येचुरी पार्टी का सिमटता जनाधार उसे दोबारा वापस दिला सकते हैं? यह इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि येचुरी के सामने ज़िम्मेदारियों और उम्मीदों का बड़ा पहाड़ खड़ा है. दूसरी तरफ़ वर्तमान में एकमात्र राज्य त्रिपुरा में ही माकपा शासित सरकार है. आइए देखते हैं कि सीताराम येचुरी के सामने कौन-कौन सी चुनौतियां हैं और वह उनका मुकाबला कैसे पार पाएंगे.

वर्ष 2008 में परमाणु करार को लेकर सरकार गिराने पर आमादा हो जाने वाली माकपा के उस क़दम ने जहां देश की बागडोर संभाल रहे मनमोहन सिंह और उनकी पार्टी कांग्रेस को हीरो साबित कर दिया था, वहीं स्वयं माकपा पर विकास विरोधी होने का ठप्पा लग गया था, जो आज तक नहीं हट सका. ऐसे में येचुरी को पार्टी की बिगड़ी छवि सुधारते हुए उसे विकास समर्थक होने की होड़ में शामिल करना होगा. दरअसल, बदलते समय के साथ पार्टी आत्म-मुग्धता का शिकार हो गई. यूपीए-एक के दौर में लगातार सरकार अस्थिर करने और धमकी देने की प्रवृत्ति ने दूसरे दलों में उसकी स्वीकार्यकता कम कर दी. सरल एवं सुलझे येचुरी के अन्य दलों के नेताओं से भी मधुर संबंध हैं. ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि वह दूसरे दलों के साथ सामंजस्य स्थापित करके पार्टी को दोबारा एक सशक्त भूमिका में ला सकेंगे.

प्रकाश करात के दौर में पार्टी की सबसे बड़ी कमजोरी यह रही कि वह युवा वर्ग को लुभाने में पूरी तरह असफल रही, जबकि पुराने नेताओं को एक-एक करके दरकिनार कर दिया गया. कभी माकपा के दिग्गज रहे सोमनाथ चटर्जी और सैफुद्दीन चौधरी आज पार्टी से बाहर हैं, तो पूर्व सांसद अनिल बसु को भी पार्टी ने बहिष्कृत कर रखा है. ऐसे में येचुरी को इन दोनों ही मोर्चों पर पार्टी को स्थापित करना होगा. जेएनयू के छात्रसंघ अध्यक्ष रहे सीताराम येचुरी को युवाओं पर फोकस करना होगा,

येचुरी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि वह पार्टी का देश भर में विस्तार करने पर ध्यान दें. ऐसे में, जबकि सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने राज्यों से निकल कर दूसरे राज्यों में दस्तक देने लगी हैं, तब माकपा का सिर्फ़ दो-तीन राज्यों में सिमटे रहना उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. येचुरी के पास खुद को साबित करने के लिए समय भी बहुत कम है, क्योंकि पार्टी को अगले साल ही उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरना होगा, जहां उसकी टक्कर उसी पार्टी से होने वाली है, जिसने गत विधानसभा चुनाव में तो उसे राज्य से बेदखल किया ही था, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी.

क्योंकि इस देश में युवाओं की संख्या काफी अधिक है. ऐसे में उन्हें नज़रअंदाज़ कर आगे नहीं बढ़ा जा सकता. कभी माकपा की पहचान उसके कैडर के लिए भी होती थी, लेकिन पश्चिम बंगाल में तृणमूल के हाथों पटखनी खाने के बाद पार्टी की हालत अब यह है कि उसका अपने सबसे बड़े गढ़ पश्चिम बंगाल में तो कैडर सिमट ही गया है, केरल और त्रिपुरा में भी उसे इस संकट से जूझना पड़ रहा है. पार्टी को किसी भी चुनाव में जीत चाहिए, तो उसे सबसे पहले कैडर को मजबूत करना होगा.

येचुरी के सामने एक बड़ी चुनौती यह भी होगी कि वह पार्टी का देश भर में विस्तार करने पर ध्यान दें. ऐसे में, जबकि सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने-अपने राज्यों से निकल कर दूसरे राज्यों में दस्तक देने लगी हैं, तब माकपा का सिर्फ़ दो-तीन राज्यों में सिमटे रहना उसके लिए आत्मघाती साबित हो सकता है. येचुरी के पास खुद को साबित करने के लिए समय भी बहुत कम है, क्योंकि पार्टी को अगले साल ही उनके नेतृत्व में पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में उतरना होगा, जहां उसकी टक्कर उसी पार्टी से होने वाली है, जिसने गत विधानसभा चुनाव में तो उसे राज्य से बेदखल किया ही था, लोकसभा चुनाव में भी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी. सीपीएम देश में धार्मिक सहिष्णुता एवं सांप्रदायिकता के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है. उसके सामने नव-उदारवाद के प्रतिकूल प्रभावों से जूझने के अलावा महिलाओं एवं दलितों के अधिकारों का मुद्दा भी है. सीपीएम को विकास के रास्ते खुद तय करने होंगे. किसी भी दल से समझौता करने की रणनीति त्याग कर उन दलों के साथ चलना सीपीएम के लिए ठीक होगा, जो खास मुद्दों पर खास समय तक उसके साथ सक्रिय रहे हों. सोशल मीडिया के बिना आज सब कुछ अधूरा है. इसलिए पार्टी को देश का मिजाज भांपते हुए सोशल मीडिया से जुड़ना होगा. जाहिर है, पार्टी जब तक लोगों के मन की बात नहीं समझेगी, तब तक उसका विस्तार संभव नहीं होगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

मीडिया के दोहरे मापदंड की ओर इशारा करते हुए प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा कि आतंकवाद केवल रायफल और बंदूक से ही अंजाम नहीं दिया जाता, बल्कि नकारात्मक सोच और किसी को मानसिक रूप से अपंग कर देना भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है. जैन मुनि जयंत कुमार ने कहा कि आतंकवाद हमेशा ग़रीबी की गोद में पलता है. अगर सरकार आतंकवाद का ख़ात्मा चाहती है, तो उसे ग़रीबी ख़त्म करने की दिशा में काम करना चाहिए. जैन मुनि ने कहा कि हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग ग़रीब हैं. अगर वाक़ई हम आतंकवाद ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें ग़रीबी ख़त्म करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए. केवल निर्दोषों को पकड़ कर और झूठे आरोप लगाकर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते.

डीएनडी

महाघोटाले का सेतु

दिल्ली और नोएडा की लाइफ लाइन कहे जाने वाले डीएनडी के टोल टैक्स की वसूली का किस्सा उस अंतहीन क़र्ज़ की तरह है, जो वर्षों बीत जाने के बाद भी ख़त्म नहीं होता. इस फ्लाई ओवर से रोज़ाना हज़ारों वाहन गुजरते हैं, जिनसे नोएडा टोल ब्रिज कंपनी को लाखों रुपये की आमदनी होती है. बावजूद इसके, कंपनी का रोना है कि उसकी लागत अभी पूरी नहीं हुई है, लिहाज़ा वह कई वर्षों तक आम जनता से टोल टैक्स वसूलेगी. जनता को उम्मीद थी कि निर्माण लागत पूरी होने के बाद इसे टोल मुक्त कर दिया जाएगा, लेकिन इसके उलट कंपनी और अधिक टैक्स बढ़ाने के मूड में है. हालांकि, आर्थिक गड़बड़ियों और मनमानी के ख़िलाफ़ स्थानीय जनता ने भी अब डीएनडी ब्रिज कंपनी के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है.

अभिषेक रंजन सिंह

दिल्ली से नोएडा को जोड़ने वाला डीएनडी फ्लाई ओवर अपने निर्माण के वक्त से ही विवादों में घिरा रहा है. शुरुआती दिनों में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कई संगठनों ने डीएनडी फ्लाई ओवर निर्माण का विरोध किया था, लेकिन सरकार जनहित और लोगों की सुविधाओं के नाम पर उन तमाम विरोधों को दबाने में कामयाब रही. फ़िलहाल इन दिनों टोल टैक्स की वसूली को लेकर डीएनडी के ख़िलाफ़ विरोध–प्रदर्शनों का दौर जारी है.

ग़ौरतलब है कि वर्ष 2001 में आईएल एंड एफएस ग्रुप की नोएडा टोल ब्रिज कंपनी ने डीएनडी के निर्माण का काम पूरा किया. इस परियोजना पर कुल 408 करोड़ रुपये की लागत आई. कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार, कंपनी को 30 वर्षों में 20 फ़ीसद मार्जिन के साथ लागत वसूलनी थी. वर्ष 2004 में एनटीबीसीएल की लागत और रिकवरी कॉस्ट बढ़कर 695 करोड़ रुपये हो गई और 2014 में तो कंपनी की रिकवरी कॉस्ट का आंकड़ा बढ़कर 3,458 करोड़ रुपये हो गया. अव्वल यह कि लागत 408 करोड़ रुपये और रिकवरी कॉस्ट 3,458 करोड़ रुपये हो गई. कंपनी के निदेशकों की मानें, तो डीएनडी की लागत वसूलने में कम से कम 70 साल और लग जाएंगे. हैरानी की बात यह है कि जिस हिसाब से कंपनी अपनी लागत की समीक्षा कर रही है, उस हिसाब से रिकवरी कॉस्ट वर्ष 2031 तक बढ़कर 85,759 करोड़ रुपये हो जाएगी. कंपनी के मसौदे पर योजना आयोग (अब नीति आयोग) ने अपनी सलाह देते हुए कहा कि कंपनी रकम और मार्जिन वसूलने का जो फॉर्मूला बता रही है, उससे लागत कभी वसूल ही नहीं हो पाएगी और लोगों को हमेशा टोल टैक्स देते रहना पड़ेगा.

दरअसल, कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनका जवाब नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के अधिकारियों के पास नहीं है. कंपनी हमेशा अपने ख़र्चों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करती है, जबकि सच्चाई यह है कि डीएनडी फ्लाई ओवर को शुरुआती दिनों से ही फ़ायदा हो रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि डीएनडी पर टोल लागत से ज़्यादा धनराशि वसूली जा चुकी है.

दरअसल, कई ऐसे महत्वपूर्ण सवाल हैं, जिनका जवाब नोएडा टोल ब्रिज कंपनी के अधिकारियों के पास नहीं है. कंपनी हमेशा अपने ख़र्चों को बढ़ा–चढ़ाकर पेश करती है, जबकि सच्चाई यह है कि डीएनडी फ्लाई ओवर को शुरुआती दिनों से ही फ़ायदा हो रहा है. इसमें कोई शक नहीं कि डीएनडी पर टोल लागत से ज़्यादा धनराशि वसूली जा चुकी है. बावजूद इसके, कंपनी लोगों की जेब पर डाका डालने से बाज नहीं आ रही है. पिछले दिनों डीएनडी टोल वसूली बंद करने की मांग को लेकर जनहित मोर्चा, क्राइम फ्री इंडिया फोर्स, रोटरी क्लब एवं एक्टिव सिटीजन जैसे कई संगठनों ने इस लूट के ख़िलाफ़ जनता को जागरूक किया. इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता नवाब सिंह नागर ने कहा कि डीएनडी टोल वसूली के ख़िलाफ़ जनता बेहद आक्रोशित है. उनके मुताबिक़, जब तक डीएनडी को टोल मुक्त नहीं किया जाता, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

महा–लूट में नौकरशाहों की मिलीभगत

डीएनडी टोल ब्रिज के निर्माण एवं टोल वसूली को अरबों रुपये की लूट का मामला बताते हुए मौलिक भारत नामक एक संगठन ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई वरिष्ठ अधिकारियों पर इसमें शामिल होने का आरोप लगाया है. संगठन का दावा है कि डीएनडी टोल ब्रिज का घोटाला आईएएस अधिकारियों की मिलीभगत से ही मुमकिन हो पाया. मौलिक भारत संगठन की मानें, तो नोएडा टोल ब्रिज का निर्माण वर्ष 2001 में हुआ था. उस समय इसकी कुल लागत 408 करोड़ रुपये बताई गई थी, जबकि वास्तविक लागत 100 से 125 करोड़ रुपये के आस–पास थी. उल्लेखनीय है कि एनटीबीसीएल 31 मार्च, 2014 तक 690 करोड़ रुपये वसूल चुकी है. वहीं नोएडा अथॉरिटी पर इसका बकाया 2,950 करोड़ रुपये है, जो वर्ष 1932 तक 53,352 करोड़ रुपये हो जाएगा. टोल कंपनी ने सरकार की आंखों में धूल झोंककर लागत की वसूली तक टोल टैक्स वसूलने के अधिकार में एक नियम यह डाला कि यदि निर्माण लागत का 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष बतौर लाभांश नहीं मिला, तो कंपनी इस राशि को निर्माण लागत में जोड़ती जाएगी. इस प्रावधान के तहत नोएडा अथॉरिटी को इस समय कंपनी को 2,950 करोड़ रुपये देने हैं और अथॉरिटी ने लिखित तौर पर उच्च न्यायालय को बताया है कि 2032 तक यह राशि 53,352 करोड़ रुपये हो जाएगी. मौलिक भारत संगठन का आरोप है कि निर्माण लागत कई गुना ज़्यादा बताई गई और वसूली कई गुना छिपाई गई. यहां तक कि टोल ब्रिज से रोज़ाना गुजरने वाले वाहनों की संख्या में भी हेर–फेर की गई. आख़िर यह कौन सी व्यवस्था है, जिसके तहत डीएनडी फ्लाई ओवर पर सदैव टोल वसूला जाता रहेगा. मौलिक भारत ने सूबे के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से अनुरोध किया कि एनटीबीसीएल एवं आईएल एंड एफएस के साथ हुए करार को रद्द करते हुए डीएनडी टोल ब्रिज को टोल मुक्त किया जाए. इसके अलावा, इस घोटाले के ज़िम्मेदार लोगों के ख़िलाफ़ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए. ■

इन नौकरशाहों पर लगे आरोप

गोपी अरोड़ा – तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के निजी सचिव एवं केंद्रीय वित्त सचिव रहे 1957 बैच के इस अधिकारी ने एनटीबीसीएल को फ़ायदा पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाई और सेवानिवृत्ति के बाद यह इसके पहले अध्यक्ष बने.

प्रदीप पुरी–1978 बैच एवं उत्तर प्रदेश कैडर के अधिकारी प्रदीप एनटीबीसीएल के बनते ही सरकारी सेवा से इस्तीफ़ा देकर इसके सीईओ बन गए.

आरके भार्गव–उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भार्गव वर्ष 1997 से एनटीबीसीएल के चेयरमैन हैं.

पीयूष मनकड़–1964 बैच के अधिकारी एवं पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव मनकड़ एनटीबीसीएल के निदेशक हैं.

सनत कौल–1971 बैच के अधिकारी सनत ने समझौते में दिल्ली सरकार की तरफ़ से हस्ताक्षर किए. फिलहाल यह एनटीबीसीएल के निदेशक हैं.

रवि माथुर–1970 बैच के अधिकारी रवि समझौते के समय नोएडा प्राधिकरण के सीईओ थे.

प्रभात कुमार–पूर्व कैबिनेट सचिव प्रभात ने रवि माथुर को अनेक स्तरों और अवसरों पर फ़ायदा पहुंचाया.

आतंकवाद के लिए ग़रीबी ज़िम्मेदार

चौथी दुनिया ब्यूरो

आतंकवाद से भारत समेत दुनिया के कई देश जूझ रहे हैं. विकास और खुशहाली के लिए आतंकवाद का ख़ात्मा बहुत ज़रूरी है. देश के बुद्धिजीवी एवं विभिन्न धर्मों के धर्मगुरु आतंकवाद को लेकर खासे चिंतित हैं. पिछले दिनों राजधानी दिल्ली के कांस्टीट्यूशन क्लब स्थित मावलंकर ऑडिटोरियम में लिमरा फाउंडेशन के तत्वावधान में एक कांफ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बुद्धिजीवियों, धर्मगुरुओं एवं समाज के अन्य वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया और अपने विचार व्यक्त किए. अधिकांश वक्ताओं का मानना था कि जैसे ही कहीं कोई आतंकी वारदात होती है, तो शक की सूई सबसे पहले मुसलमानों की ओर जाती है और मुस्लिम नौजवानों को पकड़ कर जेल में डाल दिया जाता है, उन पर झूठे आरोप लगाए जाते हैं और फिर कई साल बाद अदालत उन्हें निर्दोष बताकर रिहा कर देती है. और तो और, मीडिया भी ऐसे लोगों का साथ नहीं देता.

कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए जस्टिस राजेंद्र सच्चर ने कहा कि कोई भी देश तब तक सभ्य नहीं माना जा सकता, जब तक वहां के अल्पसंख्यक खुद को पूरी तरह सुरक्षित न समझते हों. इस सिलसिले में दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, की भूमिका भी संदिग्ध नज़र आती है. आम तौर पर जब भी किसी आतंकवादी घटना को लेकर कोई मुस्लिम नौजवान पकड़ा जाता है, तो जांच पूरी भी नहीं हो पाती कि मीडिया उसे आतंकवादी घोषित करके ब्रेकिंग न्यूज बना देता है. लेकिन, वही नौजवान जब सालों बाद निर्दोष साबित होकर जेल से रिहा होता है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं होती. जस्टिस सच्चर ने कहा कि हिंदू और मुसलमान दो आंखों की तरह हैं, एक के दर्द को दूसरी आंख महसूस करती है, लेकिन कुछ लोग भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, जो संवैधानिक रूप से बिल्कुल ग़लत है.

जुबैर खां अलीग नामक युवक, जिसे 17 जुलाई, 2012 को दिल्ली के शाहीन बाग (ओखला) से गिरफ्तार किया गया था और जिसे ढाई साल तक तिहाड़ जेल में रहने के बाद जमानत मिली, उसने कांफ्रेंस में अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि जेल में रहते हुए मीडिया ने उसके बारे में ऐसी–ऐसी बातें कहीं, जिनसे उसका दूर–दूर तक कोई लेना–देना नहीं था. वह जब रिहा होकर अपने घर आया, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी रोज़ी–रोटी की. जुबैर ने बताया कि उसने कई कंपनियों में आवेदन किया, जहां उसकी योग्यता को सराहा भी गया, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि वह आतंकवाद के आरोप में जेल जा चुका है, तो उसे नौकरी देने से मना कर दिया गया. उसे आज भी ऐसी दिक्कतों से दो–चार होना पड़ता है.

यह कांफ्रेंस इस लिहाज से बहुत खास थी कि विभिन्न राजनीतिक एवं धार्मिक चिंतक एक मंच पर एकत्र थे. इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन एवं पंडित देव आनंद, जैन मुनि जयंत कुमार और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने विचार रखे. राजनीतिक दलों में भाजपा का नेतृत्व जनरल वीके सिंह ने किया, वहीं कांग्रेस की ओर से राशिद अल्वी एवं अल्लू मियां मौजूद थे.

मीडिया के दोहरे मापदंड की ओर इशारा करते हुए प्रख्यात पत्रकार कुलदीप नैयर ने कहा कि आतंकवाद केवल रायफल और बंदूक से ही अंजाम नहीं दिया जाता, बल्कि नकारात्मक सोच और किसी को मानसिक रूप से अपंग कर देना भी आतंकवाद की श्रेणी में आता है. जैन मुनि जयंत कुमार ने कहा कि आतंकवाद हमेशा ग़रीबी की गोद में पलता है. अगर सरकार आतंकवाद का ख़ात्मा चाहती है, तो उसे ग़रीबी ख़त्म करने की दिशा में काम करना चाहिए. जैन मुनि ने कहा कि हमारे देश के 70 प्रतिशत लोग ग़रीब हैं. अगर वाक़ई हम आतंकवाद ख़त्म करना चाहते हैं, तो हमें ग़रीबी ख़त्म करने की संभावनाएं तलाशनी चाहिए. केवल निर्दोषों को पकड़ कर और झूठे आरोप लगाकर हम इससे छुटकारा नहीं पा सकते. केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि इस देश में हिंदू और मुसलमान बहुत प्यार–मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने दोनों के बीच ऐसा नफ़रत का बीज बोया कि हम एक–दूसरे को शक की निगाह से देखने लगे. इस्लाम हो या कोई और धर्म, वह आतंकवाद से दूर रहने की सीख देता है. उन्होंने कहा, मैंने कुरान का अनुवाद पढ़ा है. कुरान में मुझे कहीं भी आतंकवाद की कोई बात नहीं मिली. मैंने अपने सैन्य जीवन में रोजे भी रखे हैं, क्योंकि मैं हर धर्म को सम्मान की निगाह से देखता हूं.

यह कांफ्रेंस इस लिहाज से बहुत खास थी कि विभिन्न राजनीतिक एवं धार्मिक चिंतक एक मंच पर एकत्र थे. इसमें आचार्य प्रमोद कृष्णन एवं पंडित देव आनंद, जैन मुनि जयंत कुमार और कई मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपने विचार रखे. राजनीतिक दलों में भाजपा का नेतृत्व जनरल वीके सिंह ने किया, वहीं कांग्रेस की ओर से राशिद अल्वी एवं अल्लू मियां मौजूद थे. कुल मिलाकर यह एक अच्छा आयोजन था, लेकिन एक कमी बहुत अखरी. वह यह कि जिस तरह बुद्धिजीवियों, विभिन्न धर्मगुरुओं एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को एक मंच पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया गया, उसी तरह यदि इसमें मुसलमानों के विभिन्न वर्गों के विद्वानों–प्रतिनिधियों को भी शामिल कर लिया जाता, तो कांफ्रेंस कहीं ज़्यादा सफल साबित होती. ऐसे आयोजन निश्चित तौर पर मुसलमानों की वास्तविक छवि लोगों के सामने लाने में सहायक साबित हो सकते हैं और जो लोग इस्लाम या मुसलमानों के प्रति नकारात्मक सोच रखते हैं, उन्हें सही स्थिति समझने में मदद कर सकते हैं. इसके साथ ही मुस्लिम संगठनों को चाहिए कि जिस तरह निर्दोष मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार के ख़िलाफ़ कांफ्रेंस आयोजित करके आवाज़ उठाई जाती है, उसी तरह उन मुसलमानों के ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं. ग़ौरतलब है कि बीते दिनों अलगाववादी नेता मसर्रत आलम ने कश्मीर में एक जलसा किया और उसमें पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए. निश्चित तौर पर यह एक निंदनीय कार्य है और इससे देश के मुसलमान आहत हुए हैं. लिहाज़ा, कांफ्रेंस और सम्मेलन जैसे आयोजन करके हर तरफ़ यह संदेश देने की ज़रूरत है कि भारतीय मुसलमान जिस तरह आतंकवाद से नफरत करते हैं, उसी तरह देश विरोधी गतिविधियों से भी नफरत करते हैं. ■

feedback@chauthiduniya.com

राज्यपाल राम नाइक की बातों के निहितार्थ समझे जा सकते हैं. केंद्र सरकार सांसद निधि पर होने वाले खर्च पर नज़र रखने पर जोर दे रही है. पिछले कई वर्षों से सांसद निधि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2010–11 की अपनी रिपोर्ट में इसके क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा किया था. 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन में कहा था कि यह योजना तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए.

सांसद-विधायक निधि

औचित्य पर फिर उठे सवाल

दीनबंधु कबीर

बिहार में सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक निधि का प्रावधान समाप्त कर दिया था. केंद्र में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद निधि पर अंकुश लगाने की प्रक्रिया तेज कर दी है. विधायक एवं सांसद निधि के बेजा इस्तेमाल और भ्रष्टाचार के मामले विधानसभाओं से लेकर संसद तक उठते रहे हैं, साथ ही निधि की व्यवस्था समाप्त करने की बात भी उठती रही है, वहीं निधि की राजनीति भी उतनी ही गति से चलती रही है. उसी राजनीति का नतीजा है कि यूपीए सरकार ने सांसद निधि की राशि अप्रत्याशित रूप से बढ़ाकर ढाई गुनी कर दी थी. एक बार फिर सांसद निधि चर्चा में है और भाजपा शासित राज्यों के राज्यपालों से इस पर भूमिका बांधने के लिए कहा गया है. भाजपा के विचार-प्रचारकों को भी इस काम में लगाया गया है, ताकि विधायक निधि एवं सांसद निधि को लेकर एक व्यापक जनमत तैयार हो सके, जिसे आधार बनाकर सरकार को कोई फ़ैसला लेने में सुविधा हो. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने पिछले दिनों लखनऊ में कहा कि विकास के लिए शुरू की गई सांसद निधि का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है और अधिकांशत: दुरुपयोग होता है. हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि सांसद निधि बंद कर दी जाए, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, तभी गांव स्तर तक विकास कार्य हो सकते हैं. नाइक ने कहा कि उन्हीं की पहल पर 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हाराव ने सांसद निधि की शुरुआत की थी.

राज्यपाल राम नाइक की बातों के निहितार्थ समझे जा सकते हैं. केंद्र सरकार सांसद निधि पर होने वाले खर्च पर नज़र रखने पर जोर दे रही है. पिछले कई वर्षों से सांसद निधि में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आती रही हैं. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) ने 2010-11 की अपनी रिपोर्ट में इसके क्रियान्वयन में व्याप्त भ्रष्टाचार का खुलासा किया था. 2008 में तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने सदन में कहा था कि यह योजना तुरंत बंद कर दी जानी चाहिए. 2009 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने कहा था कि सांसद निधि और विधायक निधि में जिस पैमाने पर भ्रष्टाचार हो रहा है और जिस तरह जनता की गाढ़ी कमाई राजनेताओं द्वारा डकारी जा रही है, उसे देखते हुए इन निधियों की व्यवस्था तत्काल बंद कर देनी चाहिए, लेकिन इस दिशा में केंद्र सरकार या राज्य सरकारों (बिहार सरकार छोड़कर) की तरफ़ से कोई पहल नहीं हुई. ग़ौरतलब है कि सांसद निधि की शुरुआत 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हाराव ने की थी. उन्होंने हर सांसद को प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये बतौर सांसद निधि देने का प्रावधान किया था. कहा गया था कि सांसद की सिफारिश पर उसके निर्वाचन क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रत्येक वर्ष एक करोड़ रुपये खर्च किए जा सकेंगे. धीरे-धीरे यह रकम एक करोड़ रुपये से बढ़कर पांच करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो गई.

क्षेत्रीय विकास के लिए सांसद निधि में 150 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ही इस व्यवस्था के औचित्य पर बहस शुरू हुई. इससे पहले बिहार में विधायक निधि बंद करने के राज्य सरकार के फ़ैसले के बाद कमोबेश ऐसे ही सवाल उठने शुरू हुए. तमाम विरोधों के बीच बिहार सरकार का यह फ़ैसला तब आया था, जब पूरा देश भ्रष्टाचार की आग से झुलस रहा था. सांसदों को जनलोकपाल के दायरे में लाने की मांग को लेकर संसद के अंदर बवाल चल रहा था. 90 से ज़्यादा सांसदों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के मामले लंबित रहे हैं. तक़रीबन 180 सांसद तो ऐसे रहे हैं, जो किसी न किसी रूप में आपराधिक चरित्र रखते हैं. वैसे भी यह आम धारणा बन चुकी है कि सांसद निधि भ्रष्टाचार का पोषण करती है. आंध्र प्रदेश के छह ज़िलों के लिए इस मद में आवंटित 64 करोड़ रुपये की बैंक में एफडी कराकर उसकी ब्याजखोरी का मामला किसी से छिपा नहीं है. कुछ अर्सा पहले एक स्टिंग के ज़रिये कुछ सांसदों को ठेके के लिए कमीशनबाजी करते रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है. ज़मीनी स्तर पर विकास के लिए आवंटित यह रकम आम तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए खर्च की जाती है या फिर राजनेताओं की जेब के हवाले हो जाती है.

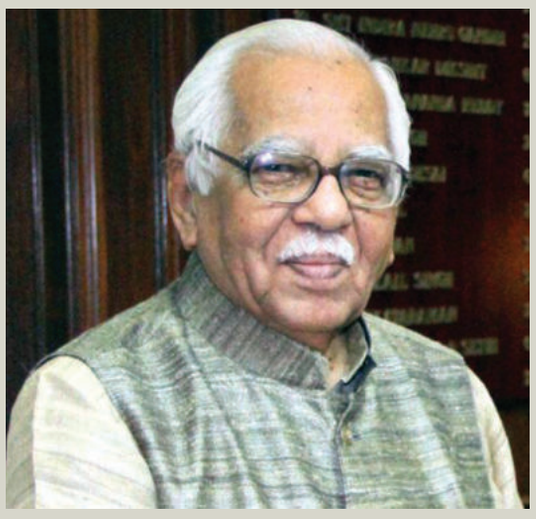

कई सांसदों ने अब तक नहीं किया निधि का इस्तेमाल

16वीं लोकसभा के गठन हुए दस महीने बीत चुके हैं, लेकिन कई सांसदों ने अभी तक अपनी निधि का इस्तेमाल नहीं किया है. स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी के कई सांसद भी इस निधि का इस्तेमाल न कर पाने वालों में शामिल हैं. राजग के सहयोगी दलों एवं विपक्षी पार्टियों के ज़्यादातर सांसदों ने अभी तक अपनी सांसद निधि से एक रुपया भी खर्च नहीं किया. आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 36 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में से केवल 10 राज्यों के सांसदों ने अपनी सांसद निधि का इस्तेमाल शुरू किया है.

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) सांसद निधि के इस्तेमाल में ठेका प्रथा और कमीशनखोरी पर अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. कैग की रिपोर्ट बताती है कि 11 राज्यों में सांसद निधि से प्रधानमंत्री-मुख्यमंत्री राहत कोष को सात करोड़ 37 लाख रुपये किस तरह नियम विरुद्ध दिए गए. 14 राज्यों में सांसदों ने एयरकंडीशनर, फर्नीचर खरीदने के अलावा ट्रस्ट के अस्पतालों एवं स्कूलों को किस तरह छह करोड़ रुपये दे दिए. छह राज्यों में सांसद निधि से सात करोड़ रुपये खर्च करके नामवर लोगों के नाम पर निर्माण कार्य कराए गए.

सांसद निधि के बेजा इस्तेमाल में महाराष्ट्र सबसे आगे रहा. तमिलनाडु दूसरे और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर हैं. इसके बाद क्रमश: असम, सिक्किम, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, नगालैंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल, उत्तराखंड एवं राजस्थान का नंबर आता है. सरकारी दावों के विपरीत कैग की राय में योजना लागू होने के डेढ़ दशक बाद भी इस मद के 1053.63 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए. आम तौर पर चुनावी वर्ष में यह निधि दिल खोलकर खर्च की जाती है. जाहिर है, इस निधि का इस्तेमाल राजनीतिक प्रयोजन के लिए किया जा रहा है. प्रशासनिक आयोग ने भी सांसद निधि समाप्त करने की सिफारिश कर रखी है. आयोग का तर्क है कि सांसदों का काम प्रशासनिक खर्च पर नज़र रखना है, न कि स्थानीय निकायों के काम हथिया लेना.

नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ कांस्टीट्यूशन और वर्ष 2005 में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय सलाहकार समिति के सांसद निधि के पक्ष में न होने के बावजूद केंद्र सरकार ने सांसदों की सालाना निधि दो करोड़ से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये कर दी. यूपीए सरकार ने यह काम राजनीतिक लाभ देखते हुए सांसदों को उपकृत करने के इरादे से किया था, क्योंकि उसके अन्य मंत्री भी घपलों-घोटालों में लगे हुए थे. यह सवाल कई बार उठा कि सांसद निधि का आख़िर औचित्य क्या है? क्या वाकई इससे विकास का सरकारी संकल्प पूरा होता है? लेकिन, इन सवालों का कोई जवाब आम नागरिकों को नहीं मिल सका. लोकसभा के प्रत्येक सांसद को अपने कार्यकाल में क्षेत्रीय विकास कार्यों पर 25 करोड़ रुपये खर्च करने का अधिकार है. ज़िलाधिकारी सांसदों की सिफारिशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन उन्हीं ज़िलाधिकारियों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है. संसद सदस्यों की तरह राज्यों में विधायकों ने भी विधायक निधि की मांग की और प्राय: हर राज्य में उन्हें उतनी ही रकम दी गई, जितनी किसी सांसद को मिलती है. इस रकम में भी जमकर बंदरबांट होती है. लेकिन, किसी भी सरकार ने कभी यह कोशिश नहीं की कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर मामले की गहराई और निष्पक्षता से जांच हो. सांसद निधि और विधायक निधि पर कितना खर्च हुआ और कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित हुईं, यह पता लगाने या जांच करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती.

पूरे भारत में, खासकर गांवों में शौचालयों का घोर अभाव है, लेकिन सांसद निधि से शौचालय बनाए जाने का कोई प्रयास नहीं होता. यदि गांव में सांसद निधि से शौचालय या सामुदायिक केंद्र बन भी जाता है, तो वह सांसद एवं उनके गुर्गों के कब्जे में रहता है. महिलाएं पूर्ववत असुविधा का सामना करती रहती हैं. ग्रामीण इलाकों में यदि कोई शख्स गंभीर रूप से बीमार हो जाता है, तो उसे शहर के अस्पताल में ले जाने के लिए कोई साधन नहीं मिल पाता. इस दिशा में कोई सांसद अपनी निधि से कभी कुछ नहीं करता. बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के बहुत-से मरीज दिल्ली में एम्स और सफदरजंग अस्पताल के सामने सड़क पर रहने के लिए मजबूर हैं. यदि इन राज्यों के सांसद अपनी-अपनी निधि से थोड़ी रक़म खर्च करके दिल्ली या कहीं आसपास धर्मशालाएं बनवा दें, तो मरीजों एवं उनके तीमारदारों को बहुत सुविधा होगी. लेकिन, सांसद निधि खर्च करने की व्यवस्था अपने पुराने ढर्रे पर कायम है. हां, घोटाले दर घोटाले की ख़बरों का आना जारी है.

अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के साथ ही सांसद निधि पर भी नज़र रखने की कोशिश कर रहे हैं. सांसद निधि के खर्च में भ्रष्टाचार और धांधली की शिकायतों के मद्देनज़र मोदी सरकार इसके तहत होने वाले विकास कार्यों की थर्ड पार्टी निगरानी की व्यवस्था कर रही है. खासकर 25 लाख रुपये से अधिक के विकास कार्यों पर पैनी नज़र रखी जा रही है. आज 21 साल पहले शुरू हुई सांसद निधि व्यवस्था जितनी लोकप्रिय हुई, उससे कहीं अधिक बदनाम हुई. इसके तहत काम कम हुआ और लूट ज़्यादा. ऐसे सांसदों की संख्या बहुत कम रही, जिन्होंने इस निधि की शत-प्रतिशत धनराशि सही तरीके से विकास कार्यों में इस्तेमाल की. केंद्र सरकार ने सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्वतंत्र संस्थाओं, शैक्षिक संस्थानों और कंसल्टेंट्स के ज़रिये देश के 100 ज़िलों में निगरानी कराने का फ़ैसला किया है. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को उन संस्थाओं की पहचान करने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जो सांसद निधि के इस्तेमाल की ज़मीनी स्तर पर थर्ड पार्टी निगरानी कर सकें. उक्त संस्थाएं ज़िला मुख्यालय, शहरों, कस्बों एवं गांवों में जाकर यह पड़ताल करेंगी कि सांसद निधि के तहत हुए किसी विकास कार्य के लिए कितना पैसा मंजूर हुआ और उस पर कितना खर्च हुआ. कार्य की गुणवत्ता परखने का काम भी यही संस्थाएं करेंगी और नियमित तौर पर अपनी रिपोर्ट केंद्र को भेजेंगी. संस्थाओं की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार राज्य सरकारों से सवाल-जवाब करेगी. विकास कार्यों के साथ ही सांसद निधि के तहत सोसायटी, ट्रस्ट या एनजीओ के लिए किए जाने वाले कार्यों की निगरानी भी होगी. पेयजल, सिंचाई, सड़क, पुल, खेल परिसर आदि सुविधाओं पर हुए खर्च की पाई-पाई का हिसाब रखा जाएगा.

दरअसल, केंद्र सरकार अगले पांच वर्षों में सांसद निधि पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपये से अधिक खर्च करने जा रही है. लिहाजा, धांधलियों और घोटालों को देखते हुए थर्ड पार्टी निगरानी तंत्र की ज़रूरत महसूस की गई. धनराशि केंद्र देता है और सांसद की सिफारिश पर ज़िला प्रशासन उसे खर्च करता है, लेकिन राज्य सरकार एवं ज़िला प्रशासन द्वारा इसकी निगरानी नहीं की जाती. सांसद निधि के तहत प्रत्येक सांसद अपने क्षेत्र में हर साल पांच करोड़ रुपये के विकास कार्यों की सिफारिश कर सकता है. केंद्र सरकार राज्य सरकारों की समीक्षा बैठक बुलाकर सांसद निधि के इस्तेमाल का जायजा लेती है और कभी-कभी ज़मीनी स्तर पर जांच के लिए दल भी भेजती है, लेकिन इतने बड़े स्तर पर निगरानी की व्यवस्था पहली बार की जा रही है.■

feedback@chauthiduniya.com

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश

सियासत जारी है

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

किसान की ज़मीन पर देश के राजनीतिक दल वोटों की फसल उगाने की पुरजोर कोशिश में जुटे हुए हैं. राजधानी दिल्ली में संसद से सड़क तक, रामलीला मैदान से जंतर-मंतर तक भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ नित नए राजनीतिक रंग दिखाई पड़ रहे हैं. सबके पास स्क्रिप्ट एक ही है, हर दिन केवल किरदार बदल रहे हैं.

नवीन चौहान

राजनीतिक दल हों या ग़ैर-राजनीतिक, हर कोई केंद्र सरकार पर वर्ष 2013 के भूमि अधिग्रहण क़ानून में किए गए बदलाव वापस लेने का दबाव बनाने की कोशिश में है. ऐसी ही एक कोशिश रामलीला मैदान में कांग्रेस और जंतर-मंतर में आम आदमी पार्टी ने भी की. कांग्रेस की रैली गुटबाजी की भेंट चढ़ गई, तो आम आदमी पार्टी की रैली को किसान गजेंद्र सिंह की मौत ने कलंकित कर दिया. 19 अप्रैल को हुई कांग्रेस की रैली को किसान-खेत मज़दूर रैली नाम दिया गया था, लेकिन यह रैली पूरी तरह कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के अज्ञातवास के बाद राजनीतिक वापसी पर केंद्रित थी. रैली से दो दिन पहले राहुल गांधी देश वापस आए. अगले दिन उन्होंने किसानों से मुलाकात की और 19 अप्रैल को रामलीला मैदान से मोदी सरकार को वर्ष 2013 के क़ानून में बदलाव न करने देने की चुनौती दे डाली. तक़रीबन दो महीने लंबी छुट्टी के बाद लौटे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने देश भर से आए किसानों को संबोधित करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि वह उनकी लड़ाई लड़ेंगे.

राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए उद्योगपतियों से कर्ज लिया था, जिसे अब वह किसानों की ज़मीन छीनकर चुकाना चाहते हैं और इसके लिए वर्ष 2013 में बना भूमि अधिग्रहण क़ानून बदलना चाहते हैं. राहुल ने कहा कि मोदी ने उद्योगपतियों को बताया था कि गुजरात मॉडल के आधार पर पूरे देश के किसानों की ज़मीन छीनी जा सकती है. अब मोदी गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू करके देश की नींव यानी किसान और खेती को कमजोर करना चाहते हैं. ऊपर से चमकाना और नींव कमजोर करना उनकी गवर्नेंस का मूल सार है. राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया योजना पर निशाना साधते हुए कहा कि यदि देश को मेक इन इंडिया की ज़रूरत है, तो किसानों की भी ज़रूरत है. किसानों के बच्चों के लिए शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य की भी ज़रूरत है. लेकिन, इसके लिए पांच साल तक

इस्तेमाल न होने वाली ज़मीन को किसानों को वापस किए जाने वाले प्रावधान को बदलने की क्या ज़रूरत थी? मोदी जी लैंड बैंक बनाकर किसानों की ज़मीन वापस नहीं करना चाहते हैं, वह किसानों को मज़दूर बनाना चाहते हैं. देश में जहां कहीं भी ज़मीन की लड़ाई होगी, कांग्रेस पार्टी आपको वहां दिखाई देगी. कांग्रेस किसानों के हक़ की लड़ाई लड़ती रहेगी.

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार किसानों के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रच रही है. रैली में बड़ी संख्या में आए किसानों को देखकर हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है. हम किसानों की तकलीफों को इतनी बेदर्दी से नज़रअंदाज़ नहीं होने देंगे. देश की जनता सरकार के खोखले वादों को समझ चुकी है. सबका साथ-सबका विकास का नारा लगाने वालों को किसानों की सहमति और साथ की ज़रूरत नहीं है. कहां हैं वे लोग, जो कह रहे थे कि अब किसानों को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें साहूकारों के पास नहीं जाना पड़ेगा. मोदी सरकार का रवैया मज़दूरों, किसानों के ख़िलाफ़ है. हम सबके हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करेंगे. किसानों की आवाज़ न दबी है और न दबेगी. इस किसान रैली का आयोजन भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ किसानों की आवाज़ केंद्र सरकार तक पहुंचाने के लिए किया गया था, लेकिन किसानों के हितों की लड़ाई गुटबाज़ी में फंसती दिखी. मोदी सरकार को ताकत दिखाने की जगह कांग्रेसी नेताओं के बीच पार्टी आलाकमान के सामने खुद को एक-दूसरे से ज़्यादा ताकतवर दिखाने की होड़ मची थी.

हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर के बीच की रस्साकशी रैली में उनके समर्थकों के व्यवहार से जगजाहिर हो गई. रैली में बड़ी संख्या में गुलाबी पगड़ी पहन कर हरियाणा से आए हुड्डा समर्थकों ने अशोक तंवर के भाषण का विरोध करना शुरू कर दिया. ऐसे में हरियाणा में किसानों का आंदोलन कैसे परवान चढ़ेगा, यह खुद-ब-खुद समझ में आ जाता है. इस तरह की गुटबाजी के उभर कर सामने आने से एक बात तो जाहिर हो जाती है कि राज्यों में कांग्रेस की ओर से भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ ज़मीनी तौर पर कुछ नहीं होने जा रहा. भूमि अधिग्रहण के बहाने कांग्रेस अपनी सियासी ज़मीन तैयार करने में जुटी है. उसे बिहार और उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की चिंता है, लेकिन मंच से पार्टी ने किसी योजनाबद्ध कार्यक्रम की घोषणा नहीं की, जिससे राज्य स्तर पर वह एक बार फिर खड़ी हो पाती. भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ कब, क्या और कैसे करना है, इसकी घोषणा न होने से कार्यकर्ता निराश हैं.

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से रैली में आईं तारा पांगती ने कहा कि यदि मंच से राज्यों में होने वाले कार्यक्रमों की घोषणा की जाती, तो किसानों एवं कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा संदेश जाता. किसानों की माली हालत पहले ही ठीक नहीं है, ऐसे में वे विरोध प्रदर्शन करने दिल्ली नहीं आ सकते. स्थानीय स्तर पर पूरे देश में एक साथ विरोध प्रदर्शन होने से ही सरकार पर दबाव बन सकेगा और किसानों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सकेगी. रैली में शामिल होने आए अधिकांश लोगों का कहना था कि भूमि अधिग्रहण आंदोलन की कमान सोनिया गांधी को अपने हाथों में रखनी चाहिए, इससे विरोध-प्रदर्शन को ताकत मिलेगी. पंजाब के पटियाला से आए प्रवीण कुमार ने कहा कि राहुल गांधी के इतने लंबे समय तक देश से बाहर रहने का असर पड़ेगा. यदि अब राहुल किसानों के पास जाएंगे, तो सवाल उठेगा कि वह उनकी परेशानी के समय कहां थे? ऐसे में, कमान सोनिया गांधी को ही संभालनी चाहिए, ताकि पार्टी और उसके रुख की विश्वसनीयता बनी रहे. राजस्थान के दौसा से आए किसान कैलाश चंद्र मीणा ने कहा, हमें मोदी का रोज़गार नहीं, हमारी ज़मीन ही चाहिए. ज़मीन हमारी मां है, हम उसके सहारे अपना जीवन गुजार लेंगे. राजस्थान के ही अलवर ज़िले के गांव बानसूर से आए महेश चंद्र सैनी ने कहा कि यदि राहुल गांधी और कांग्रेस को सदबुद्धि आई होगी, तो वह देश भर में घूमेंगे और किसानों से मिलेंगे.

अलवर की अंजू यादव ने कहा कि हम सरकार को अपनी ज़मीन नहीं लेने देंगे. सरकार पहले नौकरी दे, फिर ज़मीन ले. यदि सरकार ऐसा नहीं करेगी, तो ज़मीन हमारी है, हम नहीं देंगे. राजस्थान के कटीघाटी-भगोड़ा से आईं रीता देवी ने कहा कि हमने कांग्रेस को दस साल सहयोग किया, उसने हमारे लिए कुछ नहीं किया और इस बार मोदी को वोट दिया, वह भी वादा करके पलट गया. सरकार केवल अमीरों की सुन रही है, उसे किसानों की फिक्र नहीं है. सरकार को किसानों की ज़मीन उनसे पूछे बगैर नहीं लेनी चाहिए. सरकार सिंचाई वाली ज़मीन ले रही है, ऐसे में किसान कहां जाएगा? अधिकांश किसान कांग्रेस की रैली में शामिल होने इस आशा से आए थे कि उन्हें बेमौसम बारिश से हुए नुक़सान का मुआवजा जल्दी मिल जाएगा. अधिकतर किसान भूमि अधिग्रहण का सवाल पूछने पर जवाब नहीं दे पाए. जो बोले भी, तो वे घूम-फिरकर मुआवजे पर लौट आए. रैली को लेकर किसानों में कोई विशेष उत्साह नज़र नहीं आया. यही वजह थी कि राहुल और सोनिया के भाषण के दौरान ही किसानों ने रामलीला मैदान छोड़ना शुरू कर दिया था.

वहीं जंतर-मंतर में भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का विरोध करने उतरी आम आदमी पार्टी की रैली राजस्थान के दौसा से आए किसान गजेंद्र सिंह द्वारा आत्महत्या करने के बाद तमाशा बन गई. खेत-किसान का रखे ख्याल, हमारा नेता केजरीवाल जैसे नारों के साथ शुरू हुई इस रैली में पूरी दिल्ली सरकार मौजूद थी, लेकिन गजेंद्र की मौत ने रैली का नज़ारा बदल दिया. किसानों के भले के लिए अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने की बात कही. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे आग्रह करेगी कि यदि अध्यादेश किसान विरोधी है, तो वे इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करें. इससे केंद्र सरकार के पास एक कड़ा संदेश जाएगा. केजरीवाल ने कहा कि अध्यादेश आपात स्थिति में लाया जाता है. ऐसी कौन-सी योजना है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक हो गया और सरकार को दो बार अध्यादेश लाना पड़ा? यदि ऐसी कोई योजना नहीं है, तो इसका सीधा-सा मतलब है कि यह अध्यादेश व्यवसायिक घरानों के फ़ायदे के लिए लाया गया है. ■

navinonline2003@gmail.com

...और गजेंद्र मर गया

आपको फिल्म पीपली लाइव का नत्था तो याद ही होगा. इस फिल्म में एक किसान की आत्महत्या का सीधा प्रसारण दिखाने के लिए टीवी चैनल दिल्ली से पीपली गांव तक पहुंच जाते हैं. लेकिन गजेंद्र सिंह की कहानी रील लाइफ से ठीक उलट है. फिल्म में कैमरे नत्था के पास जाते हैं, लेकिन यहां गजेंद्र खुद ही कैमरे के सामने आया. गजेंद्र ने भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ हो रही राजनीतिक रैली में मौत को गले लगा लिया. वह भी देश की संसद से महज एक किलोमीटर की दूरी पर. एक आम किसान को अपनी तकलीफ, बेबसी और लाचारी का एहसास दुनिया को कराने के लिए शायद इससे बड़ा मंच नहीं मिल सकता था. उसने इस मौक़े का फ़ायदा उठाते हुए किसानों की दशकों पुरानी पीड़ा कुछ ही पलों में सियासी गलियारों तक पहुंचा दी. जीते जी जिसकी बदहाली पर किसी का दिल नहीं पसीजा, उस किसान की मौत की ख़बर मिलते ही सियासी मर्सिया पढ़ा जाने लगा. प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक उस किसान के प्रति संवेदना व्यक्त करने लगे. एक ऐसा किसान, जिसे फसल खराब होने के बाद उसके पिता ने घर से निकाल दिया था और वह घर लौटने का रास्ता तलाश रहा था. जिन किसानों के नाम पर जंतर-मंतर पर रैली हो रही थी, उन्हीं में से एक किसान मौत को गले लगा रहा था, लेकिन उसके मरने से पहले और बाद तक सियासत जारी है और जारी रहेगी. जिस मुआवज़े और सांत्वना के लिए किसान जीते जी तरसता रहा, वह सब उसे इस दुनिया से रुखसत होने के बाद हासिल हुआ. एक आम किसान मौत के बाद हर राजनीतिक दल का किसान बन गया. ■

बिखरे-बिखरे जन संगठन

24 फरवरी को जंतर-मंतर से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के ख़िलाफ़ बिगुल फूंकने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे एक बार फिर अलग-थलग नज़र आ रहे हैं. 12 अप्रैल को अन्ना ने पुणे में एक बैठक की, जिसके लिए विभिन्न राज्यों के चुनिंदा लोगों को बुलाया गया था. बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के भोपाल सिंह चौधरी ने बताया कि अन्ना द्वारा शुरू किए गए भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन को दूसरे संगठनों ने हथिया लिया है. पुणे में एक नए संगठन के बारे में चर्चा हुई, लेकिन कोई परिणाम नहीं निकला. बैठक के दौरान वर्धा में हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिली कि वहां मेधा पाटकर और पीवी राजगोपाल के बीच मतभेद हो गए, वहां दो अलग-अलग बैठकें हुईं. इसके बाद अन्ना ने एकता परिषद की यात्रा से खुद को अलग कर लिया और यात्रा रद्द कर दी गई. पुणे में अन्ना की बैठक में शामिल हुए किसान मंच के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शेखर दीक्षित ने बताया कि बैठक का परिणाम कुछ नहीं निकला. हालांकि, बैठक में शामिल होने के लिए कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड आदि राज्यों के जनसंगठनों के प्रतिनिधि आए थे. चर्चा हुई कि आंदोलन को कैसे बड़ा बनाया जाए और कहा गया कि बार-बार रणनीति बदलने और बनाने से कुछ नहीं होगा. गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा, तो सरकार नहीं झुकेगी. बार-बार बैठक करने से आंदोलन नहीं चलेगा और केवल दिल्ली में प्रदर्शन नहीं करना चाहिए.

उधर, नेशनल एलायंस फॉर पीपुल्स मूवमेंट (एनएपीएम) के घटक संगठन आगामी पांच मई को दिल्ली में होने वाली भूमि अधिकार संघर्ष रैली के लिए लोगों को जागरूक करने में लगे हैं, लेकिन उसका असर लोगों के बीच होता नहीं दिख रहा है. मुंबई में हुए समाजवादी समागम में पांच मई के कार्यक्रम के संबंध में भी बात हुई, लेकिन राजनीतिक दलों के साथ कांस्टीट्यूशन क्लब में हुई बैठक के बाद जो प्रस्ताव पारित हुए थे और जिन जगहों पर भूमि अधिग्रहण के ख़िलाफ़ राज्यस्तरीय और जिलास्तरीय कार्यक्रमों की घोषणा हुई थी, उनके संबंध में कोई ख़बर दिल्ली तक नहीं पहुंच रही है. फिलहाल भू-अधिकार आंदोलन के तथाकथित नेतागण अपने-अपने पारंपरिक कामों में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं. कहीं पर भी एकीकृत तरीके से प्रदर्शन नहीं हो रहे हैं, जिससे सरकार पर कोई असर होता दिखाई दे. मध्य प्रदेश के भोपाल में रहने वाले सामाजिक कार्यकर्ता अजय गौड़ का कहना है कि हम लगातार भूमि अधिग्रहण को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. हमारे साथ शहरी वर्ग की हमदर्दी है, लेकिन हम इस आंदोलन में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं और इसका असर आंदोलन पर पड़ रहा है. इसके अलावा बार-बार नेतृत्व और रणनीति में बदलाव से लोगों का विश्वास कम हो रहा है, वे आंदोलन में भागीदारी से कतरा रहे हैं. ■

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

www.kamalmorarka.com

कमल मोरारका

मज़े की बात तो यह है कि पत्रकार सांसद के लिए योग्यता निर्धारित करने की मांग करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो हिंदी या अंग्रेज़ी तो जानते हैं, लेकिन और कुछ नहीं के बराबर जानते हैं. आजकल के युवा पत्रकार भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते, वे विश्व के इतिहास को भूल गए हैं. जो लोग संसद की रिपोर्टिंग करते हैं, वे यह ज़हमत नहीं उठाते कि पुस्तकालय में जाएं और इस बात की जानकारी लें कि जवाहर लाल नेहरू के समय में क्या हुआ था या फिर जब इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री सदन में थे, तो क्या हुआ था? बहुत हुआ, तो वे राजीव गांधी के समय तक की जानकारी रख पाते हैं.

संकट के दौर में भारतीय मीडिया

दुनिया के अन्य देशों की तरह भारत में भी पत्रकारिता साल दर साल परिवर्तित हुई है. अगर हम 1947 में देश को मिली आज़ादी के बाद पिछले 67 सालों की बात करें, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में बड़े परिवर्तन हुए हैं. 1995 के मध्य में सेटेलाइट टीवी हमारे देश में आया. उसके बाद से 24 घंटे चलाए जाने वाले समाचार चैनलों ने अपना एक ब्रांड बनाया, जिसमें एक ही समाचार बार-बार दिखाया जाता है. यही नहीं, हंसी तो इस बात पर आती है कि अलग-अलग समाचार चैनल अलग-अलग समाचार दोहराते रहते हैं. टीवी चैनलों के आ जाने से समाचार-पत्रों पर उनका प्रभाव पड़ा है. समाचार-पत्र बहुत ज़्यादा समाचार नहीं दे पाते, क्योंकि एक दिन पहले ही हम टेलीविजन पर समाचार देख लेते हैं. लेकिन, समाचार-पत्रों की महत्ता इस बात के लिए है कि हम उनमें न केवल रोज़मर्रा के समाचार पाते हैं, बल्कि उसके साथ किसी मुद्दे पर विभिन्न लोगों के विचार भी हमें पढ़ने को मिलते हैं. समाचार-पत्रों में जो रोज़ के समाचार दिए जाते हैं, उन्हें ग़लत तरीक़े से पेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन समाचारों को लोग टीवी पर पहले ही देख लेते हैं.

पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले कुछ सालों से कुछ समाचार-पत्रों को छोड़कर, अधिकांश समाचार-पत्रों और टीवी चैनलों के मालिक व्यवसायिक घराने के हो गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो समाचार हमें मिलते हैं, वे पूंजीपतियों के लिए होते हैं, न कि आम आदमी या फिर समाज के निचले तबक़े के लोगों के लिए. उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के समय लाए गए आर्थिक सुधार को ले सकते हैं. मुझे विश्वास है कि किसी भी अन्य नीति की तरह इसके भी दो पक्ष हैं. यही वजह है कि कुछ लोग किसी नीति का समर्थन करेंगे और कुछ लोग विरोध, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1991 के बाद सभी समाचार-पत्र और टीवी चैनल इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि आर्थिक सुधार ही भारत की सभी समस्याओं का अंतिम समाधान है. यही कारण है कि इतने वर्षों के बाद लोग यह कहते नज़र आ रहे हैं कि बहुत विकास हुआ है, लेकिन तथ्य कुछ और है.

अगर आप प्रत्येक पांच साल का औसत निकालेंगे, तो पाएंगे कि परिणाम मिश्रित रहा है. कभी विकास की गति तेज़ रही, तो कभी काफ़ी धीमी. पिछले कुछ सालों की बात करें, तो विकास दर नीचे गिर रही है. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि विकास दर का संबंध केवल आर्थिक नीति से है. इसके कई अन्य कारण भी हैं. उदाहरण के तौर पर इस समय अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं, इसलिए विकास दर धीमी रही है. इसके लिए किसी विशेष आर्थिक नीति को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. मतलब यह है कि मीडिया को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए. आजकल मीडिया की निर्भरता कॉरपोरेट क्षेत्र पर अत्यधिक बढ़ गई है. किसी भी स्थिति में मीडिया विज्ञापनों के लिए कॉरपोरेट क्षेत्र पर निर्भर रहता है, लेकिन पहले और आजकल की स्थिति में परिवर्तन आ गया है. पहले समाचार-पत्रों के प्रसार और लोगों तक उनकी पहुंच के आधार पर विज्ञापन दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है. आजकल बड़े-बड़े औद्योगिक घराने शीर्ष के समाचार-पत्रों को विज्ञापन नहीं देते, क्योंकि वे उनके खिलाफ़ लिखते हैं. मेरी जानकारी के अनुसार, किसी अन्य देश में ऐसा नहीं होता है.

भारत में 1970 के दशक में इंदिरा गांधी डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट नाम से एक विधेयक लाई थीं. यह विधेयक संसद में पेश तो हुआ, लेकिन पारित नहीं हुआ और क़ानून नहीं बन पाया. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य यह था कि जो व्यक्ति समाचार-पत्र का मालिक है, वह किसी दूसरे उद्योग का मालिक नहीं हो सकता और जो किसी दूसरे उद्योग का मालिक है, वह समाचार-पत्र नहीं निकाल सकता है. औद्योगिक घरानों ने इसका विरोध किया और कहा कि यह प्रेस की स्वतंत्रता पर आक्रमण है, जबकि वास्तविकता यह नहीं थी. आज प्रेस के ऊपर हमला किसी तानाशाह द्वारा नहीं, बल्कि धन कुबेरों द्वारा

पत्रकारिता की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि पिछले कुछ सालों से कुछ समाचार-पत्रों को छोड़कर, अधिकांश समाचार-पत्रों और टीवी चैनलों के मालिक व्यवसायिक घराने के हो गए हैं. इसका परिणाम यह हुआ कि आज जो समाचार हमें मिलते हैं, वे पूंजीपतियों के लिए होते हैं, न कि आम आदमी या फिर समाज के निचले तबक़े के लोगों के लिए. उदाहरण के तौर पर वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह के समय लाए गए आर्थिक सुधार को ले सकते हैं. मुझे विश्वास है कि किसी भी अन्य नीति की तरह इसके भी दो पक्ष हैं.

किया जा रहा है. प्रेस को समाप्त करने के दो तरीक़े होते हैं. पहला यह है कि समाचार-पत्र को प्रकाशित ही न होने दिया जाए. यह तरीक़ा तानाशाही वाले देशों में अपनाया जाता है. दूसरा तरीक़ा यह है कि प्रेस को पैसे से खरीद लो, ताकि वह सही विचार ही प्रस्तुत न कर सके. भारत में यही दूसरा तरीक़ा अपनाया जाता है. आजकल अगर कोई ग़रीबों, अल्पसंख्यकों, बेरोज़गारों एवं अनुसूचित जाति के लिए आवाज़ उठाता है, तो उसे मीडिया समाचार नहीं बनाता है.

आजकल किसी समाचार-पत्र का विचार उसके संपादक का विचार नहीं होता, बल्कि उस समाचार-पत्र के मालिक का विचार होता है. ऐसा क्यों होता है? मुझे याद है कि जब मैं स्कूल और कॉलेज में था, तो समाचार-पत्र के संपादक और मालिक के बीच टकराहट होती रहती थी. हिंदुस्तान टाइम्स के मालिक बिड़ला थे और संपादक एस मुलगांवकर थे, टाइम्स ऑफ इंडिया के मालिक डालमिया एवं जैन थे और संपादक फ्रैंक मोरेस थे या फिर इंडियन एक्सप्रेस के मालिक राम नाथ गोयनका थे, जो अलग तरह के थे. उस समय बात कुछ और थी, लेकिन आज संपादक समाचार-पत्र के मालिक के एजेंट हो गए हैं. अधिकांश संपादक अपनी सुविधा का ख्याल पहले रखते हैं. अधिकांश संपादक किसी विषय पर लिखने से पहले समाचार-पत्र के मालिक से पूछते हैं कि कहीं इसे छापने से मालिक वर्ग के लोगों को नुक़सान तो नहीं होगा? मालिक भी संपादकों से पूछते हैं कि कौन-सी कार आप लोग लेंगे, कितना वेतन आप लोग लेंगे या फिर किस तरह की सुविधा आप लेंगे? इस तरह से सारे के सारे संपादकीय वर्ग के लोग मालिक वर्ग में शामिल हो गए हैं.

अब यह बहुत कठिन सवाल है कि इस विकासशील समाज में हम इसे कैसे रोक सकते हैं? मैं सोचता हूं कि एक ऐसा क़ानून होना चाहिए, जिसके द्वारा इसे रोका जा सके. डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट इसे रोकने का एक रास्ता हो सकता है. इसके अलावा और भी कोई रास्ता हो सकता है. भारत में पत्रकार बनने के लिए किसी तरह की योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया है. सबसे बड़ी बात तो यह है कि पत्रकार यह तर्क देते हैं कि निरक्षर लोग संसद में जा रहे हैं. संसद लोगों का प्रतिनिधित्व करती है. मान लें, आप कहते हैं कि सांसद बनने के लिए स्नातक की डिग्री ज़रूरी हो. इसका मतलब यह है कि आप 90 फ़ीसद लोगों को इससे अलग कर रहे हैं, क्योंकि भारत के अधिकांश लोग ग्रेजुएट नहीं हैं. इसलिए आप यह नहीं कह सकते कि जो लोग हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वे हमसे अलग वर्ग के हों. गांव के लोग गांव के लोगों में से ही किसी को अपना प्रतिनिधि चुनेंगे.

मज़े की बात तो यह है कि पत्रकार सांसद के लिए योग्यता निर्धारित करने की मांग करते हैं, लेकिन अपने लिए नहीं. मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो हिंदी या अंग्रेज़ी तो जानते हैं, लेकिन और कुछ नहीं के बराबर जानते हैं. आजकल के युवा पत्रकार भारत के इतिहास के बारे में नहीं जानते, वे विश्व के इतिहास को भूल गए हैं. जो लोग संसद की रिपोर्टिंग करते हैं, वे यह ज़हमत नहीं उठाते कि पुस्तकालय में जाएं और इस बात की जानकारी लें कि जवाहर लाल नेहरू के समय में क्या हुआ था या फिर जब इंदिरा गांधी या लाल बहादुर शास्त्री सदन में थे, तो क्या हुआ था? बहुत हुआ, तो वे राजीव गांधी के समय तक की जानकारी रख पाते हैं. इसलिए भारत के पत्रकारों के स्तर में सुधार के लिए कुछ करने की आवश्यकता है. कैसे किया जाए, यह एक कठिन सवाल है. सबसे पहले समस्या का अनुभव करना ज़रूरी है, उसके बाद ही उसका समाधान हो सकता है.

आज भारतीय मीडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह संकट के दौर से गुज़र रहा है. अधिकांश समाचार-पत्र कॉरपोरेट हाउसों के लिए काम कर रहे हैं. छोटे समाचार-पत्रों को दबा दिया जाता है, क्योंकि वे विज्ञापन नहीं ले पाते हैं. इसलिए सरकार को इन छोटे समाचार-पत्रों के लिए ज़रूर कुछ करना चाहिए, ताकि ये अपने पैरों पर खड़े हो सकें. या फिर डिफ्यूजन ऑफ प्रेस ऑनरशिप एक्ट जैसा क़ानून लाना चाहिए. क्या करना चाहिए, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इसे बहस का एक मुद्दा बनाना चाहूंगा. ■

feedback@chauthiduniya.com

एक औघड़ लीक से हटकर-2

परोपकारी-महात्मा थे भगवान राम

क्या औघड़ों के पास सचमुच कोई ऐसी ताकत होती है, जिससे वे परा जगत की तथाकथित शक्तियों को अपने वश में कर लेते हैं? क्या औघड़ विज्ञान की तार्किक दुनिया से परे होते हैं. उनमें असामान्य शक्तियों का निवास होता है? आम तौर पर औघड़ कहने से जो चित्र सामने आता है, उसमें दिखाई देता है श्मशान में रहने वाला एक अजीब-सा आदमी, जो भभूत लपेटे रहता है तथा हड्डियों आदि की माला पहने रहता है. विचित्र कपड़े पहनता है तथा शराब-मांस पीता-खाता रहता है. वह किसी चीज से परहेज नहीं करता तथा भयंकर क्रोधी होता है. लेकिन औघड़ भगवान राम ऐसी किसी भी परंपरागत छवि से बिल्कुल भिन्न हैं. औघड़ उन्हें अघोरेश्वर कहते हैं तथा उनका मानना है कि औघड़ भगवान राम के रूप में बाबा किनाराम ने पुनर्जन्म लिया है. भगवान राम अगर उस किस्म के औघड़ होते, जैसे औघड़ों से हम सामान्यत: परिचित हैं, तो शायद उनका वह सामाजिक महत्व न होता, जो आज है. वह उतने परोपकारी औघड़ हैं, जितना कि जनसामान्य के कल्याण के लिए कार्य करने वाला कोई महात्मा. उनके नाम की भी एक कहानी है. औघड़ों में जो भी साधना करता है, उसे अपने नाम के आगे राम लगाना होता है. पैदा होने के बाद मां-बाप ने उनका नाम भगवान रखा था. अत: साधना के क्षेत्र में प्रवेश करते ही उनके नाम के आगे राम लग गया और वह भगवान राम हो गए.

बिहार में आरा रेलवे स्टेशन से आठ मील उत्तर, गंगा से डेढ़ मील दक्षिण और सोन से पांच मील पश्चिम में गुंडी नाम का गांव है. गांव चारों ओर से सघन और सुंदर अमराइयों से घिरा हुआ है. 5,000 से ज़्यादा की आबादी है. लगभग 160 वर्ष पहले इस गांव में बाबा रामेश्वर दास रहते थे. बाबा गृहस्थ होते हुए भी सांसारिक बंधनों से मुक्त रहते थे. उनके बारे में विभिन्न प्रकार की किवदंतियां हैं. कहते हैं, उनके दर्शन के लिए अनेक साधक-संत आया करते थे. इसी गांव में साईं सामसीन जी फकीर थे. उनकी पूजा हिंदू-मुसलमान दोनों करते थे. औघड़ बाबा पकड़ी जगतपुर के बहुत ही सिद्ध अवधूत थे. कहा जाता है कि वह अक्सर वायुमार्ग से गुंडी गांव आया करते थे तथा यहीं पर बाबा रामेश्वर दास जी, साईं साहब एवं बसुरिया बाबा का सत्संग हुआ करता था.

आज पत्रकारिता के मायने बदल गए हैं, बदल रहे हैं अथवा बदल दिए गए हैं, नतीजतन, उन पत्रकारों के सामने भटकाव जैसी स्थिति आ गई है, जो पत्रकारिता को मनसा-वाचा-कर्मणा अपना धर्म-कर्तव्य और कमज़ोर-बेसहारा लोगों की आवाज़ उठाने का माध्यम मानकर इस क्षेत्र में आए और हमेशा मानते रहे. और, वे नवांकुर तो और भी ज़्यादा असमंजस में हैं, जो पत्रकारिता की दुनिया में सोचकर कुछ आए थे और देख कुछ और रहे हैं. ऐसे में, 2005 में प्रकाशित संतोष भारतीय की पुस्तक-पत्रकारिता: नया दौर, नए प्रतिमान हमारा मार्गदर्शन करती और बताती है कि हमारे समक्ष क्या चुनौतियां हैं और हमें उनका सामना किस तरह करना चाहिए. चार दशक से भी ज़्यादा समय हिंदी पत्रकारिता को समर्पित करने वाले संतोष भारतीय देश के उन पत्रकारों में शुमार किए जाते हैं, जो देश और समाज से जुड़े प्रत्येक मुद्दे पर निर्भीक, सटीक, निष्पक्ष टिप्पणी करते हैं.

इसी गांव में बैजनाथ सिंह रहते थे, जिनके बहुत दिनों तक कोई संतान नहीं हुई. वह यज्ञावतार जी के बहुत भक्त थे. उनकी प्रेरणा से जो भी गायक गुजरता था, वह यज्ञावतार जी के मंदिर में अवश्य गाता था. उन्हीं बैजनाथ सिंह के यहां संवत् 1994 वि. भाद्र शुक्ल सप्तमी, रविवार को एक पुत्र हुआ. जब उस बालक का जन्म हुआ, तो बैजनाथ सिंह ने कहा कि मेरे परिवार में साक्षात भगवान ने जन्म लिया है. उन्होंने उसका नाम भी भगवान रख दिया. जब भगवान पांच वर्ष के थे, तभी बैजनाथ सिंह का देहांत हो गया. इकलौता पुत्र होने के कारण भगवान का स्वभाव हठीला हो गया था. उन्हें पाठशाला भेजा गया, पर वहां की पढ़ाई में उनका मन नहीं लगा. वह पाठशाला जाने के बदले अपने गृह-देवालय और अपने ही बगीचे में पूजा-अर्चना में समय लगाने लगे. वहीं समवयस्क बच्चों के साथ सुबह-शाम कीर्तन आदि करते थे. वह उन्हें ध्रुव और प्रह्लाद की कहानियां भी सुनाया करते थे. भगवान सात वर्ष की वय तक ही घर में रहे. इसके बाद वह गांव में रहते ज़रूर थे, पर घर से बाहर. शुरू में दो-चार वर्ष तक तो उन्होंने घर से आया हुआ भोजन किया, परंतु बाद में वह भी बंद कर दिया.

शुरू में वह अपने घर के निकट शिव मंदिर के पास ज़मीन के भीतर कोठरी बनाकर रहते थे. उसमें कभी-कभी दो दिनों तक बिना अन्न-जल ग्रहण किए ही उनकी पूजा चलती रहती थी. दैनिक पूजा का यह क्रम इस उम्र के बालक के लिए अति कठोर था. दोनों नवरात्रि में उनका विशेष व्रतोपवास एवं पूजन चलता था. इस व्रत में भगवान नौ दिनों तक केवल जल पीकर रहते थे तथा दिन-रात पूजन, सत्संग एवं कीर्तन का कार्यक्रम करते रहते थे. जब इस प्रकार की साधना से भगवान को शांति नहीं मिली, तब वह गांव के बाहर अपने खेत के निकट कुटी बनाकर रहने लगे. वहां स्कूल के छात्र अवकाश के समय बड़ी संख्या में आते थे. उन बच्चों ने ही भगवान को भगवान दास कहकर पुकारना शुरू किया. घर वालों का आग्रह था कि भगवान दास घर में रहें, पर वह घर छोड़कर निकल पड़े और गया की ओर बढ़ने लगे. वह दिन भर चलते थे, पर रात उन्हें अरहर के खेत में गुजारनी पड़ती थी. साथ में कुछ भी सामान नहीं था. गया में कुछ दिन रहकर भगवान दास जगन्नाथ पुरी गए. उन दिनों वह जैन मुनियों की तरह आचरण करते थे. जगन्नाथ जी के दर्शन करके वह वापस आए और रामानुज संप्रदाय के एक अधिवेशन में सम्मिलित हुए. उसमें देश के विभिन्न भागों से साधु-संत आए थे. उस अधिवेशन से लौटकर भगवान दास दालान में लेटे थे. उसी समय उन्हें एक अद्भुत चमत्कारिक प्रकाश दिखाई पड़ा. उस घटना के वक्त दिन के समय भी उनकी आंखें बंद हो गईं तथा हृदय तेजी से धड़कने लगा. बाद में कई वर्षों तक यह धड़कन उभरती रही, लेकिन फिर बंद हो गई. ■

क्रमश:

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

संघ की चिंता के मायने

संघ इस बात से बहुत चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से बड़ा है, यह भावना तेजी से चल रही है. संघ अभी किसी को दोष नहीं दे रहा है. लेकिन संघ के वरिष्ठ लोगों को लगता है कि जानकारी और ज्ञान के मामले में भारतीय जनता पार्टी में फ़ैसला करने वाले पूर्णतय: परिपक्व नहीं हैं. इसीलिए वे अपने ज्ञान को सबके ज्ञान से ज़्यादा मानते हैं. और, यह अहम भारतीय जनता पार्टी में और अंतर्विरोध पैदा करेगा.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भारतीय जनता पार्टी को लेकर कुछ चिंताएं उभर रही हैं और ये चिंताएं उसकी नज़र में महत्वपूर्ण हैं. संघ को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के उस बयान पर सबसे ज़्यादा आश्चर्य हुआ, जो चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादों को पूरा करने के संदर्भ में पूछे गए एक सवाल के जवाब स्वरूप आया. अमित शाह ने कहा कि चुनाव में बहुत सारी बातें होती हैं, उन बातों का कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, ये चुनावी जुमले हैं. और, यह बात उन्होंने काला धन वापस लाने के संदर्भ में कही थी. संघ को लगता है कि अमित शाह ने यह बयान जिस भावना के तहत दिया, उसी भावना के तहत अब अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि चुनाव में किए गए वादों में केवल 40 या 50 प्रतिशत ही पूरे होते हैं.

संजय जोशी ने आज तक कभी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बयान दिया, न अमित शाह के ख़िलाफ़ और न उनकी नीतियों एवं कार्यकलापों के ख़िलाफ़ जाकर कुछ किया, बल्कि उल्टे संजय जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम सार्वजनिक रूप से अपना नेता माना है. इसके बावजूद संघ की समझ में यह नहीं आ रहा कि अगर संजय जोशी कमजोर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती क्यों है और अगर संजय जोशी मजबूत हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ क्यों नहीं जोड़ती? भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल के आधार पर अपनी सदस्य संख्या 10 करोड़ बता रही है, तो वह संजय जोशी को पार्टी का सदस्य क्यों नहीं मानती?

संघ के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर भी चिंताएं हैं. दरअसल, सच्ची सदस्यता वह होती है, जिसमें आप किसी व्यक्ति के दरवाजे जाएं, उसे पार्टी की नीतियां समझाएं, उससे फॉर्म भरवाएं और उससे सदस्यता का पैसा लें. मिस्ड कॉल के ज़रिये जितने सदस्य बने हैं, उन्होंने सदस्यता का न फॉर्म भरा है, न दस्तखत किए हैं, न सदस्यता का चंदा दिया है और वे भारतीय जनता पार्टी की 10 करोड़ की संख्या वाली पार्टी के सदस्य बन गए और पार्टी ने खुद को दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में प्रचारित करना शुरू कर दिया. संघ इसे राजनीतिक ढलान की बड़ी फिसलन के रूप में देख रहा है और संघ के वरिष्ठ, निष्ठावान प्रचारक या कार्यकर्ता खुद को बहुत दु:खी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए अपनी संपूर्ण ताकत लोकसभा के चुनाव में लगा दी थी.

संघ को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी तेजी के साथ संस्थागत नेतृत्व की जगह पर व्यक्तिगत नेतृत्व की तरफ़ बढ़ती जा रही है. संस्थागत नेतृत्व में सभी से सलाह करके कोई फ़ैसला लिया जाता है, जबकि व्यक्तिगत नेतृत्व में एक व्यक्ति को जो सही लगता है, वही फ़ैसले के रूप में लागू होता है. इसका उदाहरण किरण बेदी हैं. किरण बेदी के बारे में न संघ से बात हुई और न पार्टी के वरिष्ठ लोगों से. एक बात दिमाग में आई और फ़ैसला हो गया, जिसका ख़तरनाक नतीजा देखने को मिला. लेकिन, संघ अब इस बात से चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी संस्थागत संगठनात्मक ढांचे से अलग व्यक्तिगत संगठनात्मक ढांचे की तरफ़ बढ़ रही है.

संघ कश्मीर के फ़ैसले को भी भारतीय जनता पार्टी का फिसलन वाला फ़ैसला मानता है. पीडीपी से समझौता करके भारतीय जनता पार्टी ने खुद को अपनी सैद्धांतिक स्थिति से पीछे हटा लिया, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को देश भर में उन लोगों का समर्थन मिला था, जो कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं और कश्मीर से धारा 370 हटाने का समर्थन करते हैं. लेकिन, भाजपा इस स्थिति में पहुंच गई है कि वह समर्थन वापस नहीं ले सकती, क्योंकि अगर समर्थन वापस लेती है, तो पीडीपी सरकार को तत्काल कांग्रेस और नेशनल कांफ्रेंस का समर्थन मिल जाएगा और मुफ्ती साहब की सरकार कश्मीर में चलती रहेगी. आप उसे बर्खास्त नहीं कर सकते. दूसरी बात, अगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी शामिल रहती है, तो मुफ्ती साहब इसी तरह के फ़ैसले करते रहेंगे, जैसा उन्होंने मसर्रत के मसले में किया और कश्मीर को एक नई प्रकार की अराजकता की तरफ़ धकेल दिया. कश्मीर में पुन: खुलेआम पाकिस्तान समर्थक नारे लगने और पाकिस्तानी झंडे लहराए जाने लगे हैं. संघ इस स्थिति को बहुत ही चिंता की नज़र से देख रहा है.

संजय जोशी ने आज तक कभी न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बयान दिया, न अमित शाह के ख़िलाफ़ और न उनकी नीतियों एवं कार्यकलापों के ख़िलाफ़ जाकर कुछ किया, बल्कि उल्टे संजय जोशी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुलेआम सार्वजनिक रूप से अपना नेता माना है. इसके बावजूद संघ की समझ में यह नहीं आ रहा कि अगर संजय जोशी कमजोर हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उनसे डरती क्यों है और अगर संजय जोशी मजबूत हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने साथ क्यों नहीं जोड़ती? भारतीय जनता पार्टी मिस्ड कॉल के आधार पर अपनी सदस्य संख्या 10 करोड़ बता रही है, तो वह संजय जोशी को पार्टी का सदस्य क्यों नहीं मानती?

संघ को यह भी अजीब लगा कि जब उसने राम माधव को भाजपा में भेजा था, तो यह मानकर भेजा था कि वह उसकी नीतियां भाजपा में पूरी तरह से लागू करेंगे, लेकिन कश्मीर के मसले पर स्वयं राम माधव ने उस व्यक्ति से राय नहीं ली, जिस पर सरसंघचालक मोहन भागवत का सबसे ज़्यादा भरोसा है. उनका नाम है अरुण खन्ना, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में अरुण जी के नाम से जाना जाता है. कश्मीर मामले में सरसंघचालक मोहन भागवत का सबसे ज़्यादा भरोसा अरुण जी पर है. राम माधव ने अरुण जी से बात ही नहीं की और कश्मीर को लेकर ताबड़तोड़ फ़ैसले नरेंद्र मोदी और अमित शाह से करा लिए. इन लोगों को लगा कि संघ की इसमें सहमति है. जब संघ के भीतर इंद्रेश जी ने यह सवाल उठाया कि कश्मीर में मुफ्ती के साथ सरकार हम कैसे बना सकते हैं, जबकि उन्होंने धारा 370 हटाने से मना कर दिया है और हम उसके प्रति समर्पित हैं? तब राम माधव ने कहा, मैं सब जानता हूं और जिन्हें इस बात की जानकारी होनी चाहिए, उन्हें बता दिया गया है. जबकि हक़ीक़त यह है कि श्री मोहन भागवत, श्री भैय्याजी जोशी और श्री एमजी वैद्य को इस संदर्भ में कुछ भी नहीं बताया गया था. यह राम माधव का फ़ैसला था, जिसे भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू-कश्मीर में लागू किया.

संघ इस बात से बहुत चिंतित है कि भारतीय जनता पार्टी में मेरा ज्ञान तुम्हारे ज्ञान से बड़ा है, यह भावना तेजी से चल रही है. संघ अभी किसी को दोष नहीं दे रहा है, लेकिन संघ के वरिष्ठ लोगों को लगता है कि जानकारी और ज्ञान के मामले में भारतीय जनता पार्टी में फ़ैसला करने वाले पूर्णतय: परिपक्व नहीं हैं, इसीलिए वे अपने ज्ञान को सबके ज्ञान से ज़्यादा मानते हैं. और, यह अहम भारतीय जनता पार्टी में और अंतर्विरोध पैदा करेगा. संघ को इस बात से भी बहुत परेशानी हो रही है कि पहले तो यह फ़ैसला (मसर्रत आलम वाला) मुफ्ती सरकार का फ़ैसला माना गया, लेकिन बाद में पता चला कि यह तो राष्ट्रपति शासन के समय यानी जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और श्री राजनाथ सिंह गृह मंत्री बने, तब गृह मंत्रालय ने लिया. संघ को लगता है कि या तो राजनाथ सिंह ने जानबूझ कर यह फ़ैसला होने दिया, ताकि भविष्य में प्रधानमंत्री के लिए परेशानी हो या फिर राजनाथ सिंह दूसरे कामों में इतने व्यस्त थे और उनके अधिकारियों ने उन्हें कश्मीर पर फ़ैसला लेने से पहले कुछ बताया नहीं.

संघ को लगता है कि राजनाथ सिंह को उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, जिन्होंने राष्ट्रपति शासन के दौरान कश्मीर संबंधी यह ख़तरनाक फ़ैसला मसर्रत को लेकर किया था. पर अभी तक संघ की इस इच्छा के ऊपर गृह मंत्री ने कोई क़दम नहीं उठाया है. संघ के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस बात से परेशान दिखे और उन्होंने टिप्पणी की. पहले तो राजनाथ सिंह ने आरोप-प्रत्यारोप किए और बाद में जब पता चला कि यह फ़ैसला तो उनके गृह मंत्री रहते हुए केंद्रीय स्तर पर हुआ है, तो वह चुप हो गए. संघ के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का कहना है कि इसे क्या मानें? संघ का कहना है कि यह समझ या मूर्खता थी या सच या साजिश? पर कहीं कुछ गड़बड़ है, जो ठीक होने के रास्ते पर आती दिखाई नहीं देती.

संघ की इस चिंता में दम है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कांग्रेस की तरह व्यक्तिगत पद्धति के ऊपर जा रही है, न कि संस्थागत पद्धति के ऊपर. संघ का मानना है कि जब तक कांग्रेस संस्थागत संगठनात्मक पद्धति से चली, उसमें राजनीति समझने वाले और जनता के प्रति समर्पित लोगों का सबसे बड़ा जमावड़ा था. पर जैसे ही वह व्यक्तिगत संगठन की तरफ़ बढ़ी, वैसे ही उन लोगों का राजनीतिक पतन या राजनीतिक वनवास शुरू हो गया, जो वैचारिक रूप से देश के लिए प्रतिबद्ध थे. अब यही डर भारतीय जनता पार्टी को लेकर है कि संस्थागत पद्धति से फ़ैसले न होना और संस्थागत संगठन का न बनना भविष्य में बहुत सारे अच्छे, समझदार, जनता के प्रति समर्पित, संघ की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध लोगों को पार्टी की मुख्य धारा से बाहर धकेल देगा.

यह चिंता संघ और पार्टी के भीतर की चिंता है, जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं. और, इन चिंताओं से देश के उन लोगों का भी चिंतित होना आवश्यक है, जो भारतीय जनता पार्टी और संघ की विचारधारा को देश के लिए ठीक नहीं मानते. क्योंकि, जनता ने अगले पांच वर्षों के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथ में देश की कमान सौंपी है और अचानक भारतीय जनता पार्टी एक वर्ष के भीतर ही सामूहिक चिंतन और निर्णय की प्रक्रिया से अलग हटकर वैयक्तिक चिंतन, वैयक्तिक निर्णय प्रक्रिया की तरफ़ जा रही है. सवाल हैं, लेकिन सवालों का जवाब खोजने की जगह भारतीय जनता पार्टी और सवाल खड़े कर रही है. खासकर ऐसे सवाल खड़े कर रही है, जिनका जवाब क्या है, कम से कम आज तो उसे नहीं मालूम है. संघ इस स्थिति को बहुत चिंता की नज़र से देख रहा है. ■

editor@chauthiduniya.com

अंबेडकर को कैसे याद करना चाहिए

अंबेडकर आजीवन हिंदू धर्म और जातिवाद से जूझते रहे. उनके वृहद् ज्ञान का अंदाज़ा भगवद्गीता पर उनकी आलोचना और जातीय व्यवस्था पर उनके तीखे विश्लेषण से लगाया जा सकता है. दरअसल, अंबेडकर जिस तरह का बदलाव चाहते थे, वह नहीं हो सका. कांग्रेस के नेता जाति व्यवस्था में किसी तरह की छेड़छाड़ के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हो जाते थे.

मेघनाद देसाई

उन दिनों मैं माटुंगा के रुईया कॉलेज में पढ़ने वाला एक किशोर था. दिसंबर महीने के एक दिन मैंने एक लंबी कतार देखी, जो कहीं दूर से शुरू हुई थी और हमारे कॉलेज के सामने से मुड़कर दोहरी हो गई थी. कतार में खड़े लोग शांत थे, लेकिन उनके चेहरे से उदासी साफ़ झलक रही थी. देखने में वे ग़रीब थे, लेकिन उन्होंने अपनी-अपनी हैसियत के हिसाब से अच्छे कपड़े पहन रखे थे. हालांकि, कई लोगों के कपड़े पुराने और फटे हुए थे. उनके वहां एकत्र होने की वजह हमें जल्द ही मालूम हो गई. मैंने लोगों से पूछा, इतनी लंबी कतार क्यों? जवाब मिला कि वे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए खड़े हैं. अंबेडकर का कुछ समय पहले स्वर्गवास हुआ था. इस दृश्य ने मेरे राजनीतिक विचार को बदल दिया. दरअसल मैं डॉ. अंबेडकर से वाकिफ था. मुझे मालूम था कि उन्होंने सिद्धार्थ कॉलेज की स्थपना की थी. मुझे यह भी मालूम था कि उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की शुरुआत की थी, लेकिन जो बात मेरी समझ में नहीं रही थी, वह थी दबे-कुचले लोगों में उनके प्रति समर्थन की गहराई. उस समय दलित शब्द आम बोलचाल की भाषा में अपनी जड़ें उतनी मजबूती से स्थापित नहीं कर पाया था, जितनी वर्तमान में कर सका है. ऊंची जाति के एक मध्यमवर्गीय परिवार के बालक होने के नाते मेरी परवरिश किसी भी सवर्ण हिंदू बच्चे की तरह हुई थी, जो अछूतों के शोषण की कौन कहे, उनके वजूद से भी बेख़बर था. वे हमारे लिए अदृश्य थे. लेकिन, उस दिन मैं अपने जीवन में पहली बार उस शख्स की शक्ति देख रहा था, जिसने असंख्य लोगों के दिलों में अपने प्रति श्रद्धा और भक्ति की भावना पैदा कर ली थी.

यह 59 साल पहले की बात है. उस समय से लेकर अब तक देश में बहुत कुछ बदल चुका है. कुछ लोग यह तर्क देंगे कि कांशी राम ने बाबा साहेब के समर्थकों के बड़े समूह को एक राजनीतिक शक्ति में बदल दिया. आज विभिन्न राजनीतिक दल अंबेडकर पर अपना दावा इसलिए पेश कर रहे हैं, क्योंकि दलित एक वोट ब्लॉक के तौर पर सशक्त हो चुके हैं. भाजपा/संघ द्वारा बाबा साहेब पर किए गए दावे को लेकर कांग्रेस हंगामा कर रही है, लेकिन वह यह भूल गई है कि गांधी जी ने अंबेडकर की महान उपलब्धियों को गोलमेज कांफ्रेंस में कितना नुक़सान पहुंचाया था. कांग्रेस ने गोलमेज कांफ्रेंस में हिस्सा लेने से इंकार कर दिया था, जबकि देश के बाकी सभी दावेदार, जिनमें सभी धर्म, अछूतों समेत सभी जातियां और राजा-महाराजा शामिल थे. अंबेडकर ने अपने लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल (इलेक्टोरेट्स) की ज़ोरदार तरीके से मांग उठाई, लेकिन स्वर्ण हिंदू निचली जाति के लोगों को ऐसी कोई रियायत देने लिए तैयार नहीं थे. गांधी जी आमरण अनशन पर चले गए, जिसे बाबा साहेब ने ख़राब क़दम करार दिया था, लेकिन अंबेडकर को हार माननी पड़ी थी. अंबेडकर और कांग्रेस के नेताओं के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें एक सेक्युलर पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सवर्णों की ओर से एक पक्ष थी. इस तरह अछूतों ने अपने जीवन में सुधार लाने का एक मौक़ा खो दिया. दलितों को उस समय सीटों के आरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उसका मतलब यह था कि सवर्णों को

अछूत उम्मीदवारों के लिए मतदान करना पड़ता. ऐसे में, वही लोग चुनाव जीत सकते थे, जो वर्ण व्यवस्था को चुनौती नहीं देते थे.

अंबेडकर आजीवन हिंदू धर्म और जातिवाद से जूझते रहे. उनके वृहद् ज्ञान का अंदाज़ा भगवद्गीता पर उनकी आलोचना और जातीय व्यवस्था पर उनके तीखे विश्लेषण से लगाया जा सकता है. दरअसल, अंबेडकर जिस तरह का बदलाव चाहते थे, वह नहीं हो सका. कांग्रेस के नेता जाति व्यवस्था में किसी तरह की छेड़छाड़ के विरुद्ध दृढ़ता से खड़े हो जाते थे. उनके पास बाबू जगजीवन राम जैसे अपने पसंदीदा अछूतों के लिए बचे-खुचे रोटी के टुकड़े थे. यहां तक कि उन्हें भी भेदभाव का सामना करना पड़ा. जनता पार्टी के दिनों में जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने के जयप्रकाश नारायण के विचार को चरण सिंह ने रद्द कर दिया. इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता कि अछूत के तौर पर आप कितनी भी ऊंचाई तय कर लें, आप ऊंची जाति के लोगों की ओर से हमेशा अपमान का बिंदु बने रहेंगे. अब यह देखिए कि ग़रीब बाबा साहेब को भाजपा/संघ एक महान हिंदू बना रहे हैं. दरअसल, जब मामला वोट हासिल करने का हो, तो पाखंड की कोई सीमा नहीं रहती. जाति व्यवस्था के विरुद्ध उनके परिवर्तनकारी संघर्ष (यह ऐसी लड़ाई थी, जिसे कम्युनिस्ट मूवमेंट का भी समर्थन नहीं था) पर बात करने के बजाय ये लोग अंबेडकर को संविधान सभा की संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष के निष्पक्ष पद पर बैठा रहे हैं. संविधान-पिता के रूप में इस बात की बहुत कम संभावना है कि उन्हें हिंदू धर्म को चुनौती देने वाले के तौर पर याद किया जाए, जो सभी बड़े राजनीतिक दलों के लिए सुविधाजनक स्थिति है.

अंबेडकर ने ब्राह्मणवाद को नकार दिया था. उन्होंने ब्राह्मणवाद पर एक हज़ार साल पहले के बौद्ध धर्म की क्रांतिकारी चुनौती को अपना विषय बनाया. इतिहास के इस अध्याय को भारतीयों की स्मृति से बाहर कर दिया गया था. दरअसल, बाबा साहेब जो थे, उन्हें उसी रूप में याद किया जाना चाहिए. वह ब्राह्मणवाद और जाति व्यवस्था के कट्टर आलोचक थे. उन्हें वोट बैंक के वाहक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. और, अपने जीवन में एक लंबे संघर्ष के बाद अब उनकी आत्मा को शांति मिल जानी चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

गर्मी बढ़ते ही शहर में वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है. वायु प्रदुषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइ ऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस आक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. अचानक तापमान में हुई बढ़ोत्तरी से डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द, बुखार और बदन दर्द जैसी बीमारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है. ज्यादा गर्मी बढ़ने से त्वचा पर चकते और खुजली की शिकायत होने लगती है.

ख़राब स्वास्थ्य का जिम्मेदार है वायु प्रदूषण

मोनिशा भटनागर
feedback@chauthiduniya.com

भारत दुनिया के कुछ उन देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को सर्वाधिक वायु प्रदूषण वाले देशों की में सूची रखा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार विश्व के सर्वाधिक 20 प्रदूषित शहरों में से 13 भारत में हैं. संगठन के मुताबिक वायु प्रदूषण से हृदय रोग, सांस संबंधी बीमारियों और कैंसर का गहरा नाता है. शिकागो-हावर्ड और येल विश्वविद्यालयों के अर्थशास्त्रियों ने भी यह बात कही है कि भारत में वायु प्रदुषण सुरक्षित मानकों से बहुत ज्यादा होता है. हवा में फैले जहरीले सूक्ष्म कण सांस के द्वारा शरीर में प्रवेश करते हैं, इससे कैंसर, पार्किंसन, हार्ट अटैक, सांस की तकलीफ़ जैसी गंभीर बीमारियों के खतरे के अलावा खांसी, आंखों में जलन, एलर्जी जैसी तकलीफें भी होती हैं. सूक्ष्म कण पदार्थ यानि पार्टिकुलेट मैटर ऐसे बारीक तत्व होते हैं जो आपकी सांस के साथ सांस की नली से दिल, फेफड़े, और दिमाग की कोशिकाओं में जाकर उन्हें बीमारी से ग्रसित कर देते हैं.

वायु प्रदुषण से होने वाली बीमारी का सबसे बड़ा कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रेजन जैसी गैस हैं. साथ ही कारों, बसों और ट्रकों से निकलने वाले धुएं के महीन कण भी बीमारियों का एक बड़ा कारण हैं. ये गैसे और कण आदमी के फेफड़ों के रास्ते रक्त में चले जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते हैं. यह मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है. हवा में मौजूद एलरजेन या रासायनिक तत्व सांस के रोग पैदा करते हैं. नाक, गले या फिर फेफड़ों में सूजन पैदा होना, फेफड़ों का दाह, दमा या ब्रोन्काइटिस जैसी सांस की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, सीओपीडी, आंख में जलन आदि प्रदूषित वायु से होने वाली बिमारियों के सबसे आम उदाहरण हैं.

वायु प्रदुषण से होने वाली बीमारी का सबसे बड़ा कारण कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी गैस हैं. साथ ही कारों, बसों और ट्रकों से निकलने वाले धुएं के महीन कण भी बीमारियों का एक बड़ा कारण हैं. ये गैसे और कण आदमी के फेफड़ों के रास्ते रक्त में चले जाते हैं और स्वास्थ्य के लिए खतरा बनते हैं. यह मानव शरीर पर बहुत बुरा प्रभाव डालता है. हवा में मौजूद एलरजेन या रासायनिक तत्व सांस के रोग पैदा करते हैं. नाक, गले या फिर फेफड़ों में सूजन पैदा होना, फेफड़ों का दाह, दमा या ब्रोन्काइटिस जैसी सांस की बीमारियां, स्किन की बीमारियां, सीओपीडी, आंख में जलन आदि प्रदूषित वायु से होने वाली बिमारियों के सबसे आम उदाहरण हैं.जो हवा से सांस के रूप में हमारे शरीर में जा रही है, इस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है. वायु प्रदुषण से होने वाली गंभीर बिमारियों से बचाव में यह बात सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा करती है. खांसी, छाती में दर्द, सांस लेते वक्त आवाज आना, दम फूलना, गले का दर्द भी दूषित हवा में सांस लेने के लक्षण हो सकते हैं. कमज़ोर दिल वालों के लिए वायु प्रदूषण और नुकसानदायक साबित होता है. हृदयाघात जो हृदय की मांसपेशियों के कमज़ोर और शरीर में रक्तसंचार में अक्षम होते जाने से होता है. वायु प्रदूषण के गंभीर दुष्परिणामों में से एक है. लंबे समय से इस तरह की दूषित हवा में सांस लेने से दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों की जान जाने का खतरा बहुत बढ़ जाता है. गर्मी बढ़ते ही शहर में वायु प्रदूषण भी बढ़ जाता है.

वायु प्रदुषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइ ऑक्साइड, मीथेन तथा नाइट्रस आक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. अचानक तापमान में हुई बढ़ोत्तरी से डायरिया, पेट दर्द, उल्टी, सिर दर्द, बुखार और बदन दर्द जैसी बीमारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है. ज्यादा गर्मी बढ़ने से त्वचा पर चकते और खुजली की शिकायत होने लगती है. अधिकांश लोगों को गर्मी में प्रदूषित हवा में धूल-मिट्टी की मात्रा बढ़ने से कई तरह की त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगती हैं. इसके अलावा भी कई तरह की एलर्जी लोगों को परेशान करती हैं. प्रदूषण तत्व गर्मी के मौसम में बढ़ जाते हैं. हवा में रेसपिरेबल पर्टिकुलेट सस्पेंडेड मैटर-आरएसपीएम की अधिक मात्रा स्वस्थ्य के लिए खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि इससे इससे सांस संबंधित कई बीमारियां जन्म लेती हैं.ऐसे में घर से बाहर निकलने पर मुंह और सिर ढक कर चलना चाहिए. धूप से त्वचा को बचाने के लिए सनस्क्रीन और आंखों को बचाने के लिए सनग्लास्सेस भी इस्तेमाल में लेने चाहिए.■

नाजी रॉकेट प्रोग्राम को फेल किया था

अरुण तिवारी
feedback@chauthiduniya.com

जेनी रूसो का जन्म 1 अप्रैल 1919 को हुआ था. द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने मित्र राष्ट्रों का साथ देने की ठानी थी. वे एक साहसी महिला थीं जिन्हें यह बात अच्छी तरह से मालूम थी कि दुश्मनों को कैसे परास्त किया जाता है. जब उन्होंने जर्मन सेनाओं के विरुद्ध काम करने की ठानी तो मित्र राष्ट्रों की तरफ से उकने लिए एक कोड नेम दिया गया जो कि प्रत्येक जासूस को दिया जाता था. उनका कोड नेम था एएमएनआईएआरआईएक्स. जेनी उन महिला जासूसों में शामिल थीं जो सीधे जर्मनी अधिकृत क्षेत्रों में पहुंच कर मित्र राष्ट्रों के लिए जासूसी कर रही थीं. ज्यादातर जासूसों का काम फ्रांस में कूरियर सर्विस का होता था. इस सर्विस के जरिये वे एक से दूसरे मित्र राष्ट्र के अधिकारी तक जानकारियां पहुंचाया करती थीं. लेकिन जेनी इन सब से अलग थीं. वे सीधे जर्मनी के जासूसों के बीच पहुंच गईं. उन्होंने सबसे पहले यही ठाना था कि वे जर्मनी के रॉकेट वेपन प्रोग्राम को रोकने का प्रयास करेंगी. इसके लिए उन्होंने यह पता करने की कोशिश की कि जर्मनी के जासूसों के बीच पैठ बनाई जाये. जर्मनी के जासूसों को उस समय गेस्टापो कहा जाता था. ये एजेंट हिटलर के लिए मित्र

विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों की बात करें तो जेनी ब्रिटेन की मदद कर पाने में आसानी से इसलिए कामयाब हो जाती थीं क्योंकि जेनी को कई भाषाओं जानकारी थी. जर्मन भाषा भी उनमें से एक थी. वह जर्मनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों तक किसी भी तरीके से पहुंच बनाती थीं. उन अधिकारियों से बातचीत किया करती थीं और महत्वपूर्ण जानकारियां ब्रिटेन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ करती थीं.

राष्ट्रों के विरुद्ध जासूसी किया करते थे. गेस्टापो जासूसों के बीच पहुंचना भी काफी कठिन काम था. जेनी ने ऐसा कर दिखाया था. वे गेस्टापों जासूसों से इस बात की जानकारी निकलवाया करती थीं कि जर्मनी का रॉकेट वेपन प्रोग्राम किस अवस्था पहुंचा है. उनकी इस रिपोर्ट को लंदन फारवर्ड किया गया. उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही ब्रिटिश सेनाओं ने पीनेमुंडे नामक जगह पर सीधे हमला किया था जहां पर जर्मन का रॉकेट प्रोग्राल रहा था. ब्रिटेन के इस हमले की वजह से जर्मन सेनाओं के इस प्रोग्राम में देरी हो गई. यहां चल रहे दोनों प्रोग्राम का नाम था वी1 और वी2. ब्रिटेन के इस हमले की वजह से हजारों लोगों की जान बच गई थी क्योंकि अगर यह रॉकेट प्रोग्राम जर्मनी पूरा कर लेता तो उस समय की परिस्थितियां ऐसी थीं कि जर्मनी उस रॉकेट का प्रयोग जरूर करता. इस रॉकेट के हमले से हजारों लोगों की जान जा सकती थी लेकिन जेनी के साहसिक कारनामे की वजह से ही हजारों लोगों की जान बच सकी थी. जेनी को पूरे ऑपरेशन के दौरान दो बार गिरफ्तार हुई थीं और तीन बार जर्मनी के प्रताड़ना गृह का सामना किया था. प्रताड़ना गृह में जेनी को बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी जाती थी.

हालांकि बाद में आर वी जोन्स ने इस पर रिसर्च किया था. उन्होंने इस बात की तस्दीक करने की कोशिश की थी कि क्या यह जेनी की ही रिपोर्ट थी जिसके आधार पर ब्रिटिश सेनाओं ने हमला किया था. उनकी रिसर्च में दो वर्जन सामने आए. एक तो कि जेनी ने रिपोर्ट की थी और दूसरा वर्जन यह था कि फ्रांस में मित्र राष्ट्रों के लिए काम कर रहा जासूसों का एक दल था जिसने ब्रिटेन को इस बात की जानकारी दी थी. अब इस घटना को लेकर दो वर्जन तो सामने आ गए लेकिन आर वी जोन्स ने भी जेनी वाले वर्जन को ज्यादा प्रमाणिक माना था.

विश्व युद्ध के शुरुआती दिनों की बात करें तो जेनी ब्रिटेन की मदद कर पाने में आसानी से इसलिए कामयाब हो जाती थीं क्योंकि जेनी को कई भाषाओं जानकारी थी. जर्मन भाषा भी उनमें से एक थी. वह जर्मनी के महत्वपूर्ण अधिकारियों तक किसी भी तरीके से पहुंच बनाती थीं. उन अधिकारियों से बातचीत किया करती थीं और महत्वपूर्ण जानकारियां ब्रिटेन तक पहुंचाने में कामयाब हुआ करती थीं. उन्हें 1941 में जर्मनी के जासूसों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें यह हिदायत देते हुए छोड़ दिया गया कि वे तटीय इलाकों में नहीं रहेंगी. लेकिन जेनी कहां मानने वाली थीं. वे तुरंत ही अपने जासूसी के काम में एक बार फिर सक्रिय हो गईं. वे पेरिस पहुंचीं. यहां से उन्होंने कई खुफिया रिपोर्ट ब्रिटिश अधिकारियों तक पहुंचाई थी.

जेनी के ब्रिटिश जासूसी दल को ज्वाइन करने की कहानी भी दिलचस्प है. जेनी लंदन में ट्रेन से यात्रा कर रही थीं. इस दौरान उनके एक सहयात्री से उनक परिचय हुआ. सौभाग्य से वे ब्रिटिश सेना के एक बड़े अधिकारी निकले. उन्होंने जेनी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें सेना के लिए काम करने का न्योता दिया जिसे जेनी ने तुरंत स्वीकार नहीं किया. जेनी ने काफी दिनों तक इस पर विचार करने के बाद उस अधिकारी को फोन किया और कहा कि मैं सेना के लिए काम करने के लिए तैयार हूं. जैसे ही सेना के कुछ अधिकारी जेनी से मिले तो उन्हें इस बात की जानकारी मिली कि जेनी को कई भाषाओं की जानकारी है तो उन्होंने ने जेनी को जासूसी का काम सौंपा.

जेनी ब्रिटेन की सबसे अच्छी जासूसों में शुमार की जाती हैं. उन्होंने यह दिखा दिया कि आखिर कैसे दुश्मनों के कैंप में घुसकर नाजी जैसी सेना के भी छक्के छुड़ाए जा सकते हैं. अपने पूरे जासूसी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपना एक भी टारगेट फेल नहीं होने दिया. जेनी को जासूसी की दुनिया में हमेशा याद रखा जाएगा.■

चौथी दुनिया
CHAUTHI DUNIYA
चौथी दुनिया की हर खबर अब आपके Android फोन पर भी उपलब्ध,
Play Store से Download करें | CHAUTHI DUNIYA APP |

दक्षिण अफ़्रीका में विदेशियों पर हमले

शफ़ीक आलम

दक्षिण अफ़्रीका की राजधानी जोहांसबर्ग के टाउनशिप अलेक्सेंड्रा में 18 अप्रैल की सुबह अफ़्रीकी देश मोजाम्बिक के नागरिक इम्मानुएल सिथोले कहीं जा रहे थे. यह मालूम नहीं है कि उन्हें दक्षिण अफ़्रीका में विदेशियों के खिलाफ चल रही हिंसा का ज्ञान था या नहीं, लेकिन उनके साथ जो हुआ, उससे पूरी दुनिया इस देश में चल रही हिंसा की गंभीरता से अवगत जरूर हो गई. वाक्या कुछ यों था कि इम्मानुएल को चार–पांच लोगों ने घेर कर उनपर ताबड़तोड़ हमला बोल दिया. एक हमलावर ने उन पर चाकू से वार किया और इम्मानुएल वहीं गिर गए. इस घटना के गवाह बने स्थानीय फोटोग्राफर जेम्स ओटवे. जेम्स ने अपने कमरे में इस पूरी घटना को क़ैद कर लिया और जब हमलावर वहां से चले गए, तो एक अन्य राहगीर की मदद से उन्होंने इम्मानुएल को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान इम्मानुएल की मृत्यु हो गई.

विदेशियों का खौफ, विदेशियों से घृणा या जेनोफोबिया दक्षिण अफ़्रीका के लिए कोई नया नहीं है. रंगभेदी सरकार के समय भी और रंगभेद की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना के बाद भी दक्षिण अफ़्रीका में विदेशियों के साथ रंगभेदी हमले होते रहे हैं. दरअसल, दक्षिण अफ़्रीका एक बहुसंस्कृतिवादी देश रहा है. यहां कई अफ़्रीकी कबीलों के साथ–साथ भारत समेत दुनिया के कई देश के लोग ब्रिटिश उपनिवेशवाद के समय से बसते या बसाये जाते रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ चूंकि दक्षिण अफ़्रीका एक तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, इसलिए अफ़्रीकी देशों से बड़ी संख्या में लोग यहां नौकरी या रोजागर की तालाश में आने लगे हैं, जिसके कारण यहां के मूल निवासी यह समझने लगे हैं कि ये प्रवासी लोग उनका हक मार रहे हैं. इसी वजह से वर्ष 2000 से 2008 के बीच इस तरह के हमलों में 60 से अधिक लोग मारे गए थे. केवल मई 2008 में ही विदेशियों के विरुद्ध दंगों में 62 लोग मरे गए थे, जिसमें 21 दक्षिण अफ़्रीकी नागरिक भी शामिल थे. इसी साल जनवरी महीने में जोहांसबर्ग में विदेशियों के खिलाफ हिंसा फैल गई थी, लेकिन सुरक्षा बालों ने त्वरित कार्रवाई करके इसे फैलने से रोक लिया था. बहरहाल, दक्षिण अफ़्रीका एक बार फिर विदेशियों के प्रति खौफ या घृणा से प्रेरित दंगों के चंगुल में है और इस बार भी पिछले हमलों की तरह जो लोग प्रभावित हुए हैं, वे अफ़्रीकी देशों के अश्वेत लोग हैं. ये वे लोग हैं, जो नौकरी की तलाश में या व्यापार करने के उद्देश्य से इस देश में आए थे. गौरतलब है कि दक्षिण अफ़्रीका में विदेशियों की संख्या 20 लाख के आसपास बताई जाती है. चूंकि दक्षिण अफ़्रीकी सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, देश में बेरोज़गारी दर 25 प्रतिशत तक पहुंच गई है और इस बेरोज़गारी का सबसे अधिक शिकार देश के अश्वेत लोग हैं. वो यह समझते हैं कि उनकी बेरोज़गारी की वजह अफ़्रीकी देशों से आए हुए लोग हैं, जो उनकी नौकरी चट कर जा रहे हैं. इसीलिए एक हलकी सी चिंगारी उनके अन्दर के आग को भड़काने के लिए काफी है. लिहाज़ा, देश में पिछले कुछ हफ़्तों से चल रहे विदेशियों के खिलाफ हमले की शुरुआत कथित रूप से ज़ुलू कबीले के पारंपरिक राजा गुडविल ज्वेलिथिनी के पिछले महीने दिए गए भड़काऊ भाषण से हुई थी. इस भाषण में उन्होंने देश में हो रही हिंसा के लिए विदेशियों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन्हें देश से चले जाने का फरमान जारी किया था. हालांकि बाद में किंग गुडविल ने अपनी बात को तोड़–मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगया है, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.

ज़ुलू राजा के कथित भड़काऊ भाषण के बाद पिछले कई हफ़्तों से इस देश के कई बड़े शहर हिंसा के चपेट में हैं, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र ज़ुलू–नटाल प्रान्त और गोटेंग प्रान्त हैं. अब तक की ख़बरों के मुताबिक, इस हिंसा में कम से कम 7 लोग मारे गए हैं और 5000 से ज़्यादा बेघर हुए हैं. विदेशी नागरिकों की कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया है. बहुत सारे लोग शरणार्थी कैम्पों में चले गए हैं. हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिंसा से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सेना को तैनात करना पड़ा है. रक्षा मंत्री नोसिवीवे म्पीसा–नकालुका ने एक बयान जारी करके कहा कि ज़ुलू–नटाल प्रान्त में सेना भेजी जा रही है और जोहांसबर्ग में सेना तैनात कर दी गई है. राष्ट्रपति जैकब जुमा ने इन हमलों कि निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का यकीन दिलाया है, लेकिन अफ़्रीका के वो देश, जिनके नागरिक इन हमलों से प्रभावित हुए हैं, वो इसे हलके में नहीं ले रहे हैं. नाइजीरिया और मोजाम्बिक समेत कई देशों ने ज़ुलू राजा से अविलम्ब माफ़ी की मांग की है और सरकार से हिंसा रोकने के लिए क़दम उठाने को कहा है. साथ ही कई देशों में दक्षिण अफ़्रीका के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं. दक्षिण अफ़्रीकी सरकार ने कई देशों में अपने वाणिज्य दूतावास बंद कर दिए हैं और चीन जैसे कई देशों ने अपने नागरिकों को दक्षिण अफ़्रीका नहीं जाने की सलाह दी है.

बहरहाल, इन घटनाओं का दक्षिण अफ़्रीका के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से असर पड़ेगा. चूंकि यह देश तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सामने आया है और अफ़्रीका महाद्वीप में विकास के ऊंचे दर को हासिल करने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं, इसलिए दक्षिण अफ़्रीका के पास भी अफ़्रीकी देशों में पूंजी निवेश का बड़ा मौक़ा है. ऐसे में अगर उसके रिश्ते दूसरे अफ़्रीकी देशों से ख़राब हो जाते हैं, तो उससे बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है. विदेशियों पर हमलों से एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर ये हिंसा होती ही क्यों है? ऐसा नहीं है कि यह स्थिति केवल दक्षिण अफ़्रीका में ही है. दुनिया के दूसरे देशों में भी ज़ेनोफोबिया के मामले सामने आ रहे हैं. हैरानी की बात तो यह है कि इसमें अमेरिका से लेकर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे विकसित देश भी शामिल हैं. एक वैश्वीकृत (ग्लोबलाइज) दुनिया में ऐसी घटनाएं चिंता का विषय हैं और वैश्वीकरण के मूल सिद्धांतों के विपरीत हैं. जब आप दुनिया के बाजारों को एक बड़ा साझा बाज़ार मान रहे हैं, तो किसी देश में काम करने वाले देशी और विदेशी को अलग तरीके से क्यों बांटा जाता है? इससे यह भी ज़ाहिर होता है कि किसी देश में अगर किसी वजह से बेरोज़गारी दर में वृद्धि होगी, तो वहां काम कर रहे विदेशी नागरिक सबसे आसान निशाना होंगे. इसलिए इस मसले पर सरकारों को गंभीरता से ध्यान देना चाहिए.■

feedback@chauthiduniya.com

अंगारे पर बैठा मध्य-पूर्व

वसीम अहमद

मध्य–पूर्व में इस समय जिस प्रकार का संकट छाया है, उससे छुटकारा पाने के लिए फिलहाल कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है. खाड़ी के सभी देश किसी न किसी रूप में युद्ध जैसे हालात का सामना कर रहे हैं. कुछ प्रत्यक्ष रूप से जंग में शामिल हैं, तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से इसका हिस्सा बने हुए हैं. क्षेत्र में शक्ति और शस्त्रों का असंतुलन तेज़ी से बढ़ रहा है. मध्य–पूर्व में एक ओर ईरान अपने प्रभुत्व के लिए शक्ति प्रदर्शन कर रहा है, तो दूसरी ओर सउदी अरब और उसके सहयोगी अपना दबदबा खोना नहीं चाहते. शक्ति और प्रभुत्व की इस जंग में दुनिया की दो बड़ी ताक़तें अमेरिका और रूस अपने–अपने समर्थकों को मज़बूत करने की दिशा में काम कर रही हैं. रूस ईरान को आधुनिक वायु रक्षा सिस्टम देने पर सहमत है, तो अमेरिका अरब सहयोगियों को आधुनिक हथियारों से लैस कर रहा है. होसी के ख़िलाफ़ अरब सहयोगियों में सउदी अरब, यूएई, क़तर, बहरीन और मिस्र शामिल हैं. इनसे हथियार बेचने के लिए अमेरिकी हथियार के सप्लायरों ने अरब देशों से अरबों डॉलर कमाने के लिए अपने कार्यालय मध्य–पूर्व में खोल लिए हैं. हथियारों की यह ख़रीद–फरोख़्त निश्चित ही इलाके को जंग की स्थिति में रखने के लिए मददगार होगी. रक्षा उपकरणों के कारोबारी विश्लेषक और मध्य पूर्व के जानकार कहते हैं कि क्षेत्र में संकट छाया है और एक धार्मिक वर्ग दूसरे पर प्रभुत्व चाहता है, जिस कारण रक्षा कारोबार में हाईटेक और हार्डवेयर का इज़ाफ़ा होगा. मध्य–पूर्व के सभी देश हथियार ख़रीदने के मामले में एक–दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में लगे हुए हैं. अंतर्राष्ट्रीय पीस रीसर्च इंस्टीटयूट (एसआईपीआर) के अनुसार, सउदी अरब और यूएई दुनिया के चौथे और पांचवे सबसे बड़े हथियारों के ख़रीदार बन गए हैं. इसके अलावा खाड़ी के अन्य देशों में भी शस्त्र ख़रीदारी के रूझान में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है. वैश्विक अर्थव्यवस्था पर विवेचना करने वाली संस्था आईएचएस रिपोर्ट के अनुसार, हथियारों के कारोबार में रिकॉर्ड बढ़ोतरी का कारण, मध्य–पूर्व और प्रशांत महासागर में बढ़ता हुआ तनाव है. क़तर भी क्षेत्र में प्रभाव बनाना चाहता है. उसने बोइंग कंपनी से हेलीकॉप्टर, पीटरयाट और एयर डिफेंस सिस्टम के अलावा अन्य अमेरिकी कंपनियों से भारी मात्रा में हथियारों की ख़रीद का समझौता किया है. हथियार बनाने वाली कंपनियां क़तर में अपने कार्यालय बना रही हैं. क़तर में बोइंग ने 2011 में अपना एक ऑफिस बनाया था और इस साल लॉक हीड मार्टिन ने वहां अपना कार्यालय बनाया है. हथियारों की यह ख़रीदारी और हथियार बनाने वाली कंपनियों की मध्य–पूर्व में बढ़ती रुचि से संकेत मिलते हैं कि यहां के हालात ठीक नहीं हैं और निकट भविष्य में यह क्षेत्र युद्ध की पस्थितियों से बाहर निकल नहीं पाएगा.

वर्तमान युद्ध, जो सउदी अरब और यमन में हो रहा है, इस जंग को लेकर ईरान नाराज़ है. ईरान बार–बार सउदी अरब और उसके सहयोगियों को धमकी दे रहा है कि अगर उसने यमन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं रोका, तो वह सउदी अरब को जवाब देगा. यह स्थिति मध्य–पूर्व को आग का गोला बना सकती है. ईरान अगर प्रत्यक्ष रूप से इस लड़ाई में भाग लेता है तो निश्चित रूप से क्षेत्र दो सम्प्रदायों के विवाद में उलझ जाएगा. यानी शिया और सुन्नी एक दूसरे के आमने–सामने होंगे और यह लड़ाई लंबी भी हो सकती है. राजनीतिक जानकार तो यहां तक कहते हैं कि अगर यमन में होसियों पर सउदी अरब का हमला रुक जाए, तो भी क्षेत्र में प्रभुत्व बनाने के लिए सउदी अरब और ईरान के बीच शीत युद्ध जारी रहेगा और यह शीत युद्ध साम्प्रदायिक आधार पर होगा.

मध्य–पूर्व में अभी कई सालों तक युद्ध की स्थिति बरक़रार रहेगी, चाहे यह स्थिति वर्तमान सैन्य हमले के रूप में हो या ईरान और सउदी अरब के बीच के शीत युद्ध के रूप में. इसके अलावा एक संवेदनशील मसला है, जो मध्य–पूर्व के लिए निरंतर ख़तरा बना हुआ है और वह है क़तर का इस्लामी कट्टरपंथी समूहों के लिए नरमपंथी व्यवहार रखना. खाड़ी देशों में क़तर एकमात्र ऐसा देश है, जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाए जाने वाले इस्लामी समूहों के प्रति नरम रुख़ रखता रहा है. सूडान से प्रकाशित होने वाला एक अरबी अख़बार लिखता है कि जिस समय सउदी अरब इख़्वान समूह को आतंकवादी समूह बताने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा था, उस समय क़तर ने विरोध किया था, लेकिन इसके विरोध के बावजूद उख़्वान को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह क़रार दे दिया गया. इसके बाद क़तर ने हालांकि उख़्वानियों को अपने यहां कार्यालय खोलने की अनुमति नहीं दी, लेकिन उख़्वान के कड़े समर्थक प्रसिद्ध धर्मगुरु यूसुफ़ क़रज़ावी को अपने यहां शरण दी. क़रज़ावी ने वहां उख़्वानी चिंतन पर आधारित कई इस्लामी केन्द्र स्थापित किए. यही नहीं, अलजज़ीरा चैनल पर अलशरिया वलहियात के नाम से उनका अधिकारिक रूप से एक प्रोग्राम प्रसारित किया जाता था, जिस पर सउदी अरब ने कड़ी आपत्ति भी की, लेकिन क़तर ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया. यूसुफ़ क़रज़ावी मिस्र सरकार को उख़्वान समर्थन के कारण से वांछित हैं. मिस्र से प्रकाशित होने वाला एक अरबी अख़बार अलयौम ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसके अनुसार सउदी अरब और कुछ अन्य अरब देशों के दबाव में क़तर ने अपने यहां शरण लिए हुए जिन 7 उख़्वानी प्रतिनिधियों के निष्कासन का निर्णय लिया था, बाद में इस फैसले को वापस ले लिया. इन 7 प्रतिनिधियों में उख़्वान के दो सक्रिय प्रतिनिधि जमाल अब्दुल सत्तार और अस्साम तस्लीमा और संगठन के महासचिव महमूद हुसैन भी शामिल थे. यह स्थिति अरब स्प्रिंग के बाद की ही नहीं है, बल्कि क़तर में उख़्वानियों की जड़ें बहुत पुरानी हैं. आठवें दशक में क़तर से एक पत्रिका अलउम्मा नाम से प्रकाशित होती थी. इसके संपादक एक उख़्वानी अमर उबैद हस्ना थे. इस पत्रिका में उख़्वानी चिंतन का प्रतिनिधित्व किया जाता था, लेकिन यह पत्रिका अब बंद हो चुकी है. उख़्वानियों के प्रति नरम रुख़ रखने के अलावा क़तर पर मूरीतानिया में इस्लामी समूहों को सहायता पहुंचाने का भी आरोप लगता रहा है.

यह परिस्थितियां बता रही हैं कि उख़्वान को क़तर में वैध दर्जा प्राप्त न होने के बावजूद इसके समर्थकों की भारी संख्या मौजूद है. यही वे तथ्य हैं, जिस कारण कहीं न कहीं यह संशय पैदा होता है कि क़तर में यह इस्लामी कट्टरपंथी वही रास्ता अपना सकते हैं, जो मिस्र में अपनाया गया था. अलउख़्वान ने जमालअब्दुल नासिर से लेकर अनवर सादात तक और फिर होस्नी मुबारक के दौर में बेहद ख़ामोशी से अपनी जड़ें मज़बूत कीं और जैसे ही क्षेत्र में अरब स्प्रिंग का तूफान आया, तो उसने अपना शक्ति प्रदर्शन करके सरकार पर अपना क़ब्ज़ा कर लिया. अब अगर क़रज़ावी जैसे लोग देश में अपनी गतिविधियां चला रहे हैं, तो निश्चित ही उनकी जड़ें भी मज़बूत हो रही होंगी और जैसे ही मौक़ा मिलेगा, वह मिस्र में उख़्वानियों और यमन में होसियों की तरह क्रांति ला सकते हैं.

ख़ैर, अरब देशों के बीच हथियारों की ख़रीदारी की होड़ और खाड़ी क्षेत्रों में ईरानी हस्तक्षेप क़तर का इस्लामी कट्टरपंथियों के प्रति नरम रुख़ रखना. ये सभी चीज़ें संकेत दे रही हैं कि मध्य–पूर्व में निकट भविष्य में युद्ध स्थितियों से बाहर निकल नहीं पाएगा.■

feedback@chauthiduniya.com

कर्म और भाग्य तीसरी बार आए तो उन्होंने भिखारी को फिर भीख मांगते देखा. भाग्य को बड़ा क्रोध आया. बोला, कितना भी भला कर लो, यह दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा! लेकिन इस बार कर्म के मन में दया आ गई. वह भिखारी से बोला–हट्टे–कट्टे हो, तुम कोई काम क्यों नहीं करते? भीख मांगकर कब तक गुजारा चलेगा? भिखारी बोला–काम–धंधे के लिए पास में कुछ पैसे भी तो हों!' कर्म ने कहा–देखो, मैं तुम्हें एक ठेली फल देता हूं. तुम इन्हें बेच कर धंधा करो.

सुख और शान्ति प्रदान करते हैं साईं

चौथी दुनिया ब्यूरो

एक समय एक भक्त, जिनका नाम पंत था और जो एक अन्य सदगुरु के शिष्य थे, उन्हें शिरडी पधारने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. उनकी शिरडी आने की इच्छा तो न थी, परन्तु मेरे मन कछु और है, विधिना के कुछ और वाली कहावत चरितार्थ हुई. वे रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे, जहां उनके बहुत से मित्र व सम्बन्धियों से अचानक ही भेंट हो गई, जो कि शिरडी यात्रा को ही जा रहे थे. उन लोगों ने उनसे शिरडी तक साथ–साथ चलने का प्रस्ताव किया. पंत यह प्रस्ताव अस्वीकार न कर सके. तब वे सब लोग बम्बई में उतरे और इसी बीच पन्त विरार में उतर अपने सदगुरु से शिरडी प्रस्थान करने की अनुमति लेकर तथा आवश्यक खर्च आदि का प्रबन्ध कर, सब लोगों के साथ रवाना हो गये. वे प्रातःकाल वहां पहुंच गये और लगभग 11 बजे मस्जिद को गये. वहां पूजनार्थ भक्तों का एकत्रित भीड़ देख सब को अति प्रसन्नता हुई, परन्तु पन्त को अचानक ही मूर्च्छा आ गई और वे बेसुध होकर वहीं गिर पड़े. तब सब लोग भयभीत होकर उन्हें स्वस्थ करने के समस्त उपचार करने लगे. बाबा की कृपा से और मस्तक पर जल के छींटे देने से वे स्वस्थ हो गये और ऐसे उठ बैठे, जैसे कि कोई नींद से जगा है. बाबा ने यह सब जानकर कि यह अन्य गुरु का शिष्य है, उन्हें अभय–दान देकर उनके गुरु में ही उनके विश्वास को दृढ़ करते हुए कहा कि कैसे भी आओ, परन्तु भूलो नहीं, अपने ही स्तंभ को दृढ़तापूर्वक पकड़कर सदैव स्थिर हो उनसे अभिन्नता प्राप्त करो. पन्त तुरन्त इन शब्दों का मतलब समझ गये और उन्हें उसी समय अपने सदगुरु की स्मृति हो आई. उन्हें बाबा के इस अनुग्रह की जीवन भर स्मृति बनी रही. इसी प्रकार बाबा के एक दूसरे भक्त श्री. गोपाल नारायण आंबडेकर बाबा के परम भक्तों में से एक थे, जो ठाणे जिला और आबकारी विभाग में दस वर्षों से कार्य करते थे. वहां से सेवानिवृत्त होने पर उन्होंने अन्य नौकरी ढूंढ़ी, परन्तु वे सफल न हुए. तब उन्हें दुर्भाग्य ने चारों ओर से घेर लिया, जिससे उनकी

यह सामयिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आम्बडेकर को महान आश्चर्य हुआ. यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणान्त ही हो गया होता. बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गये.

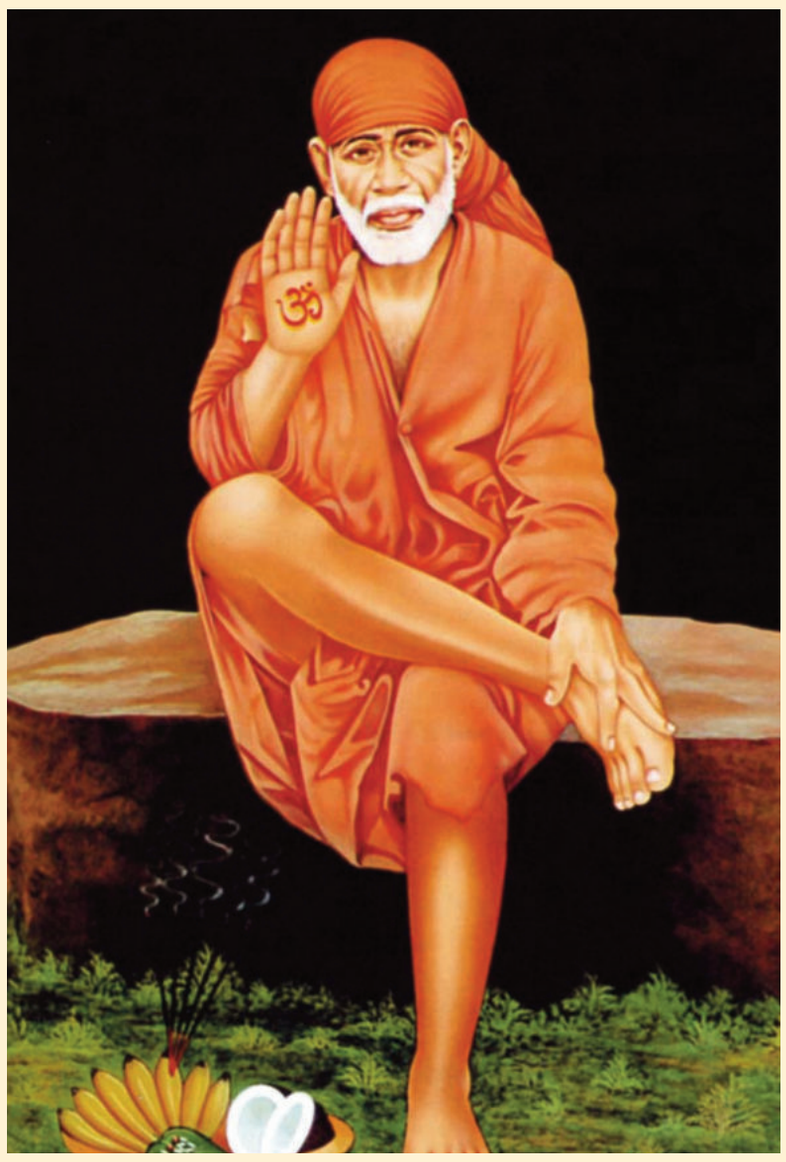

आर्थिक स्थिति और भी अधिक दयनीय हो गई. ऐसी परिस्थिति में उन्होंने सात वर्ष व्यतीत किये. वे प्रति वर्ष शिरडी जाते और अपनी दुःखदायी कथा वार्ता बाबा को सुनाया करते थे. सन् 1916 में तो उनकी स्थिति और भी अधिक चिन्ताजनक हो गई. तब उन्होंने शिरडी जाकर आत्महत्या करने की ठानी. इसलिये वे अपनी पत्नी को साथ लेकर शिरडी आये और वहां दो मास तक ठहरे. एक रात्रि को दीक्षितवाड़े के सामने एक बैलगाड़ी पर बैठे–बैठे उन्होंने कुएं में गिर कर प्राणान्त करने का और साथ ही बाबा ने उनकी रक्षा करने का निश्चय किया. वहीं समीप ही एक भोजनालय के मालिक श्री. सगुण मेरु नायक ठीक उसी समय बाहर आकर उनसे इस प्रकार वार्तालाप करने लगे कि क्या आपने कभी श्री अक्कलकोट महाराज की जीवनी पढ़ी है. सगुण से पुस्तक लेकर उन्होंने पढ़ना प्रारम्भ कर दिया. पुस्तक पढ़ते–पढ़ते वे एक ऐसी कथा पर पहुंचे, जो इस प्रकार थी–श्री अक्कलकोटकर महाराज के जीवन काल में एक व्यक्ति असाध्य रोग से पीड़ित था. जब वह किसी प्रकार भी कष्ट सह न सका तो वह बिलकुल निराश हो गया और एक रात्रि को कुएं में कूद पड़ा. तत्क्षण ही महाराज वहां पहुंच गए और उन्होंने स्वयं अपने हाथों से उसे बाहर निकाला. वे उसे समझाने लगे कि तुम्हें अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य ही भोगना चाहिए. यदि भोग अपूर्ण रह गया तो पुनर्जन्म धारण करना पड़ेगा, इसलिये मृत्यु से यह श्रेयस्कर है कि कुछ काल तक उन्हें सहन कर पूर्व जन्मों के कर्मों का भोग समाप्त कर सदैव के लिये मुक्त हो जाओ.

यह सामयिक और उपयुक्त कथा पढ़कर आम्बडेकर को महान आश्चर्य हुआ. यदि इस कथा द्वारा उन्हें बाबा का संकेत प्राप्त न होता तो अभी तक उनका प्राणान्त ही हो गया होता. बाबा की व्यापकता और दयालुता देखकर उनका विश्वास दृढ़ हो गया और वे बाबा के परम भक्त बन गये. उनके पिता श्री अक्कलकोटकर महाराज के शिष्य थे और बाबा की इच्छा भी उन्हें उन्हीं के पद–चिन्हों का अनुसरण कराने की थी. बाबा ने उन्हें आर्शीवाद दिया और अब उनका भाग्य चमक उठा. उन्होंने ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन में निपुणता प्राप्त कर उसमें बहुत उन्नति कर ली और बहुत–सा धन अर्जित करके अपना शेष जीवन सुख और शान्तिपूर्वक व्यतीत किया. ■

feedback@chauthiduniya.com

साईं के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुःख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वही नहीं है दूर.
10. मुझमें लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य-धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

साईं भक्तों!

आप भी चौथी दुनिया को साईं से जुड़ा लेख या संस्मरण भेज सकते हैं. मसलन, साईं से आप कब और कैसे जुड़े. साईं की कृपा आपको कब से मिलनी शुरू हुई. आप साईं को क्यों पूजते हैं. कैसे बने आप साईं भक्त. साईं बाबा का जीवन और चरित्र आपको किस तरह से प्रेरित करता है. साईं बाबा के बारे में अनेक किंवदंतियां हैं, क्या आपके पास भी कुछ कहने के लिए है? अगर हां, तो केवल 500 शब्दों में अपनी बात कहने की कोशिश करें और नीचे दिए गए पते पर भेजें.

चौथी दुनिया
एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर), उत्तर प्रदेश, पिन–201301
ई–मेल feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

यूपी सरकार का रिपोर्ट कार्ड

अखबारों में पूर पेज का विज्ञापन छपवाकर यूपी सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है. उसका दावा है कि उसने जनता से किए अपने सभी वादे पूरे कर दिए हैं. लेकिन अधिकांश लोगों की धारणा इसके विपरीत है. राज्य सरकार ने बेसिक स्कूलों में रिक्त पदों पर नियुक्तियां अभी तक पूरी नहीं की है. लोक सेवा आयोग और पुलिस भर्ती में सजातियों की नियुक्तियां करने में रिकार्ड तोड़ दिए हैं. स्वजाति को छोड़ पिछड़ी जातियों की भी यह सरकार हितैषी नहीं है. सरकार को बताना चाहिए कि तीन वर्षों में कितनी विद्युत इकाइयों की स्थापना की है. समूचा प्रदेश, बिजली कटौती से जूझ रहा है, लेकिन सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है. डीजल और पेट्रोल पर सर्वाधिक वैट यूपी में है. केन्द्र ने तेल के दाम 15 रूपये प्रति लीटर तक कम कर दिए हैं, लेकिन क्या सरकार ने किराओं में एक भी रूपये की कमी की है? निर्माण में 20 प्रतिशत की लागत वाली सड़के बनाकर तिजोरियां भरी जा रही हैं. सरकार न तो पिछले वर्ष गन्ने का भुगतान समय से दिला पाई और न ही इस वर्ष. क्या यही लोक कल्याणकारी सासन के लक्षण हैं?
–राजकिशोर पांडेय, लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश.

जनकल्याण के लिए राजनीति हो

पिछले एक वर्ष में लोगों की लोकतंत्र में बढ़ती भागीदारी यह दर्शाती है कि देश के लोगों की लेकतंत्र के प्रति बेहद गहरी आस्था है. इसके साथ ही लोग जनतंत्र को मजबूत करने को लेकर जागरूक भी हुए हैं. पिछले चुनावों में भारी मतदान निश्चित ही एक सकारात्मक संकेत है. देश में सरकारी तंत्र के काम में सुधार दिख रहा है और सरकारी कार्यालयों के काम करने की गति काफी बढ़ी है, लेकिन उनमें सुधार की गुजांइश बरकरार है. व्यापक सूचना एवं बेहतर सुविधा वाला तंत्र विकसित किया जाना वक्त की मांग है. आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए मानव संसाधन के अलावा उच्च स्तरीय ज्ञान और कुशलता की आवश्यकता होगी. देश के तथाकथित नेताओं को न केवल आवाम की आवाज सुननी होगी बल्कि उन्हें लोगों को शिक्षित और सामाजिक कार्यो के लिए प्रेरित करना होगा. हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां लोग एक दूसरे से भयभीत न रहें. राष्ट्रभाषा, संविधान और संसदीय परंपरा के प्रति लोगों की आशा बढ़ी है. राजनीति को एक बार फिर जलकल्याण के लिए आगे आना होगा और विरोध का उद्देश्य भी राष्ट्रहित के लिए होना चाहिए.
–अशोक कुमार निर्मोही, दरभंगा, बिहार.

दिल को झूती कविता

उधार मागने आया दोस्त यह एक खूबसूरत कविता है जो कभी एक साल में एक बार पढ़ने को मिलती है. कृपया ऐसी दिल को झू जाने वाली सामग्री हमेशा प्रकाशति करते रहें. कविता में जो संवेदना है वो आज कल कवियों की पूरी किताब में नहीं दिखाई देती. इनकी और कविताएं पढ़ाएं.
–सुनील कुमार, मिर्जापुर, उत्तरप्रदेश.

नारी सम्मान की बात कहां गई!

भाजपा के नेता भारतीय संस्कृति, मर्यादा, नारी का सम्मान करना शायद भूल चुके हैं. सत्ता सुख में मस्त व्यस्त उन्मादी स्थिति में भाजपाई अपने भाषणों द्वारा विकृत मानसिकता का परिचय दे रहे हैं. भारत-रत्न मदर टरेसा, कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी को अपमानित करने वाले यह भाजपा का समूह अब अपने ही समूह के लोगों को भी अपमानित करने से नहीं छोड़ रहा है. केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अश्लील फोटो को भाजपा के साथ जुड़े दल लोजपा के मनचले नेताओं ने वॉटसऐप पर तथा सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर समस्त देश की नारी जाति का अपमान किया है. भाजपा, लोजपा की इस तरह की वारदात देश की नारी जाति के प्रति उनकी गिरी हुई मानसिकता को दर्शाता है. माननीय प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को नारी की अस्मिता के खातिर कड़े रूख अख्तियार करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए.
–निर्भय अम्बेडकर, ई–मेल के द्वारा.

राहुल गांधी रिटर्न्स

राहुल गांधी 58 दिन की छुट्टी से वापस आने के बाद जो तेवर अपनाए वह देखने लायक था. पहले दिल्ली में किसानों से मिले, उसके बाद किसान रैली में शामिल हुए और संसद में सरकार पर जमकर प्रहार किया. बरबाद हो चुके गेंहू की बालियां और तख्तियां लिए हुए किसान भारी मात्रा में राहुल से मिलने पहुंचे. राहुल ने किसानों से कहा कि मैं इस दुख के समय में आपके साथ हूं. लेकिन वह किसानों की मौत पर भी राजनीति करते नजर आए. वहीं नहीं सभी पार्टियां किसानों के मौत पर राजनीति करने से नहीं चुक रही हैं. किसानों की आत्महत्या करने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. राजनाथ सिंह कृषि बीमा मसौदे पर पुनः काम करने की बात कर रहे हैं. राम विलास पासवान ने कहा है कि हम 50 फीसद कम चमक वाला गेहूं भी खरीदने को तैयार हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही मुआवज़े की राशि डेढ़ गुना बढ़ा चुके हैं पर इन सारी चीज़ों से कोई फर्क पड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा है. किसानों की मौत की संख्या में इससे कोई कमी आती नहीं दीख रही है. किसान आक्रोशित भी हैं और तकलीफ में भी. मुआवजों की घोषणाएं और नेताओं के आश्वासन अन्नदाता को आत्महत्या जैसे गंभीर कदम उठाने से नहीं रोक पा रहे हैं. सरकार को चाहिए कि किसानों से अपील करे कि वे आत्महत्या न करें, सरकरा उनकी हर संभव मदद करेगी.
–पुनीत पाराशर, ई–मेल के द्वारा.

वीर कुंवर सिंह की याद में ...

80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था,
सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था.

ये पंक्तियां 1857 देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के अमर सेनानी आरा के बाबू कुंवर सिंह के बारे कही गई हैं, जिन्हें लोग प्यार से तेगवा बहादुर भी कहते हैं. उनके बारे में लॉर्ड ट्रेवेलियन ने कहा था कि 1857 के समय कुंवर सिंह 80 वर्ष के थे, यदि उस वक्त जवान होते तो बहुत संभावना थी कि अंग्रेजों को 1857 में ही भारत छोड़ना पड़ता. यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि हम अपने वीर शहीदों को वो सम्मान नहीं दे पाये जिसके वो हक़दार हैं. इसलिए वीर कुंवर सिंह जैसे बहादुर जाबांजों की लोगों को याद दिलाने के लिए वीर कुंवर सिंह फाउंडेशन लगातार प्रयासरत है. पिछले 17 वर्षों से फाउंडेशन राजधानी दिल्ली में वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव समारोह आयोजित करता आ रहा है.

इसी कड़ी में फाउंडेशन ने 23 अप्रैल को दिल्ली के तीन मूर्ति भवन सभागार में 158 वें वियजोत्सव समारोह का आयोजन किया. इस मौके पर 1857 के अन्य वीर शहीदों को भी याद किया गया. कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व राज्यपाल भीष्म नारायण सिंह ने की. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे. राजनाथ सिंह ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि वीर कुंवर सिंह ने देश के मान–सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहूति दे दी. 80 बरस की उम्र में इस तरह की देशभक्ति का जज्बा उनके अलावा और किसी में नज़र नहीं आया. फाउंडेशन के अध्यक्ष निर्मल सिंह ने इस मौके पर भारत सरकार से कुंवर सिंह की याद में सिक्का और डाक टिकट जारी करने की मांग की. साथ ही उनकी स्मृति में स्मारक बनवाने और दिल्ली में उनके नाम से सड़क का नामकरण करने का अनुरोध किया. उनकी मांगों पर गृह मंत्री ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया.

वीर कुंवर सिंह केवल बिहार तक सीमित नहीं थे. उन्होंने बिहार की सीमा से बाहर जाकर

मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर अंग्रेजों से लोहा लिया था, उन्होंने सोनपुर मेले का इस्तेमाल विद्रोहियों को एकत्र करने और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की योजना बनाने में किया था. भारत के इतिहासकारों ने उन्हें इतिहास में वो जगह नहीं दी जिसके वो हक़दार थे. सिर्फ चर्बी वाली कारतूस में इतना दम नहीं था जो इतनी बड़ी क्रांति की वजह बनता और सिर्फ यह कहकर कि वो सिर्फ खोई हुई ज़मीदारी को वापस लाने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, ऐसा कहना इस वीर योद्धा के साथ ज्यादती है. ■

feedback@chauthiduniya.com

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने स्वतंत्र विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया, एफ.2, सेक्टर-11, नोएडा (उत्तर प्रदेश) पिन-201301

कला बना साहित्य का बाज़ार

अनंत विजय

हिंदी साहित्य में यह बात हमेशा से कही और सुनी जाती रही है कि कोई सिर्फ़ साहित्य लिखकर अपना जीवनयापन नहीं कर सकता. यह बात बहुत हद तक सही भी है, क्योंकि हिंदी साहित्य में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि किसी लेखक ने सिर्फ़ साहित्य रचकर अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से जी हो. हिंदी लेखकों की ऐसी छवि सायास निर्मित की गई कि वह बेचारा होता है. उनकी किताबों से होने वाली आय पर भी कई बार बात होती रही है. कॉपीराइट को लेकर प्रकाशकों एवं लेखकों के अपने-अपने पक्ष हैं. प्रकाशकों का कहना है कि जितनी किताबें बिकती हैं, उसकी रॉयल्टी लेखकों को वित्तीय वर्ष के अंत में भेज दी जाती है. उधर लेखकों को लगता है कि उनके साथ अन्याय होता है. कई लेखक एवं प्रकाशक अनुबंध करने में कोई रुचि नहीं रखते, दोनों की चाहत होती है किताब छप जाए. प्रोफेशनलिज्म की इसी कमी की वजह से किताबों की बिक्री और कॉपीराइट भुगतान का कोई बेहतर मैकेनिज्म नहीं बन पाया. इसका नुक़सान यह हुआ कि लेखक और प्रकाशक के बीच बहुधा अविश्वास की स्थिति पैदा होती रही है. इस लेख का मकसद लेखक-प्रकाशक संबंध नहीं है, बल्कि हम इस बिंदु पर बात कर रहे थे कि किस तरह से हिंदी में साहित्य लिखकर कोई भी लेखक स्वावलंबी नहीं हो सकता. इसके बरक्स अगर हम कला और संगीत को देखते हैं, तो वहां काफी पैसे हैं. वहां कलाकार सिर्फ़ कला को समर्पित होकर ठाठ से रह सकता है. पेंटिंग की स्थिति तो बहुत अच्छी है. बड़े और स्थापित चित्रकारों की तो बात ही छोड़ दीजिए, अगर हम कला बाज़ार की बात करें, तो हमें स्थिति बहुत सुखद दिखाई देती है.

क़रीब सात-आठ साल पहले की बात है, जब अमेरिकी अर्थशास्त्री पॉल कुर्गमैन ने वैश्विक मंदी की आशंका जताई थी. उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जार्ज बुश के प्रशासन को आगाह किया था कि पूरा विश्व भयानक आर्थिक मंदी की चपेट में आ सकता है. एक तरफ़ कुर्गमैन दुनिया में आर्थिक मंदी को लेकर चिंता जता रहे थे, वहीं दूसरी ओर विश्व कला बाज़ार में कलाकृतियों की क़ीमतें आसमान छू रही थीं. उस वक्त भारतीय कलाकारों की पेंटिंग्स करोड़ों रुपये में नीलाम हुई थीं. यूपीए शासनकाल के अंतिम दो-तीन वर्षों में जब अर्थव्यवस्था दबाव में थी, तो उसका थोड़ा-बहुत असर भारतीय कला बाज़ार पर भी दिखा था. उस वक्त बाज़ार के जानकार इसे शेयर बाज़ार से जोड़कर देख रहे थे. उनका तर्क था कि शेयर बाज़ार से कमाए गए पैसे लोग कला बाज़ार में निवेश करते थे, जो कि एक बेहद सुरक्षित विकल्प माना जाता था. अंतरराष्ट्रीय और भारतीय कला बाज़ार में न तो आर्थिक मंदी का कोई बहुत ज़्यादा असर दिखा और न अर्थव्यवस्था के कमजोर होने का. कई नामचीन भारतीय पेंटर हैं, जिनकी कलाकृतियां करोड़ों रुपये में बिकीं. एमएफ हुसैन, एसएच रजा, तैयब मेहता जैसे महान चित्रकारों के अलावा भी कई आधुनिक चित्रकार हैं, जिनकी कलाकृतियों की क़ीमत लाखों में रहती है. उनके बारे में कम लिखा जाता है और उनका

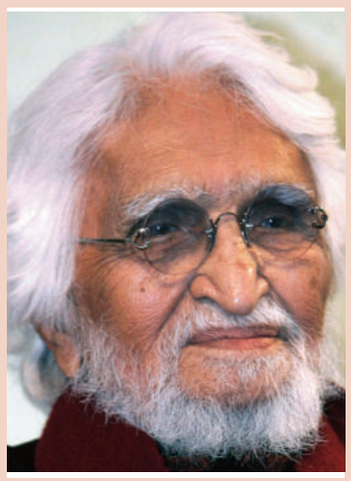

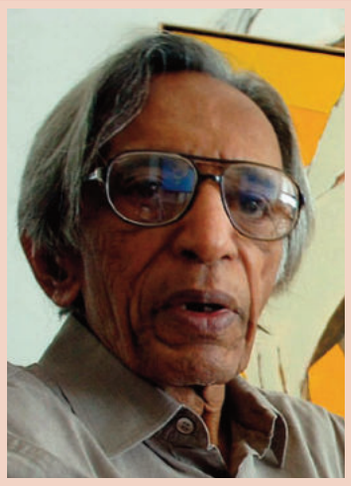

काम चर्चित नहीं हो पाता. कुछ वर्षों पहले लंदन में नीलामी करने वाली कंपनी सॉदबी ने जोगेन चौधरी की कलाकृति-डे ड्रीमिंग को तीन करोड़ रुपये में बेचा था. ग़ौरतलब है कि 2007 में सॉदबी ने रॉकिब शॉ की पेंटिंग- गॉर्डन ऑफ अर्थली डिलाइट्स को 21 करोड़ रुपये में बेचकर इतिहास रच दिया था. इसी तरह अनीश कपूर की एक पेंटिंग को 28 लाख डॉलर, टीवी संतोष की कलाकृति-टेस्ट टू को डेढ़ लाख डॉलर और रॉकिब शॉ की पेंटिंग को 51 हज़ार डॉलर मिले थे, जो नीलामीकर्ता की उम्मीदों से कहीं ज़्यादा थे. यह फेहरिस्त बेहद लंबी है. चिंतन उपाध्याय की पेंटिंग को 73 हज़ार डॉलर, रियास कोमू की सिस्टमेटिक सिटीजन फोर्टीन को 79 हज़ार डॉलर, तो बोस कृष्णामचारी की पेंटिंग को 40 हज़ार डॉलर मिले थे. इस फेहरिस्त में युवा चित्रकार मनीष पुष्कले को भी शामिल कर सकते हैं, जिनकी एक कलाकृति 2006 में 78 लाख रुपये में बिकी थी. भारतीय कलाकारों का एक बड़ा वर्ग है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय कला बाज़ार में धाक है.

इन दिनों मनीष पुष्कले के चित्रों की प्रदर्शनी दिल्ली की आकार-प्रकार गैलरी में चल रही है. प्रदर्शनियां भारतीय कला बाज़ार और चित्रकार की सोच को समझने का एक मौक़ा देती है. मनीष पुष्कले से बात करके मुझे लगा कि भारत के जो युवा चित्रकार कला बाज़ार में तेजी से स्थापित हो रहे हैं, उनके पीछे एक सोच, एक विचार, एक विरासत और एक अध्ययन है. मनीष ने पानी के बारे में जो बातें कहीं, उन पर काफी गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है. मनीष पुष्कले के मुताबिक, उसके दादा ने कहा था कि अलग-अलग स्रोतों के पानी को मिलाना एक पवित्र कार्य है. अब यह एक ऐसा वाक्य है, जिसका काफी बड़ा संदर्भ लिया जा सकता है, लेकिन मनीष ने इसे अपनी चित्रकारी के संदर्भ में लिया. मनीष ने बताया कि वह पिछले तेईस सालों से जहां भी जाते हैं, वहां का पानी ज़रूर लेकर आते हैं और एकत्र करते हैं. गांव से लेकर शहर तक, देश से लेकर विदेश तक, जंगल से लेकर गुफा तक, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ तक मनीष ने जितनी यात्राएं की हैं, हर जगह का पानी उनके पास है. मनीष के मुताबिक, जब वह उस पानी के भंडार

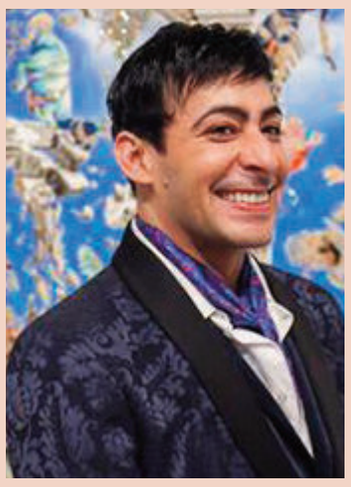

को देखते हैं, तो उन्हें अपने जेहन में बसी उन जगहों की परंपराओं एवं विरासत की याद ताजा हो जाती है, जिसे फिर वह अपनी कला में स्थान देते हैं. जब ऐसी सोच और विरासत को लेकर चित्रकारी की जाती है, तो कला प्रेमियों को बातें समझ में आती हैं. माना यह जाता है कि कला प्रेमियों को किसी खास कलाकारी के पीछे की सोच अगर पसंद आ जाती है, तो फिर वे उसकी क़ीमत पर ध्यान नहीं देते. मनीष की कला के पीछे एक सोच है. मनीष का मानना है कि आधुनिक समाज ने कोई सभ्यता नहीं बनाई है, उसने म्यूजियम बनाया है, जहां हम अपनी समृद्ध विरासत को संभाल कर रखते हैं. इन संग्रहालयों में हम पूर्वजों की यादें और उनकी समृद्ध विरासत संजो रहे हैं. मनीष की इस प्रदर्शनी का नाम भी है, म्यूजियम ऑफ अननोन मेमोरीज. इस प्रदर्शनी के चित्रों में इस थीम को साफ़ तौर पर रेखांकित किया जा सकता है. हमारे देश के इस युवा चित्रकार के सोचने का कैनवस बहुत बड़ा है. यह अपनी चित्रकारी के माध्यम से जिस तरह की संप्रेषणीयता अपनाता है, वही तकनीक अपने लेखन में भी अपनाता है. मनीष पुष्कले ने बहुत कम समय में पेंटिंग की दुनिया में काफी यश कमा लिया. चित्रकारी में यश के साथ पैसा स्वत: आता है. उनके चित्रों की प्रदर्शनी देश-विदेश में लगती रहती है. मनीष पुष्कले चित्रकारी की इस विधा में औपचारिक रूप से दीक्षित नहीं हैं, बल्कि उन्होंने अपनी लगन और मेहनत के बल पर यह मुकाम हासिल किया. मनीष ने अपनी किताब सफेद साखी में लिखा है, कैनवस दिगंबरा है, चारों तरफ़ से खुली हुई. सफेद, शांत, पवित्र. उनकी न स्मृति है, न इतिहास. इस दिगंबरा को उनके चित्रों में महसूस भी किया जा सकता है.

कला का जो बाज़ार है, उसमें ग्राहकों का मनोविज्ञान बेहद अहम भूमिका अदा करता है. किसी भी देश में राजनीतिक हालात बेहतर रहते हैं, तो निवेशकों का भरोसा मजबूत रहता है और वे बेफिक्र होकर निवेश करते हैं. हाल के दिनों में कला बाज़ार में निवेश करने वालों की तादाद बढ़ी है और आने वाले समय में इस बाज़ार में और भी बढ़ोतरी व स्थिरता देखने को मिल सकती है. घरेलू कला बाज़ार और सोना दो निवेश ऐसे हैं, जिनमें निवेशकों का विश्वास लगातार बना हुआ है. एक अनुमान के मुताबिक, भारत का कला बाज़ार लगभग दो से तीन हज़ार करोड़ रुपये का है. शेयर बाज़ार में सुधार के बाद कला बाज़ार में और बेहतरी की उम्मीद है. कला का भारत में एक बाज़ार बना, लेकिन साहित्य का बाज़ार होते हुए वह बन नहीं सका.

दरअसल, हिंदी के लेखकों को बाज़ार से बेहद तकलीफ है. यह उनका दोहरा रवैया है. कोई भी लेखक जैसे ही किताब छपने के लिए तैयार करता है, तो उसकी ख्वाहिश होती है कि वह बिके. बिकेगी कहां, बाज़ार में. बाज़ार में किताब की बिक्री की ख्वाहिश पाले लेखक उसी बाज़ार का विरोध करते हैं, लिहाजा बाज़ार उन्हें अपने तरीके से हाशिये पर डाल देता है. बाज़ार का विरोध ठीक है, आप करो, लेकिन फिर उसी से अपेक्षा तो न करो. दरअसल, हिंदी साहित्य में निवेश के पीछे यही मानसिकता ज़िम्मेदार है. इससे आगे निकलना होगा, वरना स्थिति में सुधार की उम्मीद बेमानी है. ■

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

लेखन की एक नई शैली

वसीम अकरम

जितना दिन में लोग एमए-पीएचडी करेगा, हौंक के पढ़ दिया, तो ओतना दिन में तो आईएसे बन जाएगा... नीलोत्पल मृणाल के पहले उपन्यास डार्क हॉर्स के मुख्य किरदार का यह कथन उन सभी छात्रों की संवेदना व्यक्त करता है, जो स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद गांवों से निकल कर सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए सुदूर शहरों की ओर जाते हैं. और, इस ठसक के साथ वे एक जद्दोजहद भरी ज़िंदगी में क़दम रखते हैं कि अब अगर बोरिया-बिस्तर उठा, तो उनके नन्हें हाथों में एक कुशल प्रशासक बनने का प्रमाण-पत्र होगा तथा उनके छोटे कंधों पर शिद्दत से आस लगाए मां-बाप की आंखों में पल रहे कुछ खूबसूरत ख्वाबों को पूरा करने की ज़िम्मेदारी भी होगी. यह ठसक यहीं नहीं रुकती, बल्कि और भी आगे बढ़ती है और घर-परिवार, रिश्ते-नाते, गांव-जवार, जनपद-क्षेत्र आदि को शानो-शौकत से नवाजती हुई अगली कई पीढ़ियों को तारने तक पहुंचती है. इस ऐतबार से डार्क हॉर्स महज एक उपन्यास भर नहीं है, बल्कि छात्र जीवन की अनगिनत अनकही कहानियों का ऐसा दस्तावेज़ है, जो यथार्थ के धरातल पर एक तरफ़ सफलता के आस्वाद को चिन्हित करता हुआ एक अदद नौकरी के लिए सिविल सर्विस को ही पैमाना मानता है, तो वहीं दूसरी तरफ़ बीए-एमए-पीएचडी की डिग्रियां हासिल करने के बाद भी उसी एक अदद नौकरी के न मिलने पर हमारी शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल भी खड़े करता है.

शब्दारंभ प्रकाशन, दिल्ली से प्रकाशित उपन्यास डार्क हॉर्स का मुख्य किरदार संतोष बिहार के भागलपुर से सिविल सर्विस की तैयारी के लिए दिल्ली आता है. उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे हिंदी पट्टी के राज्यों से सिविल सर्विस की तैयारी करने के लिए लड़के या तो इलाहाबाद का रुख करते हैं या फिर दिल्ली का. खास तौर से हिंदी माध्यम से तैयारी करने वाले लड़कों के लिए ये दो जगहें ही मख्सूस मानी जाती हैं. जो थोड़े कमजोर घर से होते हैं, वे इलाहाबाद रहकर तैयारी करते हैं और जो थोड़े साधन-संपन्न होते हैं, वे दिल्ली के मुखर्जी नगर में अपना आशियाना बनाते हैं. साथ ही यह भी कि मुखर्जी नगर में एक इलाहाबाद हमेशा मौजूद रहता है.

समीक्ष्य कृति : डार्क हॉर्स (उपन्यास)
लेखक : नीलोत्पल मृणाल
प्रकाशक : शब्दारंभ प्रकाशन, दिल्ली
मूल्य : 150 रुपये (पेपरबैक)

पुस्तक का लोकार्पण करतीं लोकगायिका मालिनी अवस्थी साथ में लेखक नीलोत्पल मृणाल व अन्य.

गुरुत्व व चेलत्व के भावों में उतर कर फौरन ही सोचने लगते हैं कि अब तो आईएएस बनना जरा भी दूर नहीं. चाय पे चकल्लस के दौरान हुई किसी से एक छोटी-सी ग़लती भी कैसे इतिहास की बड़ी से बड़ी ग़लती साबित हो जाती है. उसी ग़लती को जो पकड़ कर अच्छी तरह से समझ लेता है, उसके लिए परिणाम के दिन जश्न और जो नहीं समझ पाता है, उसके लिए मातम.

उसी जश्न और मातम के पहले की संघर्षपूर्ण, मगर सच्ची तस्वीर डार्क हॉर्स में पेश की है नीलोत्पल ने, जिसमें संघर्ष सिर्फ़ एक परीक्षा की तैयारी को लेकर नहीं है, बल्कि गांव-शहर की संस्कृतियों का भी संघर्ष है, खान-पान और रहन-सहन से लेकर भाषाई शुचिता और भदेसपन का भी संघर्ष है, बौद्धिकता और सहजता का संघर्ष है, गंवई बाप और शहर में समझौतावादी हो चले उसके पुत्र के बीच संवाद का संघर्ष है, सफलता और असफलता का संघर्ष है, कोचिंग क्लास में अपनी पहली प्रेमिका या प्रेमी खोजने का संघर्ष है, भारी-भरकम सिलेबस के बीच कहीं कोई मस्ती का कोना ढूंढने का संघर्ष है, मर्यादाएं-परंपराएं बनाए रखने या झट से तोड़ देने का संघर्ष है, खुद के मिजाज और व्यवस्था के लिजलिजेपन का संघर्ष है. ये सारे संघर्ष मिलकर एक आत्मकथा तैयार करते हैं, मुखर्जी नगर या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में सिविल या दूसरी किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले लड़के-लड़कियों की आत्मकथा. मगर, एक विशेष देश-काल के दौरान ही घटित हुई आत्मकथा, जिसमें जीवन का एक खास हिस्सा हमारे सामने हो. नीलोत्पल खुद भी सिविल की तैयारी करते हैं, इस ऐतबार से यह उनकी भी आत्मकथा बहरहाल! इस उपन्यास को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि नीलोत्पल ने हमें मुखर्जी नगर की एक इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल की खिड़की पर बैठा दिया है, जहां से हम इसके सारे किरदारों को आते-जाते, उठते-बैठते, पढ़ते-लिखते, खाते-पीते देख रहे होते हैं. सबकी ज़ुबान पर पुरबिया बोली ऐसा माहौल पैदा करती है कि मानो बत्रा के पास पूरा का पूरा पुरबिस्तान इकट्ठा हो गया हो. यह भी नज़र आता है कि बरसों से वैष्णव परंपरा का निबाह करते चले आ रहे छात्र दिल्ली में क़दम रखते ही कैसे समझौतावादी हो जाते हैं और है. इस उपन्यास की सबसे खास बात यह है कि लेखक ने अपने किरदारों की ज़ुबान नहीं काटी है. किरदारों ने जब चाहा-जो चाहा, बोल दिया, जैसी गाली देनी चाही, दी और लेखक ने ठीक वैसे ही उसे लिख दिया. इसलिए वह शब्द, शिल्प, बिंब आदि के साहित्यिक पैमानों से बरी हो जाते हैं. किरदारों के साथ ऐसा इंसाफ यथार्थ लेखन में ही संभव है. वैसे भी नीलोत्पल खुद भी यह दावा करते हैं कि उन्होंने इस उपन्यास के रूप में कोई साहित्य नहीं रचा है, बल्कि उन्होंने जो देखा है, उसे ही अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में पिरोकर एक कहानी कह डाली है. यह उपन्यास पढ़ते हुए, किरदारों के मुंह से गंवई गालियां सुनते हुए ऐसा नज़र भी आया है, जिससे यह कहा जा सकता है कि वह अपने दावे पर खरे उतरे हैं. लेकिन, यहीं से उम्मीदें भी पनपती हैं, जो नीलोत्पल से मांग करती हैं कि आने वाले दिनों में वह भाषाई शुचिता के पहरेदारों को नाक-भौं सिकोड़ने नहीं देंगे. अब वह एक लेखक हैं, एक लेखक के रूप में उनकी ज़िम्मेदारी और भी बढ़ जाती है. हो सकता है कि उन्हें कोई अच्छा किरदार खोज रहा हो, जो गाली न देता हो, मगर उतना ही सशक्त हो, जितना कि डार्क हॉर्स के किरदार हैं. खैर, यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन नीलोत्पल ने इस उपन्यास से यह साबित कर दिया है कि उनमें लेखन की एक नई हुमक है.

डार्क हॉर्स लेखक नीलोत्पल मृणाल का पहला उपन्यास तो है ही, साथ ही शब्दारंभ प्रकाशन की भी पहली किताब है. जिस तरह से इस उपन्यास के लोकार्पण के महज सप्ताह भर के भीतर ही पहले संस्करण की सारी प्रतियां पाठकों के पास पहुंच गईं और दूसरे संस्करण के लिए प्री-बुकिंग जारी है, इस ऐतबार से उम्मीद है कि जल्दी ही यह उपन्यास हिंदी साहित्य में बेस्ट सेलर हो जाए. हालांकि, अभी प्रूफ की ग़लतियों को लेकर प्रकाशक को सोचना होगा, जो खाने में कंकड़ की तरह कहीं-कहीं चुभती हैं, लेकिन वहीं यह भी सत्य है कि किसी प्रकाशक के लिए प्रूफ की ग़लतियां सुधारना एक अनवरत यज्ञ की तरह होता है, जिसे हमेशा जारी रहना चाहिए. ■

feedback@chauthiduniya.com

> इस फोन की स्क्रीन 5 इंच की है जो 720 गुणा 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. यह एंड्रॉयड 4.4.4 किटकैट पर आधारित है और इसका प्रोसेसर क्वाड कोर 1.2 गीगाहर्ट्ज है. इसमें इंटरनल मेमोरी 16 जीबी है. फोन की रैम 2 जीबी है. इसका कैमरा ऑटो फोकस के साथ 8एमपी का है और फ्रंट कैमरा 2एमपी का है. इसकी बैटरी 2300 एमएएच की है.

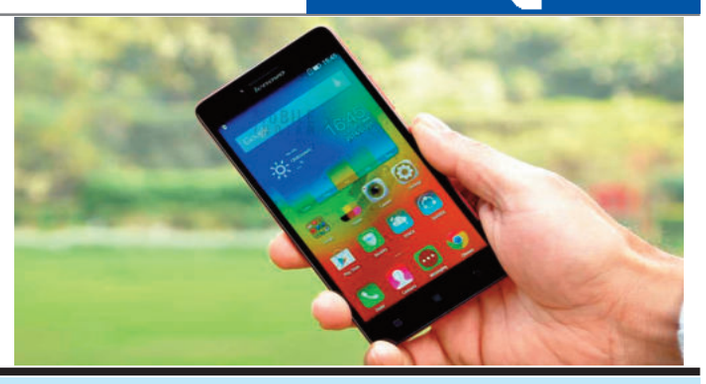

लॉजिटेक का मास्टर माउस है लाजवाब

डिजाइनिंग से लेकर पेंटिंग और एनिमेशन समेत कम्प्यूटर पर किए जाने वाले तमाम काम माउस के बिना संभव नहीं है. यही नहीं, माउस से काम की स्पीड भी बढ़ जाती है. स्मूद डिजाइन वाला यह मास्टर माउस पूरी तरह वॉयरलेस है. इसमें लगे बैटरी इंडीकेटर बैटरी डिस्चासर्ज होने की जानकारी देते रहते हैं. जबकि ऑटो शिफ्ट ऑप्शन की मदद से इसे फास्ट और स्लो स्क्रॉल सेट कर सकते हैं. माउस की डिजाइन में एक किनारे पर अगूंठा रखने के लिए एक स्लेप भी दिया गया है. मास्टर माउस में स्क्रॉल व्हील ज्यादा फास्टर वेब ब्राउजर स्क्रॉल करती है. वहीं, इस माउस में डुअल कनेक्टिविटी ऑप्शन भी दिए गए हैं. इसे एक साथ तीन डिवाइसेज से कनेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा माउस में रिचार्जेबल बैटरी लगी हुई है, जो चार मिनट चार्ज होने के बाद 40 दिनों का बैटरी बैकअप देती है. थंब डिजाइन इसे आराम से पकड़ने में मदद करता है. माउस में दिया गया लेजर ट्रैक डिजाइन किसी भी तरह की सतह पर आराम से काम करता है. यहां तक कि इसे ग्लास पर भी आसानी से चला सकते हैं. ■

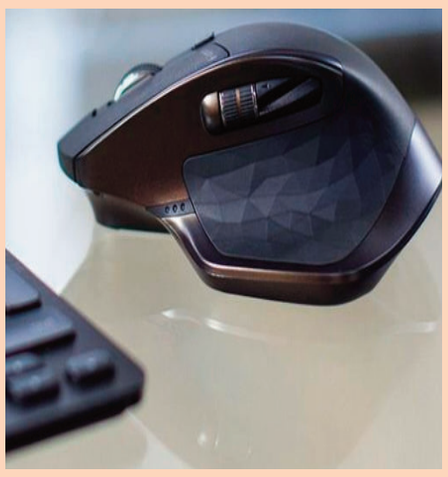

माइक्रोमैक्स का नया धमाका कैनवास स्पार्क

माइक्रोमैक्स ने अपना बजट स्मार्टफोन कैनवास स्पार्क लॉन्च किया है. इस डुअल सिम स्मार्टफोन में लेटेस्ट एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0 है. इसका डिस्प्ले 4.7 इंच का है जो 540 गुणा 960 पिक्सल का है. इस फोन की ग्लास पर गोरिल्ला ग्लास3 प्रोटेक्शन दी गई है. इसका प्रोसेसर 1.3 गीगाहर्ट्ज क्वार्ड कोर मीडिया टेक है और साथ ही इसमें 1 जीबी रैम दी गई है. इस फोन का रियर कैमरा 8 मेगापिक्सल है साथ ही लेड फ्लैश है. फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल है. फोन की इंटरनल मेमोरी 8 जीबी है जिसे बढ़ा कर 32 जीबी किया जा सकता है. कनेक्टिविटी के मामले में फोन में जीपीएस ब्लूटुथ, ऑडियो जैक का ऑप्शन है. इसके साथ ही माइक्रोमैक्स ने टेलिकॉम कंपनी वोडाफोन के साथ टाई–अप किया है जिसके मुताबिक ये फोन खरीदने वाले को वोडाफोन की ओर से 500 एमबी डेटा दो महीने तक दिया जाएगा. ये फोन अभी व्हाइट और गोल्ड कलर और कॉम्बिनेशन के साथ बाजार में मौजूद है. इस 3जी स्मार्टफोन की कीमत 4,999 रुपये है. ■

पावरफुल लेंस के साथ निकोन 1जे 5

निकोन अपनी 1 सीरीज का सबसे शानदार कैमरा लेकर आई है. निकोन1 जे5 नाम से आया यह कैमरा अनोखे डिजायन और आकर्षक डिस्पले वाला है. इसके अलावा इसमें पहले वाले मॉडल्स से ज्यादा पावरफुल लैंस और फीचर्स दिए गए हैं. इस कैमरे से 4के क्वालिटी के फोटो और वीडियो शूट किए जा सकते हैं. निकोन की 1 सीरीज कैमरों में यह पहला ऐसा कैमरा है जिसमें आकर्षक दिखने वाला 3 इंच की फ्लिपअप एलसीडी डिस्पले दिया गया है. इस डिस्पले की एक और खास बात ये है कि इसे आगे की तरफ घुमाकर खुद की सेल्फी भी ली जा सकती है. निकोन 1 जे5 कैमरे में अन्य मॉडल्स की तुलना में ज्यादा पावरफुल लैंस दिया गया है. यह 20.8 मेगापिक्सल सेंसर से लैस है जो 4 के क्वालिटी के फोटो और वीडियो शूट कर सकता है. यह कैमरा एनएफसी तथा वाय–फाय जैसे कनेक्टिविटी फीचर्स से लैस है. माना जा रहा है कि निकोन का यह नया कैमरा अभी मिल रहे 1 जे4 कैमरे की जगह लेगा. ■

निकोन की 1 सीरीज कैमरों में यह पहला ऐसा कैमरा है जिसमें आकर्षक दिखने वाला 3 इंच की फ्लिपअप एलसीडी डिस्पले दिया गया है. इस डिस्पले की एक और खास बात ये है कि इसे आगे की तरफ घुमाकर खुद की सेल्फी भी ली जा सकती है.

अपडेटेड वर्जन में लेनोवो का ए6000 प्लस

लेनोवो ने तेजी से बाजार में पॉपुलर हुए अपने स्मार्टफोन ए6000 को एक बार फिर नए अंदाज में उतारा है. डुअल सिम सपोर्ट वाले लेनेवो ए6000 प्लस के ज्यादातर फीचर ए6000 जैसे ही हैं, लेकिन इसकी रैम और इनबिल्ट स्टोरेज ज्यादा है. इसमें 2जीबी रैम और 16जीबी इंटरनल मेमोरी है. जबकि ए6000 में 1 जीबी रैम और 8 जीबी इंटरनल मेमोरी है. इस फोन की स्क्रीन 5 इंच की है जो 720 गुणा 1280 पिक्सल का रेजोल्यूशन देती है. यह एंड्रॉयड 4.4.4 किटकैट पर आधारित है और इसका प्रोसेसर क्वाड कोर 1.2 गीगाहर्ट्ज है. इसमें इंटरनल मेमोरी 16 जीबी है. इसका कैमरा ऑटो फोकस के साथ 8एमपी का है और फ्रंट कैमरा 2एमपी का है. इसकी बैटरी 2300 एमएएच की है. इस नए स्मार्टफोन ए6000 प्लस की कीमत 7499 रुपये है. ■

हुंदै ने लॉन्च किया इलैंट्रा का नया मॉडल

हुंदै इंडिया ने अपनी प्रीमियम सेडान सेगमेंट की कार इलैंट्रा का नया मॉडल बाजार में लॉन्च किया है. इलैंट्रा के इस अपडेटेड वर्जन में नई डिजाइन और फीचर्स पर काम किया गया है. हालांकि इस कार के इंजन में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. नई इलैंट्रा में नया फ्रंट बंपर, क्रोम ग्रिल, लेड लाइट गाइड के साथ प्रोजेक्टर हेड लैंप, नया फॉग लैंप, 16 इंच का एलॉय व्हील, क्रोम डोर हैंडल लगाया गया है. साथ ही कार के पिछले हिस्से में भी टू–टोन बंपर लगाया गया है. कंपनी ने कार के इंटीरियर में भी बदलाव किए हैं. कार के अंदर सारे इंटीरियर काले रंग के रखे गए हैं. साथ ही लेदर सीट, मेटालिक स्कफ प्लेट, एल्यूमीनियम पेडल, आर्म रेस्ट और रियर एसी वेंट लगाया गया है. नई इलैंट्रा के इंजन में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इस कार में 1.8 डुअल वीटीवीटी पेट्रोल और 1.6 वीजीटी सीआरडीआई डीजल इंजन लगाया गया है. इस कार का पेट्रोल इंजन 147 बीएचपी और 178 एनएम, वहीं डीजल इंजन 126 बीएचपी और 260एनएम की ताकत देता है. नई इलैंट्रा की कीमत 14.13 लाख रुपये से 17.94 लाख रुपये के बीच रखी गई है. ■

सड़कों पर फरटि भरेंगे हीरो के ये नये स्कूटर्स

हीरो मोटोकॉर्प इस साल भी अपने कई नए प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. कंपनी ने स्कूटर बाजार पर भी अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए भी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती. कंपनी जल्द ही नए स्कूटर्स बाजार में उतारेगी. इस साल जो चार स्कूटर बाजार में आएंगे उनमें हीरो डैश, डेयर, जेडआईआर, और लीप प्रमुख हैं.

हीरो के आने वाले चार स्कूटर्स के फीचर:

1. हीरो डैश 110सीसी

110 सीसी सेगमेंट में डैश हीरो का दूसरा स्कूटर होगा. डैश 110सीसी के इंजन, फोर स्ट्रोक, एयर कूल्ड, सिंगल सिलिंडर इंजन से लैस होगा. इस स्कूटर के इंजन की ताकत 8.5 बीएचपी और 9.4 एनएम की होगी. इसमें यूएसबी मोबाइल चार्जर, सर्विस ड्यू इंडिकेटर, बूट लाइट, लेड टेल लैम्प्स, एनालॉग डिजिटल मीटर, ई–कोड चाबियां और डुअल टोन इंटिरीयर जैसे फीचर्स होंगे. यह स्कूटर में नए मेटल बॉडी, एलॉय व्हील और ट्यूबलेस टायर जैसे फीचर से लैस होगा.

2. हीरो डेयर 125 सीसी

डेयर 125सीसी सेगमेंट में हीरो का पहला स्कूटर होगा. इस स्कूटर का इंजन एयर कूल्ड होगा जो कि 9.1 बीएचपी की ताकत के साथ साथ 9.5एनएम का टॉर्क देगा. डेयर के प्रमुख फीचर में–टेक्सचर सीट, डुअल टोन एलॉय, लेड डेटाइम रनिंग हेडलैम्प, बूट लैम्प, बॉडी कलर्ड ब्रेक कैलिपर्स और यूएसबी चार्जर शामिल होगा.

3. हीरो जेडआईआर 150 सीसी

जहां एक ओर कंपनी डेयर के साथ 125 सीसी सेगमेंट में अपने पांव रख रही है वहीं दूसरी तरफ जेडआईआर के साथ 150 सीसी के स्कूटर के बाजार में भ ी इंट्री ले रही है. जेडआईआर का लुक स्पोर्टी होगा जो दो वेरिएंट–फ्लैट फ्लोरबोर्ड और युरोपियन स्टाइल में उपलब्ध होगा. जेडआईआर में 157 सीसी इंजन, सिंगल सिलिंडर, 2 वॉल्व, लिक्विड–कूल्ड इंजन लगा होगा जो 13.8 बीएचपी और 12.7 एनएम की ताकत देगा जो अपने आप में बेहतरीन है. जेडआईआर में भी कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगा. यूरोपियन स्टाइल स्टेप सीट, डुअल प्रोजेक्टर हेड लैम्प (डेटाइम रनिंग फीचर के साथ), फ्रंट प्रोटेक्शन स्क्रीन, लेड ब्लिंकर्स और टेल लैम्प इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाएंगे.

जेडआईआर में 157 सीसी इंजन, सिंगल सिलिंडर, 2 वॉल्व, लिक्विड–कूल्ड इंजन लगा होगा जो 13.8 बीएचपी और 12.7 एनएम की ताकत देगा जो अपने आप में बेहतरीन है. जेडआईआर में भी कई ऐसे फीचर्स दिए गए हैं जो ग्राहकों को अपनी ओर खींचेगा.

4. हीरो लीप हाइब्रिड

भारत में बना हुआ पहला इलेक्ट्रिक–हाइब्रिड स्कूटर है. हीरो मोटोकॉर्प इसे भारत के साथ–साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी उतारने की तैयारी कर रहा है. ये यूरोपियन बाजार में भारतीय कंपनी का पहला प्रोडक्ट होगा. इस स्कूटर में 8केडबल्यू परमानेंट मैग्नेट एसी (झचङ्घउ) मोटर से लैस होगा और इसमें लीथियम–इऑन बैट्री लगी होगी. साथ ही इसमें 124 सीसी का पेट्रोल इंजन लगा होगा. इस स्कूटर की सबसे खास बात इसका टॉर्क होगा जो 60एनएम पावर देगा. लीप की अधिकतम स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी. इसमें भी एक्सटेंडर रोटेशन स्क्रीन, ब्राइट लेड ब्लिंकर्स और टेल लैम्प जैसे फीचर होंगे. साथ ही इसमें कनेक्टिविटी फीचर्स भी होंगे. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो feedback@chauthiduniya.com

एक दिवसीय क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी

इंग्लैंड के युवा क्रिकेटर लियम लिविंगस्टोन ने ताबड़तोड़ बल्लेबाज़ी करते हुए किसी भी वनडे मुक़ाबले में सबसे बड़ी पारी का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. ईसीबी नेशनल क्लब चैंपियनशिप में नैंटविच टाउन की ओर से खेलते हुए ऑलराउंडर लिविंगस्टोन ने केल्डी क्लब के खिलाफ हुए मुक़ाबले में महज 138 गेंदों पर 350 रन ठोक दिए. अपनी इस मैराथन पारी के दौरान लिविंगस्टोन ने 34 चौके और 27 छक्के लगाए. यानी लिविंगस्टोन ने 350 रनों में से 298 रन बाउंड्री के जरिए हासिल किए. इस तूफानी पारी के बाद 21 साल के लिविंगस्टोन ने ट्विटर पर लिखा कि, मैंने बहुत ख़राब दिन देखे हैं, बधाई संदेश देने वाले सभी का धन्यवाद. लिविंगस्टोन ने अपनी इस पारी से वनडे फॉरमेट के किसी भी मुक़ाबले में सबसे बड़े स्कोर के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. इससे पहले भारत के स्कूली क्रिकेटर निखिलेश सुरेंद्रन ने साल 2008 में हैदराबाद में 334 रनों की नाबाद पारी खेली थी. लिविंगस्टोन की इस पारी की बदौलत नैंटविच टाउन ने सात विकेट पर 579 रन बनाए. इसके जवाब में केल्डी की टीम महज 79 रनों पर सिमट गई. उसे यह मुकाबला 500 रनों से गंवाना पड़ा. वैसे, लिविंगस्टोन ने अभी तक प्रथम श्रेणी का कोई मैच नहीं खेला है, लेकिन माना जा रहा है कि इस तूफानी बल्लेबाज़ी को जल्दी ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेलने का मौका मिलेगा.■

और ग्रैंडस्लैम खिताब जीतना चाहती हूं सानिया

विश्व की नंबर एक युगल टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने कहा है कि वह संन्यास लेने से पहले और अधिक ग्रैंडस्लैम खिताब जीतना चाहती हैं. हाल ही में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी बनी सानिया ने अब तक तीन ग्रैंडस्लैम खिताब जीते हैं. सानिया ने कहा कि मुझे टेनिस खेलना पसंद है. मुझे अभ्यास और कड़ी मेहनत करना पसंद है, मुझे प्रतिस्पर्धा पसंद है, और मैं जब तक लुत्फ उठाती रहूंगी, तब तक टेनिस खेलती रहूंगी. मैं अधिक से अधिक उपलब्धियां हासिल करना चाहती हूं. बेशक कभी कोई चीज पर्याप्त नहीं होती. सानिया ने कहा कि अगर रोजर फेडरर आज भी खेल रहे हैं, तो सभी को खेलना चाहिए. संन्यास लेने से पहले मैं कुछ और ग्रैंडस्लैम जीतना चाहती हूं. उन्होंने कहा कि वह मार्टीना हिंगिस के साथ जोड़ी बनाए रखेंगी, उनके साथ वह काफी सफल रही हैं. सानिया ने कहा कि साल 2010 में शादी करना और केवल डबल्स मुकाबलों में खेलना उनके जीवन के दो सबसे महत्वपूर्ण फैसले हैं. उन्हें 2010 में लगा था कि उनका करियर खत्म हो गया है, तब मेरी कलाई में समस्या थी और मैं अपने बालों में कंघी तक नहीं कर पा रही थी. उस समय टेनिस खेलने का सवाल ही नहीं था. इसलिए मैंने शादी का फैसला किया. और दूसरा फैसला मैंने सिर्फ डबल्स खेलने का किया. यह फैसला भी सही साबित हुआ. ■

भारतीय पैरालम्पिक समिति निलंबित

भारतीय पैरालम्पिक समिति (पीसीआई) को अंतरराष्ट्रीय पैरालंम्पिक समिति(आईपीसी) ने निलंबित कर दिया है. आईपीसी के बाद खेल मंत्रालय ने भी 15वीं राष्ट्रीय पैरा–एथलेटिक्स चैंपियनशिप के आयोजन में बेहद खराब प्रबंधन पर नाराजगी जताते हुए पीसीआई की मान्यता को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. इस मामले में खेल मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थीं. समिति को भेजे गए एक पत्र में मंत्रालय ने कहा कि भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा की गई एक जांच में इस मामले की सभी तकनीकी, प्रशासनिक और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों की शिकायतें सही पाई गईं. मंत्रालय ने अपने पत्र में कहा है, इस संदर्भ में भारत सरकार का मानना है कि पीसीआई ने मान्यता की सेवा और शर्तों के साथ–साथ अपने प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है. सरकार को यह भी जानकारी मिली है कि पीसीआई पैरा खेलों के मामले में उत्साह के साथ कार्य नहीं कर रहा है जिसके लिए समिति को मान्यता दी गई थी. इसके अलावा समिति की सुविधाओं और व्यवहार से जुड़े पक्षों पर भी खिलाड़ियों और अन्य हितधारकों के बीच बड़े स्तर पर असंतोष व्याप्त है. इससे पहले भी खेल मंत्रालय इस मामले में पीसीआई को कारण बताओ नोटिस जारी कर चुका है. गौरतलब है कि 15वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन 20 से 22 मार्च के बीच गाजियाबाद में किया गया था. इस दौरान जो इंतजाम किये गये थे वह बेहद घटिया स्तर के थे और इस मामले में कई शिकायतें आईं थी.■

कोकीन के लिए बेचा दिया पदक

ब्राजील की सन 1970 की फुटबॉल विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे पाउलो सीजर ने स्वीकार किया है कि उन्होंने कोकीन खरीदने के लिए अपना स्वर्ण पदक बेच दिया. हालांकि सीजर ने पदक बेचने पर अफसोस जाहिर किया है. 65 साल के सीजर बोटाफोगो, फ्लामेंगो, फ्लूमिनेंसी, ग्रेमियो, वास्को डि गामा और कोरिंथियंस जैसे क्लबों के लिए खेल चुके हैं. उन्होंने बताया कि मार्सेली क्लब के लिए 1970 के दशक में खेलने के दौरान उन्हें कोकीन की लत लगी थी.■

बांग्लादेश ने किया पाकिस्तान का सूपड़ा साफ

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने इसे पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब दौर करार दिया है. इमरान ने कहा कि भाई भतीजावाद, पक्षपात और योग्यता को दरकिनार करने की संस्कृति के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बुरी स्थिति में पहुंच गया है.

पाकिस्तान की क्रिकेट टीम विश्वकप के निराशाजनक प्रदर्शन के झटके से उबर भी नहीं पाई थी, कि उसे बांग्लादेश के खिलाफ एक दिवसीय श्रृंखला में एक और झटका लग गया. बंगाल टाइगर्स ने पाकिस्तान को 3–0 के अंतर से पटखनी दे डाली. ये पहला मौका है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी द्विपक्षीय सीरीज पर कब्जा किया है. पाकिस्तान की इस हार के बाद बहुत आलोचना हो रही है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इमरान खान ने तो इसे पाकिस्तानी क्रिकेट इतिहास का सबसे खराब दौर करार दिया है. इमरान ने कहा कि भाई भतीजावाद, पक्षपात और योग्यता को दरकिनार करने की संस्कृति के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बुरी स्थिति में पहुंच गया है. उन्होंने कहा कि हम कमजोर क्रिकेट ढांचे से क्या उम्मीद कर सकते है जहां हमारा घरेलू ढांचा कुप्रबंधित है. बांग्लादेश के हाथों व्हाइटवाश झेलने के बाद पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की रैंकिंग में आठवें स्थान पर खिसक गया है. वह अब केवल बांग्लादेश और जिम्बाब्वे से ही आगे है. इमरान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में तब तक सुधार नहीं होगा जब तक कि क्रिकेट बोर्ड में भाई भतीजावाद के जरिये आने वाले अयोग्य लोग रहेंगे. दुखद बात यह है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के लोगों को क्रिकेट का कुछ भी ज्ञान नहीं है. हमारे पास काफी प्रतिभा है लेकिन कमजोर क्रिकेट व्यवस्था के कारण यह प्रतिभा निखर नहीं पा रही है. बांग्लादेश की यह जीत इसलिए भी खास है क्योंकि श्रृंखला के पहले मैच में जीत के साथ उसने 16 साल बाद पाकिस्तान के खिलाफ अपनी सिर्फ दूसरी जीत दर्ज की थी. सीरीज के आखिरी मैच में सौम्य सरकार की शतकीय पारी(127) की मदद से बांग्लादेश ने 250 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए पाकिस्तान को महज 39.3 ओवरों में आठ विकेट से हरा दिया और सीरीज पर 3–0 के अंतर से कब्जा कर लिया. ■

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

एक टीम में खेल सकते हैं रोनाल्डो-मेसी

इन टीमों में कौन से खिलाड़ी होंगे इसका चयन फैंस ऑनलाइन वोटिंग के जरिये करेंगे. हर कोई इस बात से उत्साहित है कि मेस्सी और रोनाल्डो एक ही टीम में होंगे.

फुटबॉल की दुनिया के दो दिग्गज खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लायोनल मेसी एक ही टीम से खेल सकते हैं. दरअसल हर साल ऑल–स्टार मैच में यूरोप के बेहतरीन खिलाड़ियों के बीच का मुकाबला होता है. जिसमें टीम–साउथ का मुक़ाबला टीम–नॉर्थ से होता है. स्पेन, इटली और फ्रांस के क्लबों में खेलने वाले सितारों में से टीम–साउथ चुनी जाएगी, जबकि इंग्लैंड, जर्मनी और रूस के लीग में खेलने वाले सितारों से नॉर्थ की टीम चुनी जाएगी. इन टीमों में कौन से खिलाड़ी होंगे इसका चयन फैंस ऑनलाइन वोटिंग के जरिये करेंगे. हर कोई इस बात से उत्साहित है कि मेसी और रोनाल्डो एक ही टीम में होंगे. इस बात से दुनिया भर के फुटबॉल फैंस के नज़रें इस मैच पर टिकी हैं और ये मुकाबला शायद अब तक का सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा देखा जाने वाला मुक़ाबला हो सकता है क्योंकि दोनों खिलाड़ी एक साथ कभी नहीं खेले हैं और दोनों के बीच की जुगलबंदी देखने के लिए दोनों खिलाड़ियों के प्रशंसक बेताब हैं.■

गायन सीख रही हैं श्रद्धा

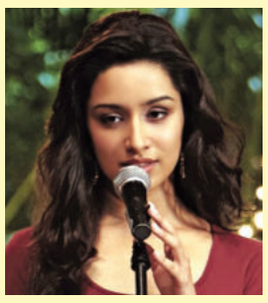

एक विलेन और हैदर जैसी सफल फिल्मों में अपनी गायकी के हुनर दिखा चुकीं अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एक बार फिर दर्शकों को अपने अभिनय के साथ–साथ अपनी गायकी का जादू दिखाने की तैयारी में जुटी हैं. वह इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म रॉकऑन–2 की तैयारी कर रही हैं. फिल्म के लिए एक तरफ वह सिक्किम जाकर रॉक बैंड से मिलने वाली हैं वहीं दूसरी तरफ सेलिब्रेटी सिंगिंग और म्यूजिक ट्रेनर समांथा एडवर्ड्स से गायकी के गुर सीख रही हैं. श्रद्धा का रिश्ता स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर परिवार से है. श्रद्धा अपने किरदार को पक्का करने के लिए ट्रेनिंग ले रही है. फिल्म रॉक ऑन–2 में श्रद्धा के साथ फरहान अख्तर, पूरब कोहली, अर्जुन रामपाल दिखाई देंगे. फिल्म रॉकआन में फरहान और अर्जुन कोहली ने काम किया था. वह फिल्म भी दोस्तों के एक बैंड पर आधारित थी. इस फिल्म में फरहान अख्तर ने अभिनय भी किया था और कई गीत भी गाए थे.■

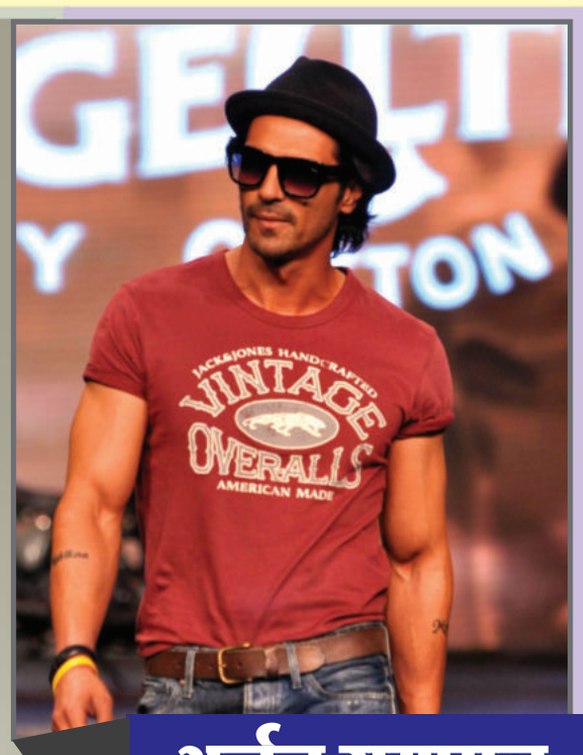

अर्जुन रामपाल बनेंगे गैंगस्टर

बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल आजकल अपनी आने वाली फिल्म डैडी के लिए दाढ़ी बढ़ा रहे हैं. फिल्म में वह गैंगस्टर से राजनेता बने अरुण गावली के किरदार अदा कर रहे हैं. अर्जुन ने इस बारे में ट्विटर पर इस बारे में जानकारी दी. रामपाल कुछ समय पहले रणबीर कपूर के साथ फिल्म रॉय में नजर आये थे. दर्शकों ने रॉय में उनकी एक्टिंग को काफी पसंद किया था. यह एक थ्रिलर फिल्म थी. उन्होंने फिल्म में एक फिल्म निर्माता का किरदार निभाया था. वहीं अब देखना दिलचस्प होगा कि अर्जुन गैंगस्टर और राजनेता के दोहरे किरदार से दर्शकों को कितना लुभा पाते हैं.■

कल्कि ने दर्शकों का शुक्रिया अदा किया

मार्गरीटा, विद ए स्ट्रा यह रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है. इसमें शारीरिक रूप से अशक्त 19 साल की एक लड़की की कहानी है जो सेलेब्रल पैल्सी से पीड़ित है. फिल्म अपने जीवन की आम गतिविधियों को लेकर लड़की के जूझने की बात करती है.

अभिनेत्री कल्कि कोचलीन अपनी हालि या रिलीज हुई फिल्म मार्गरीटा– विद ए स्ट्रा को मिली सफलता से बेहद उत्साहित हैं. कल्कि ने दर्शकों से मिली अच्छी प्रतिक्रिया और अभिनय की प्रशंसा के लिए उनका शुक्रिया अदा किया. इस फिल्म को मिली सफलता के बाद कल्कि ने कहा कि इस फिल्म की सफलता ने उन्हें अपारंपरिक विषयों पर आधारित फिल्मों की बॉलीवुड में सफलता को लेकर आशान्वित किया है. मार्गरीटा, विद ए स्ट्रा एक रोमांटिक–कॉमेडी फिल्म है. इसमें शारीरिक रूप से अशक्त 19 साल की एक लड़की की कहानी है जो सेलेब्रल पैल्सी से पीड़ित है. फिल्म अपने जीवन की आम गतिविधियों को लेकर लड़की के जूझने की बात करती है. फिल्म में कल्कि ने मुख्य भूमिका निभायी है. देव डी और ये जवानी है दीवानी जैसी सफल फिल्मों में काम कर चुकी अभिनेत्री ने ट्वीट किया, और कहा कि मैं मार्गरीटा, विद ए स्ट्रा के लिए वीकेंड में घर से बाहर आने के लिए आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं. आप ही इस तरह की फिल्मों को संभव बनाते हैं.■

शाहिद ने एकता की फिल्म छोड़ी

अभिनेता शाहिद कपूर ने एकता कपूर की फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया है. इनकार की वजह हैं अभिनेत्री सनी लियोन. सूत्रों के मुताबिक एकता कपूर ने शाहिद कपूर को अपनी फिल्म के लिए ऑफर दिया था, लेकिन शाहिद ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया. शाहिद के ना कहने की मुख्य वजह फिल्म में सनी लियोन का लीड रोल में होना है. आखिर शाहिद को सनी से क्या प्रॉब्लम है. लगता है कि वह सनी की बोल्डनेस से डर गये हैं. जल्दी ही शाहिद की शादी भी होने वाली है, इसलिए शाहिद इस तरह की फिल्मों में काम करने से बच रहे हैं. गौरतलब है कि बॉलीवुड में सनी की इमेज काफी बोल्ड है और उनकी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एक पहेली लीला में सनी काफी बोल्ड अंदाज में नजर आई हैं. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई भी की है. वहीं 8 मई को सनी की फिल्म कुछ कुछ लोचा है रिलीज होने वाली है. इसके प्रोमोज से भी यही लगता है कि इस फिल्म में भी सनी का बोल्ड लुक ही नजर आएगा. ■

शाहिद के फिल्म को ना कहने की मुख्य वजह फिल्म में सनी लियोन का लीड रोल में होना है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

feedback@chauthiduniya.com

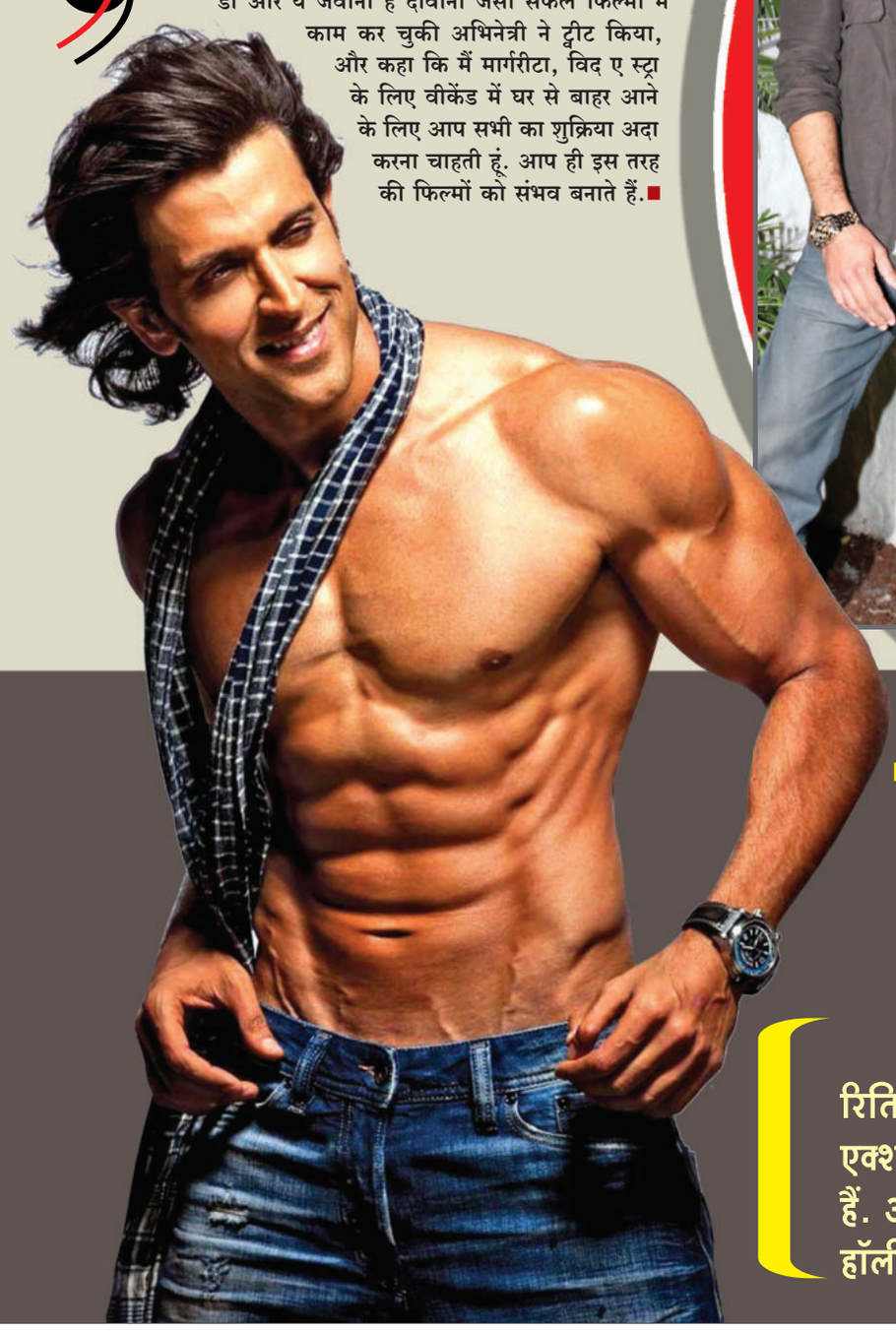

रितिक चले हॉलीवुड

रितिक शुरू से ही अपने स्टंट और अपने एक्शन के बल पर दर्शकों का दिल जीतते आए हैं. अब यह बेहद दिलचस्प होगा कि उनकी हॉलीवुड फिल्म कैसी होगी.

बॉलीवुड के सुपरहीरो रितिक रोशन जल्दी ही हॉलीवुड फिल्मों में दिखाई देंगे. फिल्म के नाम का तो अभी खुलासा नहीं किया गया है. लेकिन खबरों के अनुसार रितिक ने एक इवेंट के दौरान कहा कि वह एक हॉलीवुड फिल्म में काम करे रहे हैं. रतिक के फैंस के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है कि वे उन्हें बॉलीवुड के साथ–साथ हॉलीवुड की फिल्मों में भी देख पायेंगे. पिछले दिनों रितिक ने बयान दिया था कि हॉलीवुड के कई ऑफर्स उनके पास हैं लेकिन उन्हें कोई स्क्रिप्ट पसंद नहीं आ रही है. लेकिन अब लग रहा है कि रितिक को अपनी पसंद की स्क्रिप्ट मिल गई है. रितिक शुरू से ही अपने स्टंट और अपने एक्शन के बल पर दर्शकों का दिल जीतते आए हैं. अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि उनकी हॉलीवुड फिल्म कैसी होगी. फिलहाल वह आशुतोश गोवारिकर की फिल्म मोहनजोदड़ो की शूटिंग में व्यस्त हैं. उनका कहना है कि धूल भरी आंधियों के बीच शूटिंग करना बहुत मुश्किल काम है. हालांकि, उन्हें खुशी है कि शूटिंग तेजी से आगे बढ़ रही है. रितिक ने कहा कि हम धूल भरी आंधियों के बीच कड़ी मेहनत कर रहे हैं. फिल्म की शूटिंग बहुत मुश्किल है. अब क्या कहूं.. सेट पर मौजूद लोग गश खाकर गिर रहे हैं. बावजूद इसके हम शूटिंग कर रहे हैं. फिल्म का काम बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहा है. यह फिल्म सिंधू घाटी सभ्यता पर आधारित एक प्रेम कहानी है. इस फिल्म को गुजरात के भुज में शूट किया जा रहा है. फिल्म के एक महत्वपूर्ण दृश्य के लिए ऋतिक के नग्न होने की भी खबरें आ रही थीं लेकिन जब रितिक से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं फिल्मों में नग्न दृश्य नहीं देता.■

चौथी दुनिया बिहार झारखंड

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

04 मई–10 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

अमित शाह का चुनावी फरमान, सहयोगी दल बड़ा मुंह न खोलें

भाजपा के तेवर से दुविधा में सहयोगी

भाजपा कार्यकर्ता समागम से यह संकल्प लेकर गए हैं कि बिहार में एक बार फिर जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगे. पूरे समागम में किसी भी एक वक्ता ने यह नहीं कहा कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे. केवल और केवल भाजपा की ही बात होती रही. अब सवाल यह उठता है कि अगर केवल भाजपा की ही सरकार बनाने का टास्क दिया गया है तो फिर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के प्रति भाजपा के कैडरों का रवैया क्या होगा? क्या भाजपा के लोग पूरे मनोयोग से सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए जी जान लगाएंगे.

सरोज सिंह

बिहार में भाजपा के तल्ख तेवरों से उसके सहयोगी दलों की नींद उड़ी हुई है. सहयोगी दल लोजपा और रालोसपा के बड़े नेता तो खामोश हैं पर दूसरी पंक्ति के नेताओं के सब्र का बांध टूट रहा है. विधानसभा की टिकटों को लेकर आशंका तो शुरू से ही थी लेकिन अमित शाह के बिहार दौरे के बाद भाजपा नेताओं के सुर बदले हुए हैं. सहयोगी दलों को पहला जोरदार झटका भाजपा के कार्यकर्ता समागम में लगा. ऐतिहासिक समागम में लगभग सभी बड़े वक्ताओं ने साफ कहा कि दो तिहाई बहुमत से बिहार में भाजपा की सरकार बनाना हम सब लोगों का लक्ष्य होना चाहिए. बहुप्रचारित कार्यकर्ता समागम को बिहार में भाजपा का चुनावी आगाज माना जा रहा है. खुद भाजपा ने कहा कि कार्यकर्ता समागम से चुनाव प्रचार का शंखनाद हो गया है. अब पूरे बिहार में कार्यकर्ता घूम-घूम कर नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों को लोगों को बता रहे हैं. भाजपा कार्यकर्ता समागम से यह संकल्प लेकर गए हैं कि बिहार में एक बार फिर जंगलराज की वापसी नहीं होने देंगे. पूरे समागम में किसी भी एक वक्ता ने यह नहीं कहा कि हम अपने सहयोगी दलों के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे. केवल और केवल भाजपा की ही बात होती रही. अब सवाल यह उठता है कि अगर केवल भाजपा की ही सरकार बनाने का टास्क दिया गया है तो फिर सहयोगी दलों के उम्मीदवारों के प्रति भाजपा के कैडरों का रवैया क्या होगा? क्या भाजपा के लोग पूरे मनोयोग से सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए जी जान लगाएंगे.

भाजपा प्रवक्ता सुधीर शर्मा सफाई देते हैं कि समागम भाजपा का था तो जाहिर है बात भाजपा की ही होगी. जहां तक सवाल सहयोगी दलों का है तो उनका हम पूरा सम्मान करते हैं और उचित समय पर सीटों के तालमेल पर उनसे बात की जाएगी. इतना तय है कि भाजपा किसी भी कीमत पर जंगल राज को वापस नहीं आने देगी. हमलोगों ने सालों-साल इसके खिलाफ संघर्ष किया है इसलिए रणनीतिक रूप से जो कारगर कदम होगा वह उठाया जाएगा पर जंगल राज कभी नहीं. समागम का मामला अभी ठंडा ही पड़ रहा था कि शाहनवाज हुसैन ने यह कहकर सहयोगी दलों की सांस रोक दी कि भाजपा अपने बलबूते बिहार में सरकार बनाने में सक्षम है.शाहनवाज के इस बयान के बाद एक बार फिर अटकलों का बाजार गर्म है. जानकार सूत्र बताते हैं कि भाजपा अभी केवल अपने सहयोगियों की ताकत और उनकी कमजोरियों की टोह ले रही है. फैसले के स्तर पर अभी कोई बात नहीं हुई है. एक दबाव की राजनीति के तहत इस तरह के बयान भाजपा नेता दे रहे हैं ताकि सहयोगी दल टिकट को लेकर ज्यादा बड़ा मुंह न खोलें. इसलिए बीच-बीच में इस तरह की बातें हो जा रही हैं. चूंकि भाजपा भी अभी बिहार की चुनावी रणनीति को लेकर पूरी तरह साफ नहीं है इसलिए फिलहाल भ्रम की स्थिति बनी रहे यही बेहतर होगा. ऐसा भाजपा मान रही है. सहयोगी दल जितना बड़ा दावा करेंगे भाजपा के अंदर खींचतान उतनी ही बढ़ेगी. भाजपा को पहले अपनी पार्टी के अंदर की गुटबाजी को दूर कर एक साफ चुनावी लाइन खींचनी है ताकि वह बड़े कद के साथ अपने सहयोगियों से हां या ना के अंदाज में बात कर सके. जानकार सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ने अपनी दो दिनों की बिहार यात्रा में यह मंत्र दिया है कि ऐसे जतन हों कि सूबे में भाजपा सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे दल का मोहताज न होना पड़े. अमित शाह ने लोकसभा का उदाहरण देते हुए कहा कि हम अपने सहयोगियों का भी सम्मान करें लेकिन भाजपा के हित की कीमत पर नहीं. केंद्र में अपने बलबूते सरकार बनाने के बावजूद भाजपा ने सहयोगी दलों को साथ बनाए रखा है. लेकिन इतना अमित शाह ने जरूर कहा कि किसी की भी मनमानी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे. पहला लक्ष्य सीटें जीतना और सरकार बनाना है. केवल आदर भाव दिखाने के लिए सीटों को बर्बाद नहीं करने दिया जाएगा. अमित शाह के टास्क के बाद भाजपा ने फिलहाल अपने सहयोगी दलों से बातचीत का इरादा त्याग दिया है. अब संसद के सत्र के बाद ही इसपर कोई बात संभव है. लेकिन जानकार सूत्र बताते हैं कि एक लोकसभा सीट पर छह विधानसभा सीट का फार्मूला इस बार नहीं चलेगा. ज्यादा साफ कहा जाए तो कोई फार्मूला बनेगा ही नहीं. बस जीतने वाली सीटों का गहन मंथन होगा. अगर भाजपा को लगेगा की फलां सीट सहयोगी दल के उम्मीदवार ही निकाल सकते हैं तभी वह सीट भाजपा छोड़ेगी वरना उस सीट पर पहला दावा भाजपा का ही रहेगा.

इधर जीतन राम मांझी प्रकरण ने भी रामविलास पासवान और उपेंद्र कुशवाहा की बारगेनिंग पॉवर को काफी कम कर दिया है. यही वजह है कि भाजपा ने जीतन राम मांझी के लिए दरवाजे बंद नहीं किए हैं. विकल्प खुला है और तत्कालीन राजनीतिक हालात के मद्देनजर भाजपा कोई भी फैसला ले सकती है. यह मांझी प्रभाव ही है कि रामविलास पासवान अब बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सीटों का बंटवारा कोई मुद्दा है ही नहीं. असली मुद्दा जंगल राज को रोकना और बिहार का विकास है. इसलिए सीटों को लेकर एनडीए में कोई परेशानी नहीं होने वाली है. लोजपा के सूत्र भी इस ओर इशारा कर करे हैं कि सीटों को लेकर रामविलास भाजपा के साथ कोई टकराव नहीं करने वाले हैं. रामविलास पासवान के नाते रिश्तेदार और कुछ करीबी नेता टिकट पा जाएं लोजपा इसी में संतुष्ट हो जाएगी. जहां तक बात रालोसपा की है तो यह पार्टी अंदर से ही कमजोर हो रही है और इसका आभास बखूबी भाजपा नेताओं को है इसलिए इसे सस्ते में निपटाने में भाजपा को कोई दिक्कत नहीं आने वाली है. यही वजह है कि भाजपा ने टिकटों के बंटवारे का मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है. भाजपा टिकट बंटवारा अपनी शर्तों पर करेगी और इसमें वह किसी भी दबाव में नहीं आएगी.■

feedback@chauthiduniya.com

सीतामढ़ी - शिवहर

महाविलय से होगा भाजपा का नुकसान

देश से लेकर प्रदेश तक वैसाखी पर चलने वाली राजनीति ने महाविलय के साथ ही बिहार की राजनीति को नयी दिशा दे दी है. बिहार की राजनीति के दो योद्धा अबकी बार एक साथ भाजपा को घेरने की तैयारी में लग गये है. इसमें जदयू के नीतीश कुमार व राजद के लालू प्रसाद मुख्य रूप से है. इसके अलावा दिल्ली की सत्ता गंवा चुकी कांग्रेस भी अपना बदला बिहार के चुनावी समर में भाजपा से लेने की फिराक में है. आलम है कि 2015 में होने वाले बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय व विधानसभा चुनाव की तैयारी भी इस नजरीये से शुरू हो गई है.

महाविलय की घोषणा के बाद सीतामढ़ी स्थित परिसदन में प्रदेश राजद अध्यक्ष डॉ. रामचंद्र पूर्वे ने कहा कि देश में धर्मनिरपेक्ष व समाजवादियों को एकजुट करने का प्रयास फलीभूत हो गया है. नतीजा है कि भाजपा में भारी घबराहट होने लगी है. जबकि दूसरी ओर जदयू-राजद व कांग्रेस में उत्साह का प्रवाह हो गया है. जिसका परिणाम 2015 के चुनाव में सामने आयेगा. कुल मिलाकर उनका इशारा महाविलय की मजबूती की ओर था. इस बात से इनकार नही किया जा सकता है कि महाविलय की घोषणा के बाद अगर भाजपा का चुनावी जादुई पिटारा काम नहीं करता है तब सीतामढ़ी- शिवहर जिले में भाजपा को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. पूर्व मंत्री रघुनाथ झा ने महाविलय को देश की ऐतिहासिक घटना करार दिया. उन्होंने कहा कि जब-जब देश संकट में पड़ा है. समाजवादी एक साथ हुए हैं. लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के चुनावी वादों पर इशारा करते हुए कहा कि सांप्रदायिक शक्ति सत्ता में आने के साथ ही अपनी वादा भूल गयी. इसका खामियाजा उसे आगामी चुनाव में भुगतना होगा.

पूर्व मंत्री सूर्यदेव राय, जिला राजद अध्यक्ष मो शफीक खां, प्रदेश युवा राजद उपाध्यक्ष दिलीप राय, तारकेश्वर यादव, गणेश गुप्ता, हरिओम शरण नारायण, चंद्रजीत प्रसाद यादव व सन्नी कुमार समेत अन्य की मौजूदगी में नेताओं ने साफ तौर पर पार्टी कार्यकर्ताओं से महाविलय को स्वीकार कर भाजपा के तेज को बिहार में निस्तेज करने की अपील की. जहां तक स्थानीय राजनीति का सवाल है तो इतना साफ है कि महाविलय के बाद वोटों के समीकरण में व्यापक अदला-बदली की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है. चुनावी गणित का आकड़ा बैठाने वालों की मानें तो सीतामढ़ी व शिवहर जिला में अब जदयू व राजद के साथ कांग्रेस को पहले विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव में अपनी ताकत का एहसास विरोधी पार्टी को कराना होगा. दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने के बाद भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी के चुनावी समर में आने के बाद कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ने लगी है. पंचायतों के प्रतिनिधियों को भी अपने निर्णय को साफ तौर पर सामने लाने का बेहतर मौका हो सकता है. प्रतिनिधियों के सामने भी विकल्प चुनने का अवसर आ गया है. एक ओर पंचायत के विकास का मामला है तो दूसरी ओर प्रतिनिधियों के मान-सम्मान व स्वाभिमान की रक्षा का सवाल है. चर्चा यह भी जोर पकड़ने लगी है कि अबकी बार पंचायत व नगर निकाय के साथ नगर परिषद के प्रतिनिधि भी दलगत व जातिगत भावनाओं से उपर उठकर चुनाव में अपना योगदान देने का मन बनाने लगे है. अब सच्चाई क्या है? इसको जानने के लिए जिले की अगली राजनीति पर नजर रखने की आवश्यकता है. इतना तो साफ है कि महाविलय का अगर आधा असर भी कायम रहा तो भाजपा को नुकसान से बचने की जुगत करनी होगी.■

– वाल्मीकि कुमार

एक नज़र

बुक फेयर में जमकर खरीददारी

मोतिहारी शहर के बेलबनवा में संचालित इमानुएल स्कूल के प्रांगण में स्कोलास्टिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बुक फेयर का आयोजन किया गया. बुक फेयर में छात्रों ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया और अपने मन पसन्द की किताबें खरीदी. प्राचार्य श्रवण कुमार ने बताया कि छात्र-छात्राओं के बीच पढ़ने की ललक पैदा करना व इनकी स्किल डेवलप कराना इस आयोजन का मकसद है. उन्होंने बताया कि हर तरह की किताबें सजाई गयी हैं, जहां छात्रों की काफी भीड़ उमड़ी हुई है. पुस्तकालय की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है. छात्र-छात्राएं लेखकों को जान सकें, इसकी भी व्यवस्था की गयी है. उन्होंने कहा कि बच्चों को पुस्तकों के लेखकों से रूबरू कराना हमारी पहली प्राथमिकता में शामिल है. ताकि वे अपने ज्ञान की वृद्धि कर पुस्तकों के मानदण्ड को समझ सकें. ऐसा होने पर जहां छात्र-छात्राओं का मानसिक विकास होगा, वहीं अन्य कई लाभ भी मिलेंगे. इससे पूर्व कार्यक्रम का उद्घाटन मानवाधिकार उल्लंघन नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक ज्ञानेश्वर गौतम ने किया. मौके पर कंपनी की ओर से अभिषेक कुमार, दीपक कुमार, शिक्षक राजेश कुमार, मधुबाला, प्रिय रोशनी आदि उपस्थित थे.

जलसा आयोजित

इस्लाम की असली पहचान ईमान है और ईमान की बुनियाद पर ही इस्लाम की नींव रखी गयी है. उपरोक्त विचार उत्तर प्रदेश के इटावा से आये मफ्ती दानिश चतुर्वेदी के हैं. वे रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के बेला गांव में आयोजित एक दिवसीय जलसा कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. अपने व्याख्यान के दौरान दानिश ने लोगों से इस्लाम की बात के साथ-साथ देश-दुनिया के ताजातरीन हालात पर विस्तार से चर्चा की. उन्होंने जलसे में मौजूद लोगों से अंग्रेजी पढ़ाई के साथ साथ इस्लाम की तालीम पर जोर देते हुए कहा कि आज का जो दौर चल रहा है उसमें शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता है, सभी मुसलमानों के लिए जरूरी है. जलसे की शुरुआत उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से आये मौलाना हैदर के नात-ए-कलाम की साथ हुई. जलसे की अध्यक्षता प्रोफेसर नसीम अहमद ने की जबकि मौके पर मौलाना दाउद साहब, मौलाना बदरुल हसन, कमर रेयाजी, मौलाना गुफरान साहब, हाफिज मोबारक हुसैन, मौलाना फिरदौश समेत मोरु तारिक जमाल, मोरु नेशात, शेख वहाब आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये.■

– इंतेज़ारुल हक़

सीतामढ़ी

प्रत्याशी के समर्थन में गोलबंदी शुरू

वाल्मीकि कुमार

लंबे अर्से से विधान परिषद चुनाव को लेकर संभावित प्रत्याशी की सूचि में शामिल रहने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं में अब स्थिरता आने लगी है. दलगत आधार पर चुनाव नहीं होने के बाद भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी ही इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाने वाले हैं. भाजपा-जदयू गठबंधन में दरार के पश्चात लोकसभा चुनाव के बाद होने वाला यह पहला चुनाव होगा. पिछले विधान परिषद चुनाव में एक साथ चुनावी समर में हुंकार भरने वाली पार्टी इस बार अलग-अलग मैदान में है. पिछले दिनों जदयू समर्थित प्रत्याशी राजेश चौधरी के नाम की घोषणा बतौर प्रत्याशी होने के साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच गोलबंदी शुरू होने लगी है. पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकार में स्वतंत्रता से लेकर उनकी सुरक्षा एवं क्षेत्र का सर्वांगीण विकास का भरोसा देने का दौर एक बार फिर जोरदार तरीके से आरंभ हो गया है.

सीतामढ़ी एवं शिवहर जिला में विधान परिषद स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनावी पताका चारों ओर लहराने लगा है. खास तौर पर अबकी बार भाजपा-जदयू समर्थित प्रत्याशी को आमने-सामने भिड़ने की पूरी संभावना बन रही है. वैसे कुछ प्रत्याशी धन बल के बूते चुनावी फिजा में अपना चेहरा भी चमकाने की फिराक में लगे हैं. अब आलम यह है कि चारों ओर पंचायत प्रतिनिधियों का मोलजोल किये जाने की चर्चा भी जोर पकड़ने लगी है. चर्चा पर यकीन करें तो कुछ लोग दलगत होकर भी दल समर्थित प्रत्याशी को मात देने के लिए अपनी चुनावी औकात दिखाने को तैयार हैं. बता दें कि अब तक भाजपा से विधान पार्षद बैद्यनाथ प्रसाद और जदयू से रून्नीसैदपुर की विधायक गुड्डी देवी का पति राजेश चौधरी का नाम पार्टी समर्थित प्रत्याशी के रूप में स्पष्ट हो गया है, जबकि भाजपा का ही प्रदेश कार्यसमिति सदस्य विश्वजीत पाठक पार्टी में रहने के साथ ही चुनावी समर में अपनी दावेदारी को लेकर चुनावी चौपाल सजा रहे हैं.

उनके अलावा राजद से प्रदेश युवा उपाध्यक्ष दिलीप राय, पूर्व सांसद सीताराम यादव की पुत्रवधू सह पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष उषा किरण एवं वर्तमान जिला परिषद अध्यक्ष इंद्रानी देवी का पति लालबाबू राय भी पार्टी का समर्थन पर चुनावी समर में आने को आतुर है. चर्चाओं पर भरोसा करें तो नये गठबंधन के तहत अगर जदयू समर्थित राजेश चौधरी की घोषणा बतौर प्रत्याशी हुई है, तब गठबंधन दल के अन्य कार्यकर्ताओं को अब विधानसभा चुनाव पर नजर टिकाने का वक्त आ गया है. कारण कि विधान परिषद चुनाव के बाद फिलहाल बिहार विधानसभा का चुनाव ही होने वाला है. संभव है इस चुनाव में बेहतर कार्य कर दिखाने वाले कार्यकर्ताओं को अगली बार मौका मिल जाये. चुनावी गुणा-भाग करने वालों की मानें तो इस बार बिहार में जदयू व भाजपा गठबंधन के बीच सीधा चुनावी मुकाबला होने वाला है. कारण कि एक ओर राज्य के दो राजनीतिक धुरंधर सीएम नीतीश कुमार व पूर्व सीएम लालू प्रसाद के राजनीतिक अस्तित्व एवं राज्य के विकास का सवाल है तो दूसरी ओर केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा की नजर बिहार की राजनीति पर होना है. वैसे चुनाव को लेकर उतार-चढ़ाव का दौर शुरू है.

आने वाले दिनों में अभी और भी राजनीतिक बदलाव की संभावनाओं को खारीज नहीं किया जा सकता है. फिलहाल चल रही राजनीतिक बयार का आलम है कि अब दलगत कार्यकर्ता पार्टी समर्थित प्रत्याशी को जीत दिलाने को लेकर प्रयास शुरू कर दिया है. पिछले दिनों सीतामढ़ी के डुमरा रोड स्थित परिसदन में जदयू जिलाध्यक्ष राम जीवन प्रसाद की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई, जिसमें राजेश चौधरी को पार्टी समर्थित प्रत्याशी घोषित किये जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की गयी. प्रत्याशी को कार्यकर्ता व पंचायत प्रतिनिधियों ने माला पहना कर बधाई दी.

अमरनाथ गुप्ता

हरी यादव

किरण गुप्ता

सज्जन सुंदरका

विशाल गुप्ता

साथ ही चुनाव में जीत दिलाने का भरोसा दिलाया. इस दौरान राजेश ने पार्टी कार्यकर्ता अनिल कुमार सिंह चुम्मन, सुरेश यादव, शोभा देवी, संजीव कुमार, राहुल कुमार सिंह व सुरेंद्र पटेल समेत अन्य की मौजूदगी में पंचायत प्रतिनिधियों व पार्टी कार्यकर्ताओं को उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष का भरोसा दिलाया. कहा कि विकास की नयी परिभाषा सीतामढ़ी व शिवहर जिला में गुंजेगी. इसके साथ ही सीतामढ़ी व शिवहर जिला में चुनाव अभियान जोर पकड़ लिया है. जिला जदयू उपाध्यक्ष भरत प्रसाद व जदयू सेवादल के अध्यक्ष दिनेश प्रसाद यादव का कहना है कि पार्टी संगठन का फैसला कार्यकर्ता के मनोबल को बढ़ा दिया है.

इसका नतीजा चुनाव बाद बेहतर परिणाम के तौर पर आयेगा. डॉ अमरनाथ गुप्ता का कहना है कि पंचायत व नगर निकाय के मतदाता इस चुनाव में अपना अहम योगदान देने को तैयार है. पार्टी की किरण गुप्ता कहती है कि नया गठबंधन बिहार में नया सवेरा लेकर आयेगा. जदयू उपाध्यक्ष सज्जन सुंदरका का मानना है कि सीतामढ़ी व शिवहर जिला में पंचायत प्रतिनिधि व नगर निकाय के सदस्य जदयू गठबंधन के साथ है. युवा जदयू उपाध्यक्ष हरि यादव का कहना है कि अबकी बार जाति व पार्टी की भावना जदयू गठबंधन के साथ है. शिवहर जिला युवा जदयू अध्यक्ष विशाल गौरव का कहना है कि विकास के प्रति सजग प्रतिनिधि का चयन ही पंचायत प्रतिनिधियों की पहली प्राथमिकता है. कुल मिलाकर देखा जाये तो विधान परिषद चुनाव को लेकर फिलहाल जदयू में खुशी का माहौल है. अब भाजपा समर्थित समेत अन्य प्रत्याशी कितना जोर लगाते हैं, इस पर सभी की नजर है.■

feedback@chauthiduniya.com

स्कूल बस पलटी, प्राथमिकी दर्ज

दुर्घटनाग्रसत हुई बस मुजफ्फरपुर के भोला भंडारी ट्रांसपोर्ट के होने की बात बताई गई है. जो संविदा पर डीएवी स्कल में अपनी सेवा दे रहा है. बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक रोहित कुमार व इपचालक सोनू कुमार फरार बताया जा रहा है.

चौथी दुनिया ब्यूरो

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के केडीएस कॉलेज के बगल में अगुवानी महेशखूंट पथ पर स्कूल बस पलटने के मामले में स्थानीय थाना में एक मामला दर्ज किया गया . जिसमें दुर्घनाग्रस्त बस के चालक व उप चालक को नामजद किया गया है. दुर्घटनाग्रसत हुई बस मुजफ्फरपुर के भोला भंडारी ट्रांसपोर्ट के होने की बात बताई गई है. जो संविदा पर डीएवी स्कल में अपनी सेवा दे रहा है. बस के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद चालक रोहित कुमार व इपचालक सोनू कुमार फरार बताया जा रहा है. सोमवार को हादसे के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मची रही. प्राचार्य ने कहा कि घटना के बाद से चालक व इपचालक दोनों गायब हो जाना सम्भ समाज के लिए शर्म की बात है.

जिप अध्यक्ष सह पूर्व राजद लोक सभा प्रत्याशी कृष्णा देवी यादव गोगरी रेफरल अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चे व इनके अभिभावकों से मिले. इन्होंने गहरी संवेदना प्रकट करते हुए घटना पर अफसोस जताया और ईश्वर से बच्चे की शीघ्र स्वस्थ्य होने की कामना की. वहीं एसडीओ संतोष कुमार से भी बातचीत कर घटना की जांच करवाने की मांग की. वही इस घटना पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अखिल कुमार राय इर्फ मंटू राय जिप सदस्य पिंकु देवी, लोजपा के महिला सेल राष्ट्रीय इपाध्यक्ष सह मगध महिला कॉलेज पटना के प्रो0 सुहैली मेहता ने इस घड़ी में इश्वर से बच्चे की ठीक होने की कामना की. वहीं प्रखंड राजद अध्यक्ष अखिलेश्वर दास ने इस घटना पर दुख प्रकट किया एवं बच्चे की जल्द ठीक होने की.■

feedback@chauthiduniya.com

देवघर

प्राइवेट नर्सिंग होम बने लूट का अड्डा

रणजीत झा

देवघर शहर में कई प्राईवेट नर्सिंग होम इन दिनों लूट का अड्डा बने हुए हैं जिस पर जिला प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं है. गरीब मरीजों से भी मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है. फीस वसूलने में मरीजों के परिजनों को कई तरीके से भय भी दिया जाता है ताकि डर के मारे बेचारे मरीजों के परिजन किसी भी तरह से जुगाड़ कर फीस चुका सके. फीस चुकाने के चक्कर में कभी-कभी ऐसे गरीब परिजन घर के बर्तन आदि भी बेचने को मजबूर हो जाते हैं. हद तो तब हो जाती है जब कभी मरीजों की मौत हो जाने पर लाश तक परिजन को प्राईवेट नर्सिंग होम वाले बिना फीस चुकाए नहीं सौंपते हैं. हाल ही में एक सर्वे में रिपोर्ट आ चुकी है कि बिहार झारखंड के प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक बिना आवश्यकता के ही कई मेडिकल जांच, एक्स रे एवं अल्ट्रासाउन्ड मरीजों का करा रहे हैं जिसका भारी खर्च परिजनों को उठाना पड़ता है. बता दें कि इस प्रकार की जांच आदि में हजारों रुपये के बिल भुगतान करने पड़ते हैं. इसके अलावा मरीजों की हैसियत के हिसाब से बेड चार्ज, डाक्टर फीस एवं अन्य विशेषज्ञों की सलाह फीस साथ ही नर्सिंग चार्ज भी जोड़ कर लिया जाता है. इसके बाद मरीजों को महंगे दवा का भी बोझ झेलना आम बात हो गई है. सूत्रों की मानें तो पैथॉलोजी जांच, एक्स रे एवं अल्ट्रासाउन्ड के क्लीनिकों के साथ दवा दुकानदारों से नर्सिंग होम संचालक कमीशन भी वसूलना नहीं छोड़ते हैं. सभी जगह निर्धारित कमीशन पर सेटिंग है. लाखों रुपये खर्च के बावजूद सदर अस्पताल की बदहाली के कारण जिले भर के मरीजों को प्राइवेट नर्सिंग होम आना मजबूरी हो गया है. नर्सिंग होम वाले मरीजों से वसूले गई फीस की पक्की रसीद भी नहीं देते हैं.

प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों में कई सरकारी सेवा में चिकित्सक पद पर कार्यरत होते हुए भी बरोकटोक लूट को अंजाम दे रहे हैं. ऐसे सरकारी चिकित्सकों ने अपना तबादला सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य उप केन्द्रों में करा लिया है जहां कभी कभार जाकर नौकरी की औपचारिकता पूरी कर लेते हैं बाकि स्वास्थ्य विभाग के उच्च पदाधिकारी की सेटिंग प्रक्रिया सर्वविदित है. कुछ चिकित्सक सदर अस्पताल में पदस्थापित होते हुए दबंगई से रोगियों को प्राईवेट में इलाज कराने का सलाह देने में जरा भी नहीं हिचते हैं. अधिकांश प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक मोटी कमाई देख कर सरकारी नौकरी छोड़ चुके हैं ताकि आराम से बिना सरकारी निगरानी के मनमाने तरीके से मरीजों का दोहन किया जा सके. आए दिन प्राइवेट नर्सिंग होम में मरीजों के साथ कई घटनाएं घटती रहती है जिससे मानवता तार-तार हो रही है लेकिन जिला प्रशासन एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिर्फ जांच कर दोषी पर कार्रवाई का आश्वासन भर देकर मामला रफा-दफा कर दिया जाता है.

आश्चर्य है कि देवघर में अधिकांश प्राइवेट नर्सिंग होम अबतक क्लीनिकल इस्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत बिना रजिस्ट्रेशन कराए ही चल रहे हैं. सरकार की ओर से प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश के साथ नियम भी निर्धारित किए गए हैं परन्तु देवघर में इन नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं. सिविल सर्जन डॉ. दिवाकर कामत के अनुसार कई बार प्राइवेट नर्सिंग होम संचालकों को रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना भेजी गई है परन्तु परिणाम सार्थक नहीं है. सिविल सर्जन डॉ. दिवाकर कामत ने यह भी बताया कि नियम विरुद्ध काम करने वालों के लिए सरकार की ओर से जिला स्तर पर कार्रवाई एवं दंड प्रावधान का मार्गनिर्देशन अबतक नहीं मिल पाया है जिसके कारण समस्या बनी हुई है. सरकार की ओर से प्राइवेट नर्सिंग होम के लिए शुल्क व टैक्स भी निर्धारित किए गए हैं परन्तु बिना रजिस्ट्रेशन के ही चल रहे प्राइवेट नर्सिंग होम राज्य सरकार को भारी आर्थिक नुकसान के साथ सरकारी राशि का गबन भी कर रहे हैं.■

feedback@chauthiduniya.com

देवघर के प्रसिद्ध समाजवादी नेता एवं कर्पूरी लोहिया विचार मंच के संस्थापक अनिरुद्ध आजाद ने कहा कि कभी डॉक्टर को भगवान कहा जाता था लेकिन आज डॉक्टर गरीबों को लूटने वाले हो गए हैं. लुटेरे लोगों को रात में लूटते हैं लेकिन डॉक्टर दिन में ही मरीजों के परिजनों को लूटते हैं. श्री आजाद ने बताया कि कोयला, लोहा एवं शिक्षा माफिया के बाद अब चिकित्सा माफिया का राज कायम हो गया है. बड़ी-बड़ी बहुमंजिली इमारतों का करोड़ों खर्च से निर्माण कर नर्सिंग होम बन रहा है. इन चिकित्सा माफिया की संपत्ति एवं आय की जांच होनी चाहिए. अंत में श्री आजाद ने कहा कि सरकार को गरीबों, मध्यमवर्गीय व असहायों को लुटने से बचाने के लिए कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है.

– अनिरुद्ध आजाद
संस्थापक, कर्पूरी लोहिया विचार मंच एवं समाजवादी नेता

सिविल सर्जन डॉ. दिवाकर कामत ने इस संबंध में बताया कि जिले में प्राइवेट नर्सिंग होम संचालन के लिए राज्य सरकार के नियमानुसार सिविल सर्जन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, सभी को नोटिस भेज दिया गया है, कुछ ही नर्सिंग होम संचालक ने अबतक रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन दिए है. अधिकांश प्राइवेट नर्सिंग होम संचालक इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जिनपर कार्रवाई की जाएगी. सरकारी हो या प्राईवेट डॉक्टर सभी को प्राइवेट क्लीनिक के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सरकार ने नियमानुसार ही मरीजों से सभी प्रकार के फीस ले सकेंगे.

– डॉ. दिवाकर कामत
सिविल सर्जन, देवघर

अन्य ख़बरें

बोधगया के लिए समस्या बने भिखारी

बोधगया में आने वाले विदेशी पर्यटकों को भिखारियों के झुंड से काफी परेशानी होती है. भिखारी बोधगया की छवि को भी खराब कर रहें हैं. यह बात महाबोधि सोसाईटी के संयुक्त सचिव व प्रभारी भंते मेधांकर ने कही है. भंते मेधांकर ने कहा कि विदेशी पर्यटकों से भीख मांगने के दौरान यहां के भिखारी जबर्दस्ती भी करने लगते हैं. जिससे विदेशी पर्यटको को काफी दु:ख होता है. जबकि सही रूप मे भिखारी को विदेशी पर्यटक भी मदद करना चाहते हैं, लेकिन भिखारी की आड़ मे अच्छे लोग भी विदेशी मुद्रा की लालच में भीख मांगने लगते हैं, जो कि गलत है.

मिला बेस्ट प्रिंसिपल का अवार्ड

ओलंपियाड फाउंडेशन एकेडेमिक काउंसिल ने दिल्ली पब्लिक स्कूल, गया के प्रिंसिपल अभिषेक को 'वेस्ट प्रिंसिपल-बिहार जोन' का अवार्ड प्रदान किया है. उल्लेखनीय है कि अभिषेक कुमार के निर्देशन में डीपीएस गया के छात्र-छात्राओं ने बहुत कम समय में ओलम्पिया डमें बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है.2014 में झारखण्ड राज्य चैम्बर आफ कामर्स द्वारा दिल्ली पब्लिक स्कूल गया को आधुनिक एवं उन्नत तकनीक के प्रयोग के लिए वेस्ट स्कूल का खिताब मिला था. बिहार में सहारा समय की ओर से भी डीपीएस गया को अच्छे स्कूल के लिए अवार्ड मिला था. अभिषेक कुमार ने इस सफलता के लिए अपने शिक्षकों के साथ-साथ छात्र-छात्राओं की मेहनत का प्रतिफल बताया है.

आबिद बना 'सिटी विनर'

स्पेल बी इंटरनेशल द्वारा जिला स्तर पर आयोजित स्पेंलिंग प्रतियोगिता में दिल्ली पब्लिक स्कूल के छठवीं कक्षा के छात्रआबिद रजा काजमी को सिटी विनर घोषित किया गया. गया के कर्क व्यू स्कूल में आयोजित स्पेल बी प्रतियोगिता के संकेड लेबल में गया के विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया. अब आविद राज्य स्तर पर होने वाले तीसरे राइंड के स्पेल बी प्रतियोगिता में भाग लेगा. प्राचार्य अभिषेक कुमार ने इस सफलता पर आविद रजा काजमी को बधाई देते हुए उसके उज्वल भविष्य की कामना की है.

डीपीएस का शानदार प्रर्दशन

दिल्ली पब्लिक स्कूल, गया के छात्र- छात्राओं ने साइंस ओलम्पियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित साइबर, विज्ञान व गणित ओलम्पियाड में राज्य स्तर पर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किया है. वर्ष 2014-15 कें साइबर ओलम्पियाड के द्वितीय चरण में कक्षा चार के अदित्य किशोर राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया है. उसे गोल्ड मेडल, प्रमाण पत्र तथा पुरस्कार राशि प्रदान की गयी है. इसी में कृष ने चौथा तथा कक्षा तीन की प्रगति रागिनी नें दसवां स्थान प्राप्त किया है. गणित ओलम्पियाड में छठी कक्षा के अपुपम कुमार को राज्य में सातवां स्थान प्राप्त किया है. इससे पूर्व भी ओलम्पियाड कें प्रथम चरण में डीपीएस के छात्र-छात्राओं ने अच्छा प्रदर्शन किया था. राज्य स्तर पर यहां के में 11 छात्र-छात्राओं ने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है.

– सुनील सौरभ

श्री राम कथा का आयोजन

जगत जननी मां जानकी की पावन जन्मस्थली पुनौरा धाम में नौ दिवसीय श्रीराम कथा का आयोजन किया गया. पद्म विभूषण चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर जगदगुरु रामानंदाचार्य श्रीराम भद्राचार्य जी ने पूर्व की भांति इस साल भी जानकी नवमी के अवसर पर कथा का श्रीगणेश किया. नौ दिवसीय कथा की कडी में पिछले साल जगदगुरु ने एक भव्य प्रेक्षागृह का निर्माण कराये जाने की अवश्यकता पर जोर दिया था. इस कार्य को पूर्ण कराने में पूर्व पर्यटन मंत्री सह नगर भाजपा विधायक सुनील कुमार पिंटू ने अहम योगदान दिया. अब सीतामढी के पुनौरा धाम स्थित सीता कुंड के पश्चिमी भाग में बालरूप सीता मंदिर का निर्माण कराया जाना है. कार्यक्रम में स्थानीय लोगों के अलावा भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन होने लगा है.

– विकास

सामाजिक कार्यो को मिल रहा बढ़ावा

सीतामढ़ी नगर कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सीमा गुप्ता राजनीति के साथ जिले में सामाजिक कार्य को बढ़ावा देने में लगी है. एक ओर जन समस्याओं को लेकर पार्टी के बैनर तले संघर्ष करती है, तो दूसरी ओर समाज की महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने को लेकर विभिन्न प्रकार का कार्यशाला का आयोजन कर रही है. पिछले दिनों तकरीबन सवा सौ महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने को लेकर ब्यूटिशियन कोर्स कार्यशाला का आयोजन करायी. कार्यक्रम का विधिवत इदघाटन जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विमल शुक्ला ने की. कार्यक्रम के मौके पर जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र कुमार तिवारी समेत अन्य थे.

– ब्रजेश

गोगरी स्थित कार्यालयों का निरीक्षण

गोगरी अनुमंडल क्षेत्र के गोगरी के निरीक्षण के दौरान मुंगेर के प्रमंडलीय आयुक्त सुनील कुमार सिंह ने कहा कि पंचायत की भी कुछ योजनाओं को देखने आयुक्त ने डीएम एवं एसडीओ के साथ गोगरी नगर पंचायत के अन्तर्गत बड़ीचक स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र संख्या-229 पर गये सेविकाएं गीता देवी इपस्थित थी. स्थानीय लोगों से केन्द्र के खुलने एवं पोषाहार वितरण करने से संबंधित पूछा. जिस पर स्थानीय वार्ड पार्षद विजय पंडित एवं अन्य ग्रामीणों ने कहा कि इस केन्द्र की स्थिति संतोषप्रद है. आयुक्त मदारपुर स्थित पंचायत भवन पहुंचे जहां पंचायत के मुखिया एवं पंचायत से कमरे का ताला खुलवाकर निरीक्षण कर योजनाओं के बारे में जानकारी ली. बीडीओ रंजीत कुमार ने कहा कि गोछारी में पंचायत सरकार भवन निर्माण हो रहा है. आयुक्त ने गोछारी जाकर सरकार भवन का निरीक्षण किया. भवन की गुणवत्ता को देखकर अविलम्ब कार्य पूरा करने का निर्देश दिया. शिरनियां गांव के प्रणव कुमार मिश्र ने आवेदन देकर कहा कि इनके पंचायत में रेणू देवी पति के नाम से फर्जी इंदिरा आवास का आवंटन किया गया है. शिकायत के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इसके अलावा समाजिक सुरक्षा पेंशन, जनशिकायत एंव आवश्यक कई फाइलों को खंगाला. अनुमंडल न्यायालय से संबंधित कई केस को भी गंभीरता से अवलोकन किया. मौके पर डीएम राजीव रौशन, एसडीओ संतोष कुमार, डीसीएलआर संजय कुमार, कार्यालय दंडाधिकारी मनोरमा देवी के अलावे कई पदाधिकारी मौजूद थे.■

–चौथी दुनिया ब्यूरो

एक नज़र

सत्याग्रह की वर्षगांठ मनायी

चम्पारण सत्याग्रह की 98 वीं वर्षगांठ पर मोतिहारी रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष गांधीवादी एवं अन्ना हजारे के अनुयायी केएल भास्कर के नेतृत्व में आमरण सत्याग्रह शुरू हुआ. सनद रहे कि 98 वर्ष पूर्व 15 अप्रैल को दिन में चार बजे गांधी जी इसी स्टेशन पर ट्रेन से उतरे थे. पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता केएल भास्कर पूर्व में गांधी की कर्म भूमि चम्पारण से बापू की जन्म भूमि पोरबंदर तक साइकिल यात्रा कर सुर्खियों में आये थे. चार वर्षो से चम्पारण की भूमि पर विभिन्न मांगों को लेकर गांधीवादी तरीके से आंदोलन चला रहे हैं. सत्याग्रह के शुभारम्भ पर उन्होंने गांधी भक्त तारकेश्वर प्रसाद एवं अन्य के साथ गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया. अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि अनिश्चितकालीन सत्याग्रह पांच सूत्री मांगों को लेकर आरंभ किया गया है. मुख्य मांगें पोरबंदर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम पूर्व समान बापूधाम मोतिहारी एक्सप्रेस करना, मुजफरपुर-नरकटियागंज रेल खण्ड का दोहरी करण, हाजीपुर-सुगौली बड़ी रेल लाइन का शीघ्र निर्माण, सीतामढ़ी-मोतिहारी रेल लाइन का शीघ्र क्रियान्वयन, पकड़ीदयाल-बैरगनिया रेल परियोजना को शीघ्र पुरा करना आदि है. मौके पर जिला संयोजक गांधी भक्त तारकेश्वर प्रसाद व पूर्व मंत्री ब्रजकिशोर प्रसाद ने कहा कि गांधी की प्रिय भूमि चम्पारण आज भ्रष्टाचार से पीड़ित है.

जिला कार्यकारी मण्डल का गठन

हिन्दू नवजागरण मंच का प्रथम जिला अधिवेशण मोतिहारी के मिस्कॉट मुहल्ला में स्थित विवाह भवन में हुआ. जिला अधिवेषन के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता प्रो. शोभाकान्त चौधरी ने की जबकि संचालन निवर्तमान जिला संयोजक संजय कुमार तिवारी ने किया. इस अवसर पर ग्यारह सदस्यीय टीम बनायी गयी और मोतिहारी नगर कार्यकारी मण्डल के तीन पदाधिकारियों को आमंत्रित सदस्य बनाया गया. जिला कार्यकारी मण्डल में गौरीशंकर पाण्डेय को जिला प्रधान, मदन शर्मा शास्त्री को उप जिला प्रधान, ज्योति पूंज को उप जिला प्रधान, दिनेश कुमार को मुख्य जिला कार्यकारी, आनन्द प्रसाद केशरी को कोष प्रमुख का पद दिया गया. इसी तरह संजय कुमार तिवारी को जिला कार्यकारी, राम मनोहर प्रसाद, ईश्वर चन्द्र प्रसाद, मुनिन्द्र मोहन पाण्डेय, प्रमोद कुमार पटेल व रवीश कुमार पाठक को जिला कार्यकारी का पद दिया गया. मोतिहारी नगर क्षेत्र के कार्यकारी मण्डल में विजय कुमार उपाध्याय को नगर प्रधान, शैलेन्द्र कुमार तिवारी को उप नगर प्रधान व अमित कुमार को मुख्य नगर कार्यकारी बनाया गया. मौके पर प्रो. राम निरंजन पाण्डेय, डॉ. उमाशंकर प्रसाद, राम चन्द्र द्विवेदी, मदन चौधरी, उपेन्द्र पाण्डेय, कुन्दन कुमार, प्रमोद पाण्डेय, धीरज कुमार तिवारी, संजय तिवारी, विष्णुकान्त सिंह, रामाकान्त शर्मा, विरेन्द्र प्रसाद, हरीफ सहनी, आलोक चन्द्रा, सुभाष गुप्ता, अरुण गिरी, अंचित सिंह, सुरेन्द्र तिवारी, अमित कुमार, रूपेश कुमार, बब्लू कुमार, जगदीश ठाकुर व रूमीत कुमार आदि ने अपने-अपने विचार व्यक्त किये.

– इंतेज़ारुल हक़

कांग्रेस की पदयात्रा

सत्ता से दूर हुए कांग्रेसी नेताओं ने बापू की कर्मभूमि पश्चिम चम्पारण के बेतिया जिला मुख्यालय स्थित बृन्दावन आश्रम की ओर प्रदेश अध्यक्ष डा. आशोक कुमार चौधरी के नेतृत्व व जिलाध्यक्ष नरेन्द्र शर्मा की अगुआई में शहर से लेकर बुनियादी विद्यालय वृन्दावन बालक परिसर में आयोजित सभा स्थल तक पद यात्रा भी हर्षोल्लास के साथ किया गया. अलबत्ता वे इस भूमि तक नहीं पहुंच पाये जहां पर मोहन दास करमचन्द गांधी ने किसानों के सहयोग से निर्मित पर्ण कुटीर से निलहों के अत्याचार से मुक्ति दिलायी थी. वर्तमान में वहां एक छत के नीचे बापू की प्रतिमा है. मजेदार बात तो यह है कि उक्त कार्यक्रम में पूर्व केन्द्रीय मंत्री जयराम रमेश अखिल भारतीय कांग्रेस के सचिव सह बिहार प्रभारी के एन शर्मा, पूर्व राज्यपाल निखिल, पूर्व मंत्री राय विश्व मोहन शर्मा, पूर्व सांसद पूर्णमासी राम, पूर्व मंत्री रामचन्द्र दास, पूर्व विधायक मनोज चौधरी बिहार प्रदेश कांग्रस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा आदि उक्त पद यात्रा में शामिल हुए, अपना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मध्य विद्यालय दुसाधपट्टी कार्यक्रम में मुक्तिनाथ उपाध्याय सुधा मिश्रा सहित जिले के तमाम कांग्रसी नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे.

कानूनी कार्रवाई की मांग

नरकटियागंज के दो चिकित्सकों डॉ नौशाद आलम और डॉ आफताब आलम की गिरतारी की घटना के इपरान्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी बेतिया ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है. इसके बाद नीमा के अधिकारियों ने जिला पदाधिकारी बेतिया से मुलाकात किया और उनसे मिलकर लौरिया के चिकित्सा पदाधिकारी तथा भाप्रसे अधिकारी सह अनुमण्डल पदाधिकारी नरकटियागंज के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है. दूसरे दिन रविवार को नीमा के चिकित्सकों ने नरकटियागंज स्थित डॉक्टर नौशाद आलम के नवजीवन क्लीनिक पर एक सम्मान समारोह अयोजित किया. जिसमें डॉ आफताब आलम और डॉ नौशाद आलम को माला पहनाकर सम्मानित किया गया. इसके बाद आयोजित प्रेस सम्मेलन में नीमा के प्रदेश सचिव डॉ. मनीष कुमार ठाकुर ने कहा कि सर्व प्रथम डॉ किरण शंकर झा की संपत्ति की जाँच कराई जाए. श्री ठाकुर ने श्री झा पर प्रशासन के साथ मिलकर दलाली करने का अरोप लगाया. नीमा के इपर्युक्त समारोह में बीएएमएस और बीयुएमएस के डॉ डीपी सिंह, डॉ लक्ष्मण कुमार, डॉ.इतेखार अहमद, डॉ. राहत हुसैन, डॉ. अंजारूल हक, डॉ एकराम, डॉ अनिल कुमार, डॉ रामलाल महतो, डॉ एके पाण्डेय, डॉ. अरविन्द कुमार मिश्र, डॉ ए रहमान, डॉ मनीषा कुमारी, डॉ सेबी फैजा, डॉ रानी मिश्रा और डॉ शबाना मुख्य रूप से शामिल हुए.

रोजगार की अपार संभावनाएं

हॉस्पीटेलिटी मैनेजमेंट के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार की अपार संभावनाएं है. कक्षा 10वीं एवं 12 वीं पास युवाओं के लिए इस क्षेत्र में सुनहरा अवसर है. उपरोक्त जानकारी देवघर स्थित नीभ एजुकेशन संस्थान के चेयरमेन के अधिकारी ने देते हुए बताया कि देश के नामी गिरामी चार एवं पांच सितारा होटलों में रसोईया, हाउस कीपींग, वेटर, फोन ऑपरेटर, रिसेप्शनिस्ट एवं कैशियर जैसे पदों पर आकर्षक वेतनमान एवं अन्य सुविधाओं के साथ रोजगार पाने के अवसर अधिक हैं. उन्होंने बताया कि सन 2002 ई. में झारखंड में शुभारंभ किया गया संस्थान अबतक सैकड़ों युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में रोजगारपरक शिक्षा देकर नौकरी पाने का अवसर प्रदान कर चुका है. देश के कोन-कोने में संस्थान के छात्र एव छात्राएं नौकरी पेशे पाकर सुखद जिंदगी जी रहे हैं जिसके कारण ही संस्थान अपनी विश्वसनीयता की पहचान बना चुका है. श्री अधिकारी ने कहा कि हॉस्पीटेलिटी प्रबंधन कोर्स करने के समय भी छात्रों को फीस का 40 प्रतिशत राशि कमाने का मौका मिलता है. नीभ एजुकेशन संस्थान में कम आय वाले परिवारों के युवा अल्प शुल्क के साथ अल्प समय में कोर्स पूरा कर रोजगार पाने के अवसर हैं. संस्थान में कम्प्यूटर एवं स्पोकेन अंग्रेजी भी सिखाया जाता है.■

– चौथी दूनिया ब्यूरो

मैं उनकी ख़ूबसूरती पर मर मिटा था

शायद सुचित्रा मन हीं मन नागमणि को पसंद करती थी. लेकिन समाज के डर से उन्होंने कभी इस बारे में किसी से कुछ कहा नहीं. शायद अपने पिता के नागमणि के प्रति आए शादी के ख्याल के बारे में उनको पता होता तो उनकी शादी पहले ही हो गई होती. लेकिन ना पिता ने कुछ कहा था और ना ही बेटी ने. पर दोनों ही मन ही मन नागमणि को पसंद जरूर करते थे. शायद इसे ही कहते हैं किस्मत.

राधिका

feedback@chauthiduniya.com

प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है
हर खुशी से हर गम से अनजाना होता है!

कुछ ऐसी ही है बिहार के राजनेता नागमणि और उनकी पत्नी सुचित्रा सिन्हा की कहानी. ये सिलसिला तब शुरू हुआ था जब नागमणि के घरवालों को लगा कि उनकी उम्र शादी लायक हो गई है और अब उनकी शादी करा देनी चाहिए. और फिर शुरू हुआ था नागमणि के लिए एक सुंदर, सुशील और गुणवान लड़की ढूंढने का सिलसिला. और तब बात आई थी सुचित्रा की. नागमणि बताते हैं कि सुचित्रा के परिवार और उनके परिवार के अच्छे संबंध थे. और जब मेरे लिए लड़की ढूंढने की सिलसिला शुरू हुआ था तब मेरे ससुर के मन में ये ख्याल आया था कि मेरी शादी सुचित्रा से करा दें. लेकिन ये ख्याल उस वक्त सिर्फ ख्याल हीं बन कर रह गया क्योंकि मेरे ससुर के मन में ये डर था कि अगर मैं इस शादी से इंकार कर देता हूं तो हमारे आपसी रिश्तों में दरार आ सकती है. इसी वजह से मेरे ससुर ने उस समय इस बारे में कोई चर्चा नहीं की और इस बात को वहीं छोड़ दिया. फिर मेरे लिए रिश्ता ढूंढने का सिलसिला जारी रहा. लेकिन ऐसा लगता है मानों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और नागमणि की शादी कहीं और तय नहीं हुई. इसी दौरान सुचित्रा के मन में कहीं ना कहीं नागमणि ने अपनी जगह बना ली थी. शायद सुचित्रा मन ही मन नागमणि को पसंद करती थी. लेकिन इस समाज के डर से उन्होंने कभी इस बारे में किसी से कुछ कहा नहीं. शायद अपने पिता के नागमणि के प्रति आए शादी के ख्याल के बारे में उनको पता होता तो उनकी शादी पहले ही हो गई होती. लेकिन ना पिता ने कुछ कहा था और ना ही बेटी ने. पर दोनों ही मन ही मन नागमणि को पसंद जरूर करते थे. शायद इसे ही कहते हैं किस्मत. लेकिन हर दिन एक सा नहीं होता. नागमणि आगे बताते हैं कि एक दिन उनके ससुर ने सुचित्रा से उसकी शादी के बारे में सवाल किया. उससे वो सारी बाते पूछीं जो एक पिता अपना बेटी से उसकी शादी के बारे में पूछता है. उन्होंने यहां तक पूछा डाला कि तुम किस लड़के से शादी करना चाहती हो तो सुचित्रा की तरफ से जवाब आया– नागमणि. तब कहीं जा कर सुचित्रा को ये पता चला कि मेरे ससुर भी सुचित्रा की शादी मुझ से करवाना चाहते थे, लेकिन कहीं मैं मना न कर दूं और हमारे रिश्ते बिगड़ न जाएं, इस डर से उन्होंने कभी भी ये बात नहीं छेड़ी थी. नागमणि कहते हैं कि सुचित्रा की खूबसूरती का मैं कायल तो था हीं और इस खूबसूरती की वजह से कहीं ना कहीं मैं सुचित्रा की तरफ आकर्षित भी था. जब मेरे ससुर को पता चला कि सुचित्रा मुझसे शादी करना चाहती है तो उन्होंने और देर नहीं की और मेरे घर रिश्ता लेकर चले आए. सब कुछ पहले से ही जाना परखा था. घर–बार हो या परिवार सब कुछ हमारे परिवार के

नागमणि बताते हैं कि सुचित्रा के परिवार और उनके परिवार के अच्छे संबंध थे. जब मेरे लिए लड़की ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ था तब मेरे ससुर के मन में ये ख्याल आया था कि मेरी शादी सुचित्रा से करा दें. लेकिन ये ख्याल उस वक्त सिर्फ ख्याल ही बन कर रह गया क्योंकि मेरे ससुर के मन में ये डर था कि अगर मैं इस शादी से इंकार कर देता हूं तो हमारे आपसी रिश्तों में दरार आ सकती है.

सामने बिल्कुल खुली किताब की तरह ही था. कहीं ना कहीं मैं भी सुचित्रा की तरफ आकर्षित था तो मैंने झट से इस शादी के लिए हां बोल दिया. मेरे हां बोलते हीं हमारी शादी तय कर दी गई. हमारी शादी 1979 में बहुत ही धूम–धाम से हुई थी. हमारी शादी को लव कम अरेंज मैरेज भी कहा जा सकता है. नागमणि अपनी पत्नी सुचित्रा बारे में बताते हुए कहते हैं कि उनकी खूबसूरती ने मुझे उनका कायल बना दिया था. वो इतनी खूबसूरत हैं जिसका कोई जोड़ नहीं है और मेरी नजर में कोई हो भी नहीं सकता है. इसके साथ साथ ही वो बहुत ही साफ दिल की हैं. सबका ख्याल रखती हैं. किसी को दुखी नहीं देख सकती, और मैं खुद को बहुत ही भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इतनी गुणवान पत्नी मिली है. नागमणि और सुचित्रा के तीन बच्चे हैं. दो बेटी और एक बेटा. दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है और बेटा इंग्लैंड में बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा है. आज दोनों अपने शादीशुदा जीवन में बहुत खुश हैं. दोनों का प्यार आज भी वैसा ही है जैसा बरसों पहले था. और दोनों हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं.■

घोड़ासहन की घटना के ज़िम्मेदार कौन

इंतेज़ारुल हक़

feedback@chauthiduniya.com

पूर्वी चम्पारण जिला मुख्यालय के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित घोड़ासहन रेलवे स्टेशन पर हुई घटना के जिम्मेदार कौन हैं?आखिर पुलिस ने आन्दोलनकारियों पर लाठियां क्यों चलाई और इसके पीछे की मंशा क्या थी.इस मुद्दे पर घटना के बाद एक लम्बी राजनीतिक बहस छिड़ी हुई है और अनेक तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं. स्थानीय लोगों ने एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से यह आन्दोलन किया था और इस आन्दोलन की सूचना पूर्व से संबधित अधिकारियों को दी थी. आन्दोलन कर रहे लोगों को क्या पता था कि इनपर लाठियां तो बरसेंगी ही साथ ही गोलियां भी खानी पड़ेगी और लोग घायल भी होंगे. खुल–आम यहां की लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ किया गया और स्टेशन परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया.एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव की मांग को लेकर यह आन्दोलन किया गया था जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए था.चूकि यह मामला रेल मंत्रालय के हाथों में है और रमा देवी यहां की सांसद हैं. रेलमंत्रालय व सांसद रमा देवी को इस बाबत अपनी ओर से पहल करनी चाहिए थी.किन्तु ऐसा नहीं हुआ और आंदोलनकारियों को समझाने के लिए न तो रेल प्रशासन ने अपनी तरफ से कोई दिलचस्पी दिखाई और न ही सांसद महोदया की ओर से कोई पहल की गयी.केवल आन्दोलनकारियों को उकसाने का काम किया गया जिसका नतीजा यह हुआ कि मामला काफी उग्र हो गया और देखते ही देखते पूरा स्टेशन परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया. जानकार बताते हैं कि रेल प्रशासन की ओर से कोई आलाधिकारी स्थल पर आ जाता तो यह घटना नहीं होती और इतने लोग घायल नहीं होते.वैसे यहां के लोगों की यह मांग कोई नई नहीं है और पूर्व में कई बार लोग आन्दोलन कर चुके हैं.यहां धरना–प्रर्दशन भी हुआ है और रेल प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा जा चुका है.यहां एक बात और भी बता देना जरूरी है कि पूर्व में इस स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनें रुकती थीं और रेलवे को काफी राजस्व भी आता था.यह स्टेशन भारत–नेपाल सीमा के निकट स्थित है

और यात्रियों के साथ–साथ विदेशी पर्यटकों का भी आगमन इस रेल मार्ग से होता है.इधर इस घटना ने यहां की राजनीति गरमा दी है और केन्द्र की मोदी सरकार व रेल मंत्रालय के खिलाफ विभिन्न पार्टियों के नेता आग उगलने लगे हैं और इसके लिए सीधे रेल मंत्रालय को सीधे जिम्मेदार ठहराने लगे हैं. जारी एक बयान में युवा जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष फैसल रहमान,जनता दलयू पूर्वी चम्पारण के जिला प्रवक्ता विशाल कुमार शाह एवं जिलाध्यक्ष प्रमोद कुमार सिन्हा इस घटना के लिए सीधे केन्द्र की मोदी सरकार व रेल मंत्रालय को दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि एक साजिश के तहत बिहार की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. इनके अनुसार, जनता की मांग जायज है और रेल मंत्रालय को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए.दूसरी तरफ भाकपा माले ने इस घटना की जांच निष्पक्ष एजेंसी से कराने की वकालत कर रही है.पुलिस फायरिंग की न्यायिक जांच करने और निर्दोष लोगों को बिना शर्त रिहा करने की मांग की है. कुल मिलाकर इस घटना पर राजनीतिक बहस जारी है और अनेक तरह के सवाल खड़े किये जा रहे हैं.दूसरी तरफ स्थानीय सांसद की खामोशी पर भी यहां सवाल उठ रही है और स्थानीय लोग इस मुद्दे पर इन्हें घेरने का प्रयास कर रहे हैं.अब सबों की नजर रेल प्रशासन पर टिकी हुई है.इतना सब कुछ होने के बाद रेल प्रशासन एक्सप्रेस ट्रेनों की ठहराव कराने की दिशा में कितना दिलचस्पी दिखाता है.■

Mob. : 9386745004, 9204791696
www.iiher.org,
Email : anilsulabh6@gmail.com

INDIAN INSTITUTE OF HEALTH EDUCATION & RESEARCH
Health Institute Rd, Beur (Near Central Jail), Patna -2.
(Recongnised by Govt. of Bihar, RCI, Govt. of India, IAP & ISPO)
AFFILIATED TO MAGADH UNIVERSITY, BODHGAYA

POST GRADUATE COURSES :

Name of Courses		Eligibility	Duration
MPT	Master of Physiotherapy	BPT	2yrs.
MOT	Master of Occupational Therapy	BOT	2yrs.

DEGREE COURSES

BPT	Bachelor of Physiotherapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BOT	Bachelor of Occupational Therapy	I.Sc (Bio)	4yrs.+6 Months of Internship
BPO	Bachelor of Prosthetic & Orthotic	I.Sc	4yrs.+6 Months of Internship
BASLP	Bachelor of Audiology & Speech Language Pathology	I.Sc	3yrs.+1 year of Internship
BMLT	Bachelor of Medical Laboratory Technology	I.Sc	3yr.+6 Months of Internship
BMRIT	Bachelor of Radio Imaging Technology	I.Sc	3yrs.+6 Months of Internship
B.Ophth.	Bachelor of Ophthalmology	I.Sc	4yr.+6 Months of Internship
B.Ed.	(Special Education)	Graduate	1yr.

1 YEAR ABRIDGED DEGREE FOR DPT / DOT

DIPLOMA COURSES :

DPT	Diploma In Physiotherapy	I.Sc (Bio)	3yrs.+6 Month of Internship
D-X-Ray	Diploma In X-Ray Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DMLT	Diploma In Medical Laboratory Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DECG	Diploma In E.C.G.	I.Sc (Bio)	2yr.
DOTA	Diploma In O.T. Technology	I.Sc (Bio)	2yr.
DHM	Diploma In Hospital Management	Graduate	1yr.
CMD	Certificate in Medical Derssing	Matirc with Science & English	1yr.

ADMISSION OPEN

Form & Prospectus -
Can be obtained from the office against a payment of Rs. 500/-. only by cash. Send a DD of Rs. 550/- only in the favour of Indian Institute of Health Education & Research, Patna, for postal delivery.

डा. अनिल सुलभ
निदेशक प्रमुख

"टी.आई." ब्राण्ड शटरपत्ती
क्वालिटी में सर्वोत्तम

मजबूती हमारी सुरक्षा आपकी.....

AL अलीगढ़ लॉक्स TM प्रा.लि.

पीरमुहानी,जगत जननी माता मन्दिर के नजदीक, पटना–3
फोन : 0612-3293208, 6500301, Email : aligarhlocks@gmail.com

अपने क्षेत्र बिहार का प्रथम एवं एकमात्र TM प्रतिष्ठान
नक्कालों से सावधान
कृपया हमारे इस नाम से मिलते–जुलते प्रतिष्ठान को देख भ्रमित न हों।

चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

04 मई–10 मई 2015

Postal Regn. No. DL (ND)-11/6139/2015-17, RNI No. DELHIN/2009/30467

उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड

बीमार स्वास्थ्य व्यवस्था

आखिर इस मर्ज़ की दवा क्या है

प्रभात रंजन दीन

उत्तर प्रदेश सरकार की यह आधिकारिक स्वीकारोक्ति है कि पिछले 10 साल में प्रदेश में संक्रामक रोगों से 2016 मौतें हुई हैं. सरकार कहती है कि वर्ष 2005 से 2014 के बीच के 10 वर्षों में 178235 लोग संक्रामक रोगों की चपेट में आए जिसमें कुल 2016 लोगों की मौत हो गई. इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका पर मांगे गए जवाब में उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में यह बात कही है. इन सरकारी आंकड़ों के अनुसार 10 वर्ष की इस अवधि में सबसे अधिक 127484 मरीज डायरिया के शिकार हुए, जिसमें 1276 रोगियों की मौत हो गई. इस दरम्यान 18316 लोग चिकन पॉक्स (चेचक) से ग्रस्त हुए, जिसमें 31 लोगों की मौत हुई. खसरा से 13210 लोग बीमार हुए, जिनमें 410 रोगियों की मौत हुई. इस 10 साल में 11304 लोग गैस्ट्रो से पीड़ित हुए, जिसमें 137 रोगियों की मौत हुई. मैनेंजाइटिस से 147 लोग प्रभावित हुए जिनमें 19 मौतें हुईं और कालाजार से पीड़ित हुए 330 रोगियों में सात रोगियों की मौत हो गई. इस अवधि में हैजा से 137 लोग पीड़ित हुए, लेकिन सरकार कहती है कि हैजा से कोई भी रोगी मरा नहीं.

उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 10 वर्ष की इस अवधि में 4128 रोगी डेंगू का शिकार हुए, जिनमें 46 रोगियों की मौत हो गई. स्वाइन फ्लू से इन दस वर्षों में 1536 लोग रोगी बने, जिनमें से 49 रोगियों की मौत हो गई. अब आप सरकारी आंकड़ों की सच्चाई भी परखते चलिए. सरकार कहती है कि 2005 से 2014 के बीच 49 रोगियों की मौत हुई. जबकि सरकार के आधिकारिक आंकड़े यह भी बताते हैं कि अकेले इस साल (2015) में जनवरी के पहले हफ्ते से लेकर मध्य अप्रैल तक के करीब सवा तीन महीने में स्वाइन फ्लू से 27 रोगियों की मौत हो गई. स्वाइन फ्लू से इस कदर आक्रांत हो रहे उत्तर प्रदेश में तीन महीने में 27 मौतें और दस साल में 49 मौतों का तथ्यात्मक विरोधाभास सामने है. हालांकि इस तरह की सरकारी झांसापट्टियों के उजागर होने से सरकार की खाल पर कोई असर नहीं पड़ता.

स्वाइन फ्लू के सम्बन्ध में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में डॉ. नूतन ठाकुर की जनहित याचिका के जवाब में प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक विजयलक्ष्मी ने पिछले दिनों अदालत को यह जानकारी दी थी और बाकायदा हलफनामा पेश किया था. उन्होंने हलफनामे पर बताया था कि इन तीन महीनों में टैमीफ्लू 75–एमजी के 3.62 लाख टेबलेट खरीदे गए थे, जिसमें 1.56 लाख टेबलेट विभिन्न जिलों में वितरित किए गए और 2.06 लाख टेबलेट निदेशालय में रखे गए. इसी तरह टैमीफ्लू 45–एमजी के 50,000 टेबलेट में से 9,000 टेबलेट जिलों में भेजे गए और 41,000 टेबलेट निदेशालय में रखे गए. टैमीफ्लू 30–एमजी के 1.28 लाख टेबलेट में से 47,000 टेबलेट जिले में रखे गए और 81,000 टेबलेट निदेशालय में रखे गए थे. प्रदेश की स्वास्थ्य महानिदेशक ने बताया था कि चार जनवरी से 12 अप्रैल के बीच प्रदेश के 44 जिलों में 1534 स्वाइन फ्लू केस दर्ज हुए, जिसमें 27 रोगियों की मौत हो गई. इसमें अकेले लखनऊ में 1064 केस दर्ज हुए और आठ रोगियों की मौत हो गई. सरकार के इस विरोधाभासी बयानों के बीच प्रदेश में स्वाइन फ्लू का कहर जारी है. बसपा नेता अय्यूब खां समेत कई लोग स्वाइन फ्लू की वजह से मारे गए. सरकार का ही आंकड़ा है कि मार्च महीने तक लखनऊ में ही स्वाइन फ्लू के 1381 मरीज भर्ती किए गए थे, जबकि अदालत में यह संख्या 1064 बताई गई थी. इस खतरनाक वायरस से देश भर में 34,000 से भी अधिक लोग प्रभावित हुए हैं. मरने वालों की संख्या 2,064 है.

स्वाइन फ्लू के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार की लापरवाही उजागर होती रही है. स्वास्थ्य महकमे के बड़े अधिकारी अपने कमरों से बाहर नहीं निकलते और सारी जिम्मेदारी सामान्य और छोटे दर्जे के कर्मचारियों पर रहती है. वही स्वाइन फ्लू के मरीजों के संपर्क में रहते हैं. इलाज करते–करते कई स्वास्थ्यकर्मियों के खुद स्वाइन फ्लू की चपेट में आ जाने की खबरें आ चुकी हैं. उन्हें पहले से वैक्सीन भी नहीं लगाया जाता. हैरत यह है कि वैक्सीन आई तो अधिकारियों ने खुद ही लगा लिया, जबकि उनका रोगियों से कोई पाला नहीं पड़ता. जो स्वास्थ्यकर्मी फील्ड में जाकर मरीज़ों की देखभाल कर रहे हैं उनके लिए वैक्सीन बच ही नहीं पाई. स्वाइन फ्लू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की इस तरह की अनगिनत लापरवाहियां लगातार जारी हैं. ऐसी लापरवाहियों के विरोध में मेरठ मेडिकल कालेज के जूनियर डॉक्टर काली पट्टी बांध कर सरकारी इंतजामात पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं. उनका स्पष्ट आरोप था कि केवल कागजों पर ही स्वाइन फ्लू के बचने के उपाय हो रहे हैं. हकीकत में कुछ भी नहीं है, न दवा है न मास्क है. इस वजह से सभी डॉक्टर ओपीडी में काम नहीं कर पा रहे हैं. जूनियर डॉक्टरों की मांग को सही मानते हुए सीनियर डॉक्टरों ने भी कह दिया था कि मास्क नहीं मिले तो वो भी काम से अलग रहेंगे. विडंबना यह है कि अस्पतालों में नर्सों तक के लिए मास्क उपलब्ध नहीं कराए गए थे. सरकारी अस्पताल में एक नर्स को स्वाईन फ्लू होने के बाद मेडिकल कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई थी.

स्वाइन फ्लू को लेकर बरती जा रही लापरवाहियों को लेकर हाईकोर्ट यूपी सरकार को कई बार फटकार लगा चुका है. कोर्ट ने तीन दिन में टैमीफ्लू के तीन लाख टेबलेट और तीन लाख मास्क मुहैया कराने के निर्देश भी दिए थे. हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार की तरफ से सार्वजनिक स्थानों पर कीऑस्क के जरिए मास्क बेचने की ढीली–ढाली कवायद शुरू की गई थी. स्वास्थ्य विभाग के पास स्वाइन फ्लू से निपटने के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं. प्रदेश में मात्र दो ही जगह इसकी जांच हो पाती है. स्वाइन फ्लू के लिए अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड नहीं हैं. हर व्यक्ति हर जगह आता जाता रहता है और पीड़ित के परिवारीजनों को भी टैमी फ्लू की दवा का कोर्स दिए जाने के नियम–प्रावधान की अवहेलना की जाती है. इसमें डॉक्टर भी लापरवाही बरतते हैं.

स्वाइन फ्लू का वायरस दूसरे देशों से यहां आया. अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों व सीमा पर इसकी निगरानी ठीक से नहीं की गई, जिस वजह से यह फैलने लगा. लखनऊ व वाराणसी दोनों ही हवाई अड्डों पर सख्त चेकिंग और जांच का कोई इंतजाम नहीं किया गया था. नेपाल सीमा पर खासकर सोनौली–महाराजगंज, रुपईडीहा–बहराइच, गौरी फंटा–खीरी में भी मेडिकल चेक पोस्ट नहीं के बराबर हैं. स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए प्रदेश सरकार ने लखनऊ के पीजीआई व किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी को नोडल सेंटर बनाया हुआ है. केवल यहीं की प्रयोगशालाओं में जांच हो रही है.

स्वास्थ्य विभाग के लिए एक ही चारा है कि वह तापमान बढ़ने का इंतजार करता रहता है. अब तापमान बढ़ रहा है तो स्वाइन फ्लू का असर कम हो रहा है. दरअसल, स्वाइन फ्लू का वायरस तापमान बढ़ने पर बेअसर हो जाता है. 25 डिग्री से ऊपर तापमान रहा तो स्वाइन फ्लू का वायरस कमजोर पड़ जाता है. ठंड में या जल्दी–जल्दी बदलते मौसम में स्वाइन फ्लू का वायरस सक्रिय हो जाता है.

(शेष पृष्ठ 19 पर)

घातक जीवाणु बिखेरने वाला विमान!

2009 में स्वाइन फ्लू के जीवाणुओं का छिड़काव कर रहे जिंबाब्वे के विमान एमडी–11 अमेरिकी ऑपरेटेड विमान को चीन ने मार गिराया था. चीन ने आधिकारिक तौर पर बताया था कि वह विमान सीआईए से संबद्ध एविएंट एविएशन कंपनी का था. ऐसे ही संदेहास्पद उड़ान भरते अमेरिकी ऑपरेटेड विमान को भारत और नाइजीरिया की वायुसेना ने उतार लिया था, लेकिन उसे जाने दिया. चीन की घटना के कुछ ही दिन बाद 26 जून, 2009 को एएन–124 को मुंबई में फोर्स्ड लैंडिंग कराई गई. भारतीय वायुसेना ने अमेरिकी ऑपरेटेड विमान को मुंबई में उतरने पर विवश कर दिया. ऐसे ही दूसरे विमान को नाइजीरियाई वायुसेना ने उतरने पर विवश किया. नाइजीरिया वायुसेना ने तो उस विमान के चालक दल के सदस्यों को गिरफ़्तार भी कर लिया, लेकिन भारत यह हिम्मत भी नहीं दिखा पाया. मुंबई एयरपोर्ट पर विमान को 24 घंटे तक रोके रखा गया, लेकिन भारत सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की और आखिरकार विमान को जाने की इजाज़त दे दी गई. इस तरह के मर्दाना रवैये से हम आतंकवाद का सामना कर रहे हैं. ■

HOTEL ★ MINIPLEX

SPARSH ★ AC BANQUET HALL ★ RESTAURANT

www.chauthiduniya.com
चौथी दुनिया

जहालत की जिंदगी जीते हैं पुलिसवाले

वैष्णवी वंदना

सरकार के तीन साल बीत जाने के बाद अखिलेश को पुलिस वालों की याद आई है. जैसे-जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशासन तंत्र के उन-उन पुर्जों के रखरखाव का अधिक ध्यान आ रहा है, जो चुनावों में अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं और किसी को चुनाव जितवा सकते हैं और किसी को हरवा सकते हैं. पिछले तीन साल में लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस के कर्मचारियों की निजी जिंदगी के जहालत से भरे होने का मसला छिटपुट तरीके से उठता रहा. इसमें सबसे अहम था कि यूपी पुलिस के कर्मचारियों के परिवारों को रहने के लिए जो घर मिले हुए हैं, उनसे तो अच्छे बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुहल्ले हैं, जहां सरकार उनकी सुविधाओं के लिए कुछ ज्यादा ही मरी रहती है. लेकिन पुलिस वालों के घर कब गिर जाएं और किन-किन लोगों पर गिर जाएं, पता नहीं रहता. जर्जर मकानों में सड़ांध जैसी हालत में पुलिसकर्मियों के परिवार रहते हैं. बिजली और पानी के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है और कई इलाकों से तो यह भी खबरें हैं, पुलिस के आला अधिकारी ही पुलिस के सामान्य कर्मचारियों के परिवारों को पानी बेचते हैं. अब प्रदेश सरकार ने पुलिस कर्मचारियों के रहने वाले पुराने जीर्ण-शीर्ण आवासों को नया बनाने का निर्णय लिया है. थानों के लिए भी नए थाना भवन बनाए जाएंगे. पुलिसकर्मियों के लिए आवासीय एवं अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों को तेज करने के लिए समय सीमा का निर्धारण किया गया है. पुलिस विभाग में काफी पुराने बने जीर्ण-शीर्ण थानों के स्थान पर नए थाना भवन निर्मित कराए जाएंगे. पुलिस कर्मियों को आवासीय सुविधा देने के लिए जिलावार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए निर्माण कार्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है. पुलिस के विभिन्न अधिकारियों के कार्यालय और आवास तथा पुलिस लाइन से जुड़े निर्माण कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं.

आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 30 नवम्बर 2014 तक पुलिस के आवासीय एवं अनावासीय निर्माण कार्यों की संख्या 655 थी, जिनमें से 31 मार्च, 2015 तक अधिकांश लंबित ही पड़े थे. महज 223 काम पूरे किए जा सके हैं. खूबी यह है कि यह निर्माण कार्य खुद पुलिस आवास निगम प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजकीय निर्माण निगम, सी एंड डीएस, समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश पैक्सफेड, आवास एवं विकास परिषद तथा उत्तर प्रदेश जल निगम करा रहा है. आप अपनी नज़रों से हालात देखें तो पुलिसकर्मियों के साथ हो रहे सलूक का पूर्ण विरोधाभास दिखाई पड़ेगा. आला पुलिस अधिकारियों के आवास चमकते दिखाई देंगे और कर्मचारियों के आवास बदरंग. उन आवासों की छतें टपक रही होंगी और पानी की टोटियां सूख कर खराब हो चुकी होंगी. कमरे में बैठने या सोने वाले के सिर पर कब छत का टुकड़ा आ गिरे, कोई कह नहीं सकता. जान जोखिम में डाल कर सामान्य पुलिसकर्मी ड्यूटी करते हैं और उनके परिवार के लोग जान-जोखिम में डाल कर सड़ियल घरों में रहते हैं. उन्हें ही आला अधिकारी उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते. यह हाल केवल पुलिस लाइनों के जर्जर आवासों का ही नहीं है. बल्कि जहां कहीं भी आपको सामान्य पुलिसकर्मचारियों के आवास दिखें तो उनकी बदहाली का जायजा ले सकते हैं. अधिसंख्य आवासों के छज्जे गिर चुके हैं, छतों से पानी टपकता रहता है. दीवारें दरक चुकी हैं. लेकिन इन्हीं आवासों में पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ रहते हैं. पुलिसकर्मियों का कहना है कि जर्जर आवासों के बारे में संबंधित अधिकारियों को कई बार पत्र लिखे गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई. फिर उन्होंने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई. दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के आवास और कार्यालयों के रंगरोगन पर पैसा बहाया जाता है. लखनऊ पुलिस लाइन में परिवहन शाखा कार्यालय के सामने ब्लॉक नंबर तीन का छज्जा गिरने-गिरने को है. बैरक नंबर सात के पीछे मुख्य आरक्षी नरेंद्र सिंह के आवास का आधा छज्जा गिर भी चुका है. अर्से से उनके परिजन ऊपर के अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही. लाइन में तैनात बैद्यनाथ सिंह की पत्नी बुंदा सिंह ने घर के पीछे ही लगने वाले कूड़े के अंबार के चलते पिछले तीन साल से अपने घर के पीछे का दरवाजा ही नहीं खोला. बदबू से जीना मुहाल रहता है, लेकिन वे आखिर जाएं तो कहां जाएं. दरवाजा भी सड़ चुका है. दूसरी तरफ पुलिसकर्मियों के बैरक कंडम हैं पुलिस लाइन में बैरक नंबर सात, आठ, नौ और 10 को कंडम घोषित हुए कई साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके बनने की बारी नहीं आई. पुलिसकर्मी इन्हीं कंडम बैरकों में रहने और कंडम सिस्टम को कोसने को मजबूर हैं. बैरकों की छत दरक चुकी हैं. उसके गिरने का भय सताता रहता है.

कुछ ही दिनों पहले गाजियाबाद पुलिस लाइन में दो मकानों के छज्जे गिर गए थे. हरसांव पुलिस लाइन में बने तीन मंजिला मकानों में दो के छज्जे गिरने से गनीमत है कि कोई मरा नहीं. यहां के ढाई सौ फ्लैट जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं. इन फ्लैटों के रखरखाव के लिए शासन से बजट मांगा जाता है. लेकिन सरकार कुछ सुनती ही नहीं.

केवल लखनऊ ही क्या, प्रदेशभर की पुलिस लाइनों के जर्जर आवासों बनाने के लिए कई बार घोषणाएं होती रही, वे केवल घोषणाएं ही रहीं. स्थिति इतनी खराब है कि पुलिसकर्मी बाहर ड्यूटी करते हैं और उनकी जान अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर अटकी रहती है. पुलिस लाइन में अधिकांश जगहों पर बिजली के खुले तार का घोसला भी खतरे का जंजाल है. मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान पुलिसकर्मियों के जर्जर आवास ठीक कराने का आश्वासन दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भी कोई पहल नहीं हुई.

अभी कुछ ही दिनों पहले राजधानी लखनऊ की सआदतगंज कोतवाली में बने पुलिस क्वॉर्टर की दीवार ढहने से एक पुलिसकर्मी की पत्नी की मौत हो गई थी. कई-कई पुलिस क्वॉर्टर्स तो 90 साल से भी अधिक पुराने हैं. मरम्मत और रख-रखाव के अभाव में इनकी स्थिति और भी बदहाल हो चुकी है. जिनका आवास ग्राउंड फ्लोर पर है वे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी के नीचे नहीं खड़ा होते. इसी तरह लोग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के छज्जे पर नहीं खड़े होते. पुलिसकर्मी ही बताते हैं कि मकान के कुछ-कुछ हिस्से टूट-टूट कर गिरते रहते हैं.

अभी कुछ ही दिनों पहले गाजियाबाद पुलिस लाइन में दो मकानों के छज्जे गिर गए थे. हरसांव पुलिस लाइन में बने तीन मंजिला मकानों में दो के छज्जे गिरने से गनीमत है कि कोई मरा नहीं. यहां के ढाई सौ फ्लैट जर्जर हालत में हैं, जो कभी भी गिर सकते हैं. इन फ्लैटों के रखरखाव के लिए शासन से बजट मांगा जाता है, लेकिन सरकार कुछ सुनती ही नहीं. कॉन्सटेबल स्तर के पुलिसकर्मियों को एक-एक कमरे के फ्लैट आवंटित किए गए हैं. 1976 में जब गाजियाबाद जिला बना था, तभी ये फ्लैट भी बने थे, लेकिन इसके बाद कभी इन फ्लैटों के मेंटेनेंस का काम नहीं किया गया. इसी तरह वाराणसी में भी पुलिसकर्मियों को हमेशा जान का खतरा मंडरा रहा है. प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र होने के बावजूद पुलिसकर्मी और उनके परिवार कैसे रहेंगे, इसकी चिंता किसी को नहीं है. आवास तो जहालत की स्थिति में हैं ही, वाराणसी के नौ थानों की हालत भी खतरनाक है, जहां पुलिस को हमेशा यह डर सताता रहता है कि जिस छत के नीचे बैठकर वे काम करते हैं, वह कभी भी गिर सकती है. वाराणसी के चौक थाने की इमारत ब्रिटिश हुकूमत के समय ही बनी थी. इसके गेट पर आज भी निर्माण सन् 1904 लिखा दिखेगा. यहां का रसोइया भी खाना बनाने वाली जगह छत पर चादर लगाकर खाना बनाता है, क्योंकि छत से बराबर पानी रिसता रहता है. यह हाल केवल चौक का ही नहीं है, इससे भी पुराना है रोहनिया थाना. जिसका निर्माण सन् 1851 में हुआ था. इस थाना भवन को खतरनाक घोषित किया जा चुका है. रोहनिया के अलावा लंका, रामनगर, चेतगंज, कैंट, मंडुआ डीह, मिर्जामुराद और फूलपुर थाना भवनों को भी कई वर्ष पहले ही खतरनाक घोषित किया जा चुका है. इसके बावजूद उन्हीं खतरनाक भवनों में बैठ कर पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी देते हैं. सरकार की खाल पर कोई सुगबुगाहट ही नहीं हो रही. लोक निर्माण विभाग कहता है कि अभी पुराने भवनों का डेप्रिशिएशन-वैल्यू निकाला जा रहा है, उसके बाद नए भवनों का एस्टीमेट तैयार किया जाएगा. डेप्रिशिएशन-वैल्यू निकालने में लगी सरकार और सरकारी महकमों की दुष्टता में ह्यूमन-वैल्यू (मानवीय मुल्यों) का खुलेआम हनन हो रहा है, यह किसी को नहीं दिखता. ■

feedback@chauthiduniya.com

सांसद के हाथ में अलादीन का चिराग

मोदी न खाएं, हम तो खाएंगे

शत्रुंजय सिंह रैकवार

भ्रष्टाचार और कालेधन के खिलाफ सख्ती का नारा देकर प्रचंड बहुमत के साथ देश के सिंहासन पर काबिज हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न खाऊंगा और न खाने दूंगा का जुमला भुला दिया है. मोदी के उस कथन का उनके मंत्रियों, सांसदों और विधायकों पर कोई असर नहीं पड़ा है. तमाम ऐसे सांसद और विधायक हैं जो धन अर्जित करने के लिए वे सारे काम कर रहे हैं जो उन्हें जल्दी से जल्दी लखपति और लखपति से करोड़पति व करोड़पति से अरबपति बना सके. धन-सम्पदा का ऐसा ही मामला गोरखपुर के बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए भाजपा नेता कमलेश पासवान की आर्थिक तरक्की से दिख रहा है. लोकसभा चुनाव में पासवान द्वारा दिए गए चुनावी शपथ पत्र में उनके पास चल-अचल सम्पत्ति लगभग 06 करोड़ की थी. उनके सांसद बने एक वर्ष भी नहीं हुए कि गोरखपुर शहर के बीचों-बीच गोलघर के विशाल व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बलदेव प्लाजा के वे मालिक बन गए. उक्त सम्पत्ति कितने की होगी इसका कोई भी स्थानीय व्यक्ति अनुमान लगा सकता है. आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि दो करोड़ 92 लाख रुपये की तो केवल स्टाम्प ड्यूटी अदा की गई है. यह गोरखपुर रजिस्ट्रार कार्यालय की पहली ऐसी बड़ी स्टाम्प ड्यूटी है.

बांसगांव लोकसभा सीट से 2009 में चुनाव लड़ते समय कमलेश पासवान ने अपने शपथ पत्र में अपनी, पत्नी और बेटे की कुल सम्पत्ति 1,15,00,000 घोषित की थी. सांसद बनते ही कमलेश पासवान के ऊपर लक्ष्मी इतनी मेहरबान हुईं कि पांच साल उनकी सम्पत्ति में पौने नौ करोड़ रुपये का इजाफा हो गया. सांसद बनने के बाद कमलेश पासवान औसतन हर साल डेढ़ करोड़ रुपये की सम्पत्ति अर्जित करते रहे. अप्रैल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में कमलेश पासवान द्वारा दिए गए शपथ पत्र में उनके और उनकी पत्नी की कुल सम्पत्ति 10,12,08,775 रुपये घोषित की गयी थी. उन्हें सांसद बने एक वर्ष भी नहीं बीता कि वे कृष्णा डेवलपर्स के डायरेक्टर के रूप में बलदेव प्लाजा के मालिक बन गए. महराजंगज जिले के फरेन्दा विधानसभा क्षेत्र से निवर्तमान भाजपा विधायक बजरंग बहादुर सिंह पर विधायक रहते हुए ठेकेदारी से करोड़ों रुपये अर्जित करने के आरोप लगे थे. यह मामला लोकायुक्त तक पहुंचा, जिसकी जांच के बाद लोकायुक्त ने उन्हें विधायक से हटाए जाने की संस्तुति की और फरेंदा की सीट खाली हो गई थी. समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव दीपक रंजन का कहना है कि भाजपा की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अन्तर है. उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री लूट-खसोट में लगे हुए हैं और प्रधानमंत्री विदेश दौरे में मगन हैं.

ऐसी ही सख्ती अपेक्षित है

सांसद-विधायक निधि के बेजा इस्तेमाल का मुद्दा हो या जन प्रतिनिधियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने का, मसला उठता रहता है और उनका धंधा चलता रहता है. उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने ऐसे दो मामलों में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक और बहुजन समाज पार्टी के विधायक की विधान मंडल की सदस्यता समाप्त कर इस ओर पहला प्रभावकारी कदम उठाया है.

प्रदेश में अब तक होते रहे ऐसे मामलों में राजभवन की ओर से की गई इस पहली कार्रवाई से यह तो साफ हुआ है कि कम से कम अब जनप्रतिनिधि के तौर पर विधायक, सांसद अथवा सरकारों में बैठे मंत्री हों या सरकारी मुलाजिम उन्हें पद के दुरुपयोग से थोड़ा भय लगेगा. विधायकी के साथ-साथ ठेकेदारी के धंधे में लिप्त दो विधायकों भाजपा के बजरंग बहादुर सिंह और बसपा के उमाशंकर सिंह के खिलाफ प्रदेश के लोकायुक्त एनके मेहरोत्रा की विस्तृत जांच रिपोर्ट और उनकी संस्तुतियों को पुख्ता मानते हुए सम्बन्धित सदस्यों की विधानसभा सदस्यता समाप्त करने का आदेश देकर राज्यपाल राम नाइक ने इतिहास रचा. 29 जनवरी को राज्यपाल ने यह कार्रवाई संविधान के अनुच्छेद 192 के तहत की. राज्यपाल के आदेश के तहत दोनों ही विधायकों की सदस्यता वर्ष 2012 में हुए प्रदेश विधानसभा के आम चुनाव में विधायक चुने जाने के समय से ही समाप्त मानी गई. यानि, बतौर विधायक इन दोनों ने जिन सरकारी सुविधाओं का भोग किया तथा साथ ही वेतन और भत्ते लिए वह सभी इन्हें सरकारी कोष को वापस जमा कराने होंगे.

बजरंग बहादुर सिंह महाराजगंज की फरेन्दा सीट से भाजपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे. उमाशंकर सिंह बलिया की रसड़ा सीट से बसपा के टिकट पर विधायक चुने गए थे. लोकायुक्त को इन विधायकों के खिलाफ शिकायत मिली थी कि दोनों ही विधानसभा सदस्य होने के साथ-साथ सरकारी ठेकेदारी का काम भी कर रहे हैं. यानि नियम विरुद्ध लाभ के दो-दो पदों पर काम कर रहे हैं. लोकायुक्त संगठन ने पूरे मामले की जांच की तो शिकायतें सही पाई गईं, जिन्हें देखते हुए लोकायुक्त ने दोनों को विधायकी के अयोग्य पाया और राज्यपाल को यथोचित कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ अपनी रिपोर्ट भेजी थी. इस मामले में राजभवन ने केन्द्रीय चुनाव आयोग से भी राय मांगी थी और आरोपी विधायकों के पक्षों को जानने के लिए उनसे भी अलग-अलग मुलाकात की थी. ऐसे ही सफेदपोश धंधेबाजों में प्रदेश सरकार के दो मंत्रियों और एक विधायक का ताजा मामला अभी चल रहा है. खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ आय से अधिक अकूत सम्पति का मामला है तो माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली पर भी विद्यालयों को मान्यता देने तथा नकल माफियाओं के दबाव में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाओं के केन्द्र निर्धारित करने के नाम पर धन उगाही का मामला है. दोनों पर ही पद का दुरुपयोग कर आय से अधिक सम्पत्ति जमा करने के संगीन आरोप मय सबूतों के लोकायुक्त संगठन के पास हैं. इनके अलावा मुरादाबाद की विधायक लक्ष्मी गौतम पर भी ऐसे ही आरोप हैं. इन सभी मामलों में लोकायुक्त संगठन जांच कर रहा है. प्रजापति का मामला तो लगभग रोजाना ही नए खुलासों के साथ समाचार पत्रों और मीडिया में सुर्खियां बन रहा है.

प्रदेश की पूर्ववर्ती मायावती सरकार में हुए कई घोटालों और भ्रष्टाचार के लगभग एक दर्जन मामलों की जांच रिपोर्ट लोकायुक्त की संस्तुतियों के साथ मौजूदा सपा सरकार के पास कार्रवाई के लिए लम्बित है. महीनों से सरकार की ओर से इन प्रकरणों में कार्रवाई नहीं किए जाने के नाराज प्रदेश के लोकायुक्त ने राजभवन को भी इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है. राज्यपाल नाइक ने भी लोकायुक्त की रिपोर्ट पर सरकार और प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई से राजभवन को सूचित करने के निर्देश दिए हैं. पर, सरकार की चुप्पी सधी हुई है. पूर्ववर्ती मायावती सरकार के जमाने के एक दर्जन घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों, जिनमें माया सरकार के कई मंत्रियों सहित तमाम नौकरशाह और अन्य सरकारी मुलाजिम लोकायुक्त की रिपोर्ट के मुताबिक दोषी हैं, ऐसे मामलों में प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी सपा सरकार कार्रवाई करने क्यों बच रही है, यह सरकार क्या, आम नागरिक भी समझता है.

लाभ के दो पदों पर आजम भी

लाभ के दो पदों पर काम करने का मामला वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री आजम खान के खिलाफ भी लम्बित है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में यह मामला चल रहा है कि आजम खान विधायक होने के कारण प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं और जौहर अली युनिवर्सिटी के कुलाधिपति भी बने बैठे हैं. आजम खान ताकतवर मंत्री हैं, लिहाजा उन पर कार्रवाई भी देर से ही होगी. विधायक होते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई में देर नहीं लगती. ■

feedback@chauthiduniya.com

भ्रष्टाचार का कारनामा, ईमानदारी का हलफनामा

दीनबंधु कबीर

उत्तर प्रदेश सरकार के कलयुगी प्रतिनिधि यादव सिंह ने अदालत में कह दिया कि उसने कभी कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं. यादव सिंह को शर्म भले नहीं आई हो लेकिन उसके इस हलफनामे से अदालत जरूर शर्मा गई होगी. भ्रष्टाचार से अकूत सम्पत्ति जमा करने वाले नोएडा प्राधिकरण के निलंबित चीफ इंजीनियर यादव सिंह का दावा है कि उसने कभी किसी भी मामले में भ्रष्टाचार नहीं किया और अपना सरकारी दायित्व पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाया. उसने यह बात सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. नूतन ठाकुर द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका के जवाब में पेश किए गए हलफनामे में कही है. हलफनामे में यादव सिंह ने कहा है कि जनहित याचिका में दी गई किसी कंपनी से उसका कोई संबंध नहीं है.

यादव सिंह ने कहा है कि उस पर नोएडा में हुई एफआईआर अभियंता आरपी सिंह और रामेंद्र की लड़ाई का नतीजा थी. जिसे सीबी-सीआईडी ने गलत पाते हुए अंतिम रिपोर्ट लगा दी. वह कभी देश छोड़ कर नहीं गए और न ही उसका कुसुमलता से कभी तलाक हुआ, जैसा जनहित याचिका में लिखा है. पत्नी कुसुमलता 1997 से कुसुम गार्मेंट्स चलाती हैं, जिसकी मौजूदा कीमत 1.07 करोड़ है. छापे में उसके घर से मात्र 11.5 लाख रुपये नगद और 2.86 किलो सोना निकला था. उसके पास केवल 115 वर्गमीटर का एक प्लॉट है. इसके अलावा उसके परिवार की बताई जा रही सारी सम्पत्ति की सूचना भी गलत है. यादव सिंह ने कहा कि उसका मायावती के भाई आनंद कुमार से कोई राजनीतिक या व्यवसायिक संबंध नहीं है. हलफनामे के अनुसार, मीडिया ने इस मुद्दे को बिना तथ्यों के, तोड़मरोड़ कर सनसनी फैलाई. उसने कहा कि डॉ. नूतन ठाकुर ने अत्यंत आपत्तिजनक और मानहानि वाले आरोप लगाए हैं.

आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के छापे में करोड़ों रुपये नकद और दस्तावेजों के साथ यादव सिंह के पकड़े जाने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार हमेशा शीर्ष स्तरीय जांच से कन्नी काटती रही है. सीबीआई जांच से बचने के लिए सरकार ने सीबीसीआईडी से जांच कराने का आदेश दे दिया. लेकिन आधिकारिक दस्तावेजों से यह

पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में किसी भी कीमत पर सीबीआई जांच नहीं चाहती थी. सुप्रीमकोर्ट के आदेश पर काले धन की जांच के लिए बने एसआईटी के सदस्य सचिव उदय सिंह कुमावत ने 11 फ़रवरी 2015 को राज्य सरकार को पत्र लिख कर अब तक किए गए सभी प्रशासनिक और सिविल तथा आपराधिक न्यायिक कार्रवाई का ब्यौरा मांगा था, ताकि सीबीआई जांच पर निर्णय लिया जा सके.

इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव आलोक रंजन ने 13 फ़रवरी को कुमावत को जवाब दिया कि चूंकि प्रकरण इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए अभी समानांतर प्रक्रिया उचित नहीं होगी. लेकिन एसआईटी ने यूपी सरकार की दलील नामंजूर करते हुए 24 फ़रवरी को उत्तर प्रदेश सरकार से यादव सिंह मामले के सभी अभिलेख सीबीआई को देने के निर्देश दिए. प्रदेश सरकार ने इस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की. यादव सिंह प्रकरण की सीबीआई जांच के लिए दाखिल जनहित याचिका में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा पारित आदेश से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए. मुख्य न्यायाधीश डॉ. डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायाधीश मनोज मिश्र की बेंच के आदेश के अनुसार नोएडा विकास प्राधिकरण के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि यादव सिंह को निलंबित कर उनको चीफ इंजीनियर बनाए जाने और उनकी आय से अधिक सम्पत्ति के मामलों की अलग-अलग जांच कराई जा रही है. कोर्ट ने राज्य सरकार से यादव के खिलाफ आरोपों के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्रवाई से अवगत कराने को कहा था. लेकिन इस बारे में अदालत को अवगत नहीं कराया गया. भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार से काले धन पर बने एसआईटी के आदेशों पर यादव सिंह मामले के सभी अभिलेख सीबीआई को देने के निर्देश दिए थे. लेकिन सीबीआई जांच से बचने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्मा जांच आयोग की अधिसूचना जारी कर दी. अधिसूचना के मुताबिक एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना एक्सप्रेस-वे के निलंबित मुख्य अभियन्ता यादव सिंह द्वारा अपने पद पर कार्यरत रहते हुए निर्माण कार्य के ठेकों में संगठित एवं व्यापक रूप से की गई अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार की जांच करेगा. जांच आयोग के अध्यक्ष अवकाशप्राप्त जज अमरनाथ वर्मा ने मामले की जांच की औपचारिकताएं शुरू कीं, लेकिन आयोग की जांच किसी नतीजे पर नहीं पहुंची. जबकि मामले की जांच कर रही सीबीसीआईडी ने फाइनल रिपोर्ट भी पेश कर दी. विडंबना यह है कि यादव सिंह के भ्रष्टाचार की सीबीसीआईडी जांच यादव सिंह के अनुरोध पर ही कराई गई. और जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ, सीबीसीआईडी ने यादव सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को नकारते हुए मामले में अंतिम रिपोर्ट लगा दी. गृह विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पंडा ने भी हलफनामे के जरिए अदालत में झूठ परोस दिया. प्रमुख गृह सचिव ने यादव सिंह पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता दिया और कह दिया कि कोई साक्ष्य नहीं पाया गया. हलफनामे में सीबीसीआईडी जांच को पूरी तरह सही करार दे दिया गया. उल्लेखनीय है कि विदेशों में जमा कालेधन की जांच करने वाली एसआईटी ने ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के मुख्य इंजीनियर रहे यादव सिंह के घोटालों की सीबीआई से जांच कराने की सिफारिश कर रखी है. एसआईटी की सिफारिश यूपी सरकार ने नहीं मानी. सरकार इसे कानूनी गुत्थियों में उलझाने की कोशिश करती रही. सरकार का कहना था कि मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए इस पर अभी इंतजार किया जाए. प्रदेश सरकार ने न्यायिक आयोग की जांच को भी ढाल बनाया. यादव सिंह के भ्रष्टाचार मामले की जांच को लेकर व्यक्तिगत तौर पर नकारात्मक रवैया रखने वाले मुख्यमंत्री के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि रामपुर में मुलायम सिंह यादव का भव्य जन्मदिवस समारोह मनाने में यादव सिंह का पैसा खर्च हुआ था, इसीलिए इस प्रकरण को टाला जा रहा है. रामपुर में मुलायम सिंह यादव का भव्य जन्म दिवस समारोह मनाने पर हुए आलीशान खर्च पर सवाल उठने से नाराज होकर आजम खान ने मामले को घालमेल करने के इरादे से कहा था कि माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम और अबु सलेम के अलावा आतंकी संगठन तालिबान ने मुलायम का बर्थ-डे मनाने के लिए पैसे दिए हैं. सपा के सूत्रों ने ही कहा था कि जन्मदिवस समारोह पर दाऊद और सलेम का तो नहीं, लेकिन यादव सिंह का पैसा जरूर खर्च हुआ था. हालांकि सपा सूत्रों की इस सूचना का कोई आधिकारिक तथ्य नहीं, लेकिन मामले की सीबीआई जांच से बचने की कोशिश इस सूचना की सच्चाई की ओर इशारा करती है. सपा नेताओं का ही कहना था कि आजम ने दाऊद और सलेम का नाम लेकर यादव सिंह के काले धन के इस्तेमाल की चर्चा को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश की थी, जिसका खुलासा तभी हो पाएगा, जब मामले की सीबीआई जांच हो. ■

feedback@chauthiduniya.com

दस हजार करोड़ के घोटाले की सीबीआई जांच हो-भाजपा

रेनू शर्मा

आपदा पीड़ितों के लिए केंद्र सरकार ने दस हजार करोड़ रुपये से अधिक सहायता राशि राज्य सरकार को दी, लेकिन प्रदेश सरकार ने केंद्रीय राशि का समुचित उपयोग करने की बजाय भारी घोटाला किया है. लिहाजा, पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराने की जरूरत है. भाजपा दिग्गज नेताओं का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल से मिला और केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री व गंगोत्री की अलग-अलग विस्तृत रिपोर्ट सौंपी. भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने तीर्थयात्रियों की परेशानियों को देखते हुए कई अहम सुझाव के साथ हरीश सरकार के सुरक्षित यात्रा चारधाम यात्रा की पोल खोल कर रख दी. उन्होंने कहा कि निमचोली से केदारनाथ तक जाने के लिए सात किमी तक की पैदल यात्रा वहां पर जमी बर्फ की वजह से बाधित हो सकती है. इसलिए वैष्णो देवी ट्रस्ट की तरह 1200 रुपये प्रति यात्री हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की जाए और इसका खर्च सरकार वहन करे. भाजपा ने राज्य सरकार से कहा है कि स्थानीय व्यापारियों व चारधाम के पंडा समाज को तत्काल सरकार एक आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए. इसके अलावा भाजपा ने हजारों करोड़ की राशि के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया है. भाजपा ने कहा है कि आपदा पीड़ितों के लिए भेजी गई केंद्र सरकार की राशि पीड़ितों तक नहीं पहुंची और न ही पुनर्वास की कोई सही व्यवस्था की गई है.

भाजपा ने लोगों को रोजगार देने की मांग की और यात्रा रोड पर इनकी दुकानें तैयार करके स्थानीय व्यापारियों को नि:शुल्क प्रदान की जाए. बिजली के बिल व व्यापारियों के सेल टैक्स आदि पांच सालों के लिए माफ किए जाएं. केदारघाटी का फिर से सर्वे कराकर मुआवजा से वंचित लोगों को तत्काल राहत राशि प्रदान की जाए. यात्रा मार्ग पर शौचालयों एवं सफाई की व्यवस्था दुरुस्त की जाए. गौरीकुंड स्थान पर जो पहले कुंड रहा है, उसको तत्काल ठीक कराया जाए और बद्रीनाथ की सड़कें तत्काल प्रभाव से दुरुस्त कराई जाएं. कंचनगंगा व पागल नाले के पास ग्लेशियर की वजह से तीर्थयात्रियों को परेशानी होगी. बद्रीनाथ में व्यापारी काफी डरे हुए हैं, इसलिए अब तक वहां दुकाने नहीं लगी हैं. गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था ठीक नहीं है. यहां पर भी केंद्रीय फंड का उचित इस्तेमाल नहीं किया गया है. नेताला के पास 200 मीटर स्लिप जोन खतरनाक स्थिति में है और साथ ही बिशनपुर स्लिप की सड़क भी ठीक नहीं है. इसका ट्रीटमेंट सरकार द्वारा तुरंत कराने की जरूरत है. बिशनपुर स्लिप जोन की सड़क की भी स्थिति ठीक नहीं है. चणोती व भटवाड़ी में सड़कें पूरी तरह से धंस गई हैं. यमुनोत्री-बड़कोट से आगे का रास्ता काफी खराब है. धनौल्टी से आगे डाम्टा, वन्नीगांव व नौगांव की सड़कें भी खराब हैं.

जानकीचट्टी से यमुनोत्री पैदल चलते हुए रास्ते में राम मंदिर के पास पैदल का रास्ता काफी खराब है. आपदा आने के बाद आज तक स्थानीय लोगों को मुआवजा नहीं मिला है. कुछ स्थानों पर मजदूर कार्य कर रहे थे, लेकिन सामग्री में गुणवत्ता नहीं थी.

चारधाम यात्रा की रिपोर्ट भाजपा ने सूबे के राज्यपाल डॉ. के.के. पॉल को सौंप कर चारधाम यात्रा पर अपनी सियासत तेज करने का संकेत दे दिया. इसके साथ ही राज्यपाल से यह मांग किया कि यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो. इसको लेकर राज्यपाल सरकार पर दबाव डालें, ताकि बिना बाधा के चारधाम यात्रा संपन्न हो सके. भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तीरथ सिंह ने कहा कि भाजपा की चारधाम यात्रा के पीछे मूल मकसद यह है कि देश-विदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा के दौरान किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं हो. साथ ही, बाहरी तीर्थयात्रियों को हर तरह की जानकारी राज्य सरकार उपलब्ध कराए. उन्होंने कहा कि भाजपा चाहती है कि अधिक से अधिक संख्या में तीर्थयात्री चारधाम में शामिल हों. भाजपा चाहती है कि किसी हाल में यात्रा बाधित न हो. उन्होंने कहा कि अब तक तो यात्रा मार्ग के दोनों ओर दुकानें सज जाती थीं, लेकिन इस बार इसका अभाव दिख रहा है. तीरथ सिंह ने मुख्यमंत्री के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के बयान को गलत तरीके से जनता के सामने पेश कर रहे हैं. उन्हें तो यात्रा व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए. तीरथ ने माना कि सरकार ने पूरी ताकत केदारनाथ पर लगाई. इससे अन्य धामों की सड़कों की हालत खस्ता हो गई है. उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केदारनाथ पर सरकार ने पूरी ताकत लगाई. इसके बावजूद वहां अब अव्यवस्थाएं नजर आ रही हैं.

चारधाम यात्रा के विभिन्न मार्ग के इर्द-गिर्द करीब 200 से ज्यादा डेंजर जोन की पहचान अब तक की गई है. अब तक महज 75 से 90 डेंजर जोन पर विशेष व्यवस्था हो पाई है. डेंजर जोन की शिनाख्त करने का काम काफी देर से शुरू किया गया. शासन ने शुरू में यह जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन को सौंपी थी, लेकिन मैन पावर की कमी की वजह से यात्रा मार्ग के आसपास के डेंजर जोन की पहचान नहीं हो पाई. बाद में शासन ने डेंजर जोन की पहचान के लिए पुलिस की मदद ली. बीते दिनों आईजी संजय गुंज्याल ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और पाया कि 170 से ज्यादा डेंजर प्वांइट हैं, जहां पहले कई हादसे भी हो चुके हैं. प्रदेश के गृह विभाग के मुताबिक, चारधाम यात्रा के पहले सभी पहचान किए गए डेंजर प्वांइटों पर विशेष सुरक्षा की व्यवस्था कर दी जाएगी, ताकि दुर्घटनाओं को टाला जा सके.

feedback@chauthiduniya.com

पृष्ठ 17 का शेष

बच्चों की रहस्यमय मौत : बीमारी या जैव आतंकवाद

हैरत यह है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसकी सीमा से लगे बिहार के जिलों में हर साल रहस्यमय बीमारी आती है और हजारों बच्चों की जिंदगी ले जाती है. लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार इस पर कोई ध्यान ही नहीं देती. न कोई इलाज ढूंढा गया और न इस रहस्यमय बीमारी की जड़ें तलाशी गईं. डॉक्टर हो या नेता या नौकरशाह, सब इसे जापानी इंसेफ्लाइटिस तो मैनिंजाइटिस तो कोई रहस्यमय बीमारी बता कर अपना विद्रुत वक्तव्य जारी करते और अपनी दुकान चलाते रहते हैं बच्चे मरते रहते हैं. इसकी रोकथाम पर कोई निर्णयात्मक चर्चा नहीं होती. चौथी दुनिया ने ही पूर्व में यह सवाल भी उठाया था कि उत्तर भारत में फैल रहा अनजाना ज्वर कहीं जैव आतंकवाद के प्रयोग का परिणाम तो नहीं है? पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तर पश्चिमी बिहार और इससे सटे नेपाल के तराई इलाक़े में मस्तिष्क ज्वर से रोज़ हो रही औसतन सौ बच्चों की मौत की वजह कहीं जैव आतंकवाद के प्रयोग के लिए गिनी-पिग बनाए जाने की वजह से तो नहीं हो रही? अगर रोग का इलाज नहीं मिल रहा तो कम से कम इन सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए. गोरखपुर समेत पूर्वांचल के जिलों और बिहार के सीमाई जिलों में औसतन सौ बच्चे रोज़ मर रहे हैं, जो बच रहे हैं, वे जीने लायक़ नहीं रहते. कहीं यह देश की नई फसल बर्बाद करने की साज़िश के तहत तो नहीं हो रहा? इन सवालों में दम है, क्योंकि इस रहस्यमय महामारी के आगे राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों फेल है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं संत कबीर नगर समेत आठ ज़िले खास तौर पर इस कथित जापानी इंसेफ्लाइटिस से हर साल आक्रांत रहते हैं. इनके साथ-साथ बिहार के छपरा, सीवान और गोपालगंज जैसे सीमावर्ती ज़िलों में भी यह रोग हर साल फैलता है और हजारों बच्चों की जान लेता है. इन मौतों पर केंद्र और प्रदेश सरकारों का उपेक्षात्मक रवैया आपराधिक है. लखनऊ के प्रसिद्ध फिज़ीशियन डॉ. नीरज भसीन कहते हैं कि जापानी इंसेफ्लाइटिस की मृत्यु दर तक़रीबन 50 फीसदी है. इस बीमारी से जो बच भी जाते हैं, उनके शरीर और स्नायु तंत्र का नुक़सान (रेसीड्यूअल डैमेज) इतना हो चुका होता है कि बाक़ी की ज़िंदगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती. डॉ. नीरज भसीन भी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग गंदगी-मच्छर को इसकी वजह बताता है, यह वजह अगर है तो यह रोग पूरे भारत में क्यों नहीं फैल रहा? खास इलाक़े में ही बार-बार इसका प्रकोप क्यों हो रहा? उन्होंने भी यह सवाल सामने रखा और पूछा कि सरकार अपना प्राथमिक दायित्व भी पूरा क्यों नहीं कर रही है? बहरहाल, इस रहस्यमय बीमारी के परिप्रेक्ष्य में इन प्रसंगों पर ध्यान देते चलें. अमेरिका के फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में कीटाणु आधारित आतंकवाद की आशंकाओं पर कुछ अर्सा पहले हुए सेमिनार में चर्चा का विषय ही था कि पैथोजेन-इंफेक्टेड वेक्टर एवं एडीज़ मच्छरों के ज़रिए फैलाए जाने वाले जैव आतंकवाद का मुक़ाबला कैसे किया जाए. होम लैंड सिक्यूरिटी को लेकर हुए इस आयोजन में आए विशेषज्ञों ने माना था कि विषाणुओं से इंफेक्टेड मच्छर हालांकि बहुत विषाणु फैला चुके हैं, लेकिन जापानी इंसेफ्लाइटिस और चिकनगुनिया से अमेरिका उस तरह आक्रांत नहीं है, जिस तरह भारत आक्रांत है. विशेषज्ञों का कहना था कि कीटाणुओं के बारे में सतही जानकारी रखने वाले आतंकी गुट भी भारत जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट वाले देशों में इसका आसानी से प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उन पर नियंत्रण के कोई उपाय नहीं कर रही है. जैव आतंकवाद के संवेदनशील मसले पर फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में आयोजित सेमिनार का आयोजन विश्वविद्यालय के पैथोजेंस इंस्टीट्यूट, फ्लोरिडा मेडिकल एंटोमोलॉजी लेबोरेट्री और यूएसडीए सेंटर फॉर मेडिकल एग्रीकल्चरल एंड वेटरीनरी एंटोमोलॉजी की तरफ़ से किया गया था. चर्चित किताब वर्ल्ड एट रिस्क के लेखक, पूर्व गवर्नर एवं सिनेटर बॉब ग्राहम भी इस गोष्ठी में शामिल थे. भारतीय सुरक्षा विशेषज्ञ भी कहते हैं कि जैव आतंकवाद से निबटने का कोई कारगर उपाय नहीं है. बंगलुरू स्थित नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का इस दिशा में कुछ काम चल रहा है. विश्व स्वास्थ्य संगठन के पैसे पर एनडीएमए ने इंटीग्रेटेड डिज़ीज़ सर्विलांस प्रोग्राम भी शुरू कर रखा है. नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिज़ीज़ इसकी नोडल एजेंसी है, लेकिन पूर्वांचल में फैल रहे इस महारोग पर कोई ध्यान ही नहीं है. नेशनल डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की कुछ बटालियनें खास तौर पर जैव, रासायनिक, रेडियोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर आतंकवाद से निबटने के लिए प्रशिक्षित की गई हैं. पर अफसोस यह है कि किसी को पूर्वी उत्तर प्रदेश की रहस्यमय बीमारी नहीं दिख रही, जिसने यहां के मासूम बच्चों को गिनी-पिग बना डाला है. हर बार जब बारिश का मौसम आता है, मौत का कहर साथ लेकर आता है और वह केवल पूर्वांचल पर ही बरपता है. ■

कार्यालय नगर पालिका परिषद गोला गोकर्णनाथ (खीरी)

भूतभावन कल्याणकारी आशुतोष, भगवान शिव की नगरी छोटी काशी, गोला गोकर्णनाथ-खीरी में नगर पालिका परिषद परिवार अपने नगर व नगर के सन्निकट ग्रामीण क्षेत्र के समस्त प्रबुद्ध नागरिकों, व्यापारियों, चिकित्सकों, उद्यमियों, विद्यार्थियों, करदाताओं, श्रद्धालुओं, पत्रकार बन्धुओं, अधिवक्ताओं व जन प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनन्दन करती है तथा हिन्दु-मुस्लिम, सिख-ईसाई की गंगा-जमुनी संस्कृति की पहचान ऐतिहासिक मेला चैती 2015 में उनके द्वारा प्रदान किए गए अमूल्य समय, सहयोग, प्रेरणा व मार्गदर्शन के लिए धन्यबाद ज्ञापित करती है.

मेला के आकर्षण

चैती मेला में बच्चों के लिए विभिन्न झूले व खेल तमाशे, युवाओं के लिए मौत का कुंआ, महिलाओं के लिए उपयोगी घरेलू वस्तुओं के स्टाल की उत्तम व्यवस्था. प्रतिदिन कीटनाशक तथा चूने का छिड़काव, जनरेटर द्वारा पर्याप्त विद्युत, भजन संध्या रामायण गोष्ठी, भोजपुरी, कवि सम्मेलन-मुशायरा, स्कूल के बच्चों का कार्यक्रम, आधुनिक आर्केस्ट्रा, गायन प्रतियोगिता वायस ऑफ गोला, नृत्य प्रतियोगिता, काला जादू, कठपुतली इत्यादी के माध्यम से मनोरंजन की अपार व्यवस्था.

समापन समारोह

मेला चैती 2015 का समापन दिनांक 11/04/2015 दिन शनिवार को रात्रि 8.00 बजे स्थान श्री नीलकण्ठ तीर्थ ग्राउंड पर मुख्य अतिथि माननीय डॉ. शिव प्रताप यादव, जन्तु उद्यान मंत्री उत्तर प्रदेश शासन व मा. श्री रवि प्रकाश वर्मा सांसद(राज्य सभा) राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी की अध्यक्षता में सम्पन्न होगा. इस अवसर पर पुरस्कार वितरण, स्मारिका विमोचन तथा बाबा सत्य नरायन मौर्य, सैण्ड आर्टिस्ट मुम्बई द्वारा भारत माता की आरती का सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी होगा.

हमारी उपलब्धियां

1.सार्वजनिक निर्माण : नगर में राज्य वित्त आयोग, 13 वां वित्त आयोग, 2 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी तथा पालिका निधि के अन्तर्गत विगत एक वर्ष में नगर के विभिन्न वार्डो/मोहल्लों में इण्टरलाक, सीमेण्टेड, डामर सड़कों का निर्माण कराया गया जिससे नागरिकों को आवागमन की बेहतर सुविधा प्राप्त हो सके, नगर की जल निकासी हेतु नाला नालियों का निर्माण कराया गया.

2.सफाई व्यवस्था : दो नग टैम्पो/टिपर, दो नग ट्रैक्टर मय हाइड्रोलिक ट्राली, एक नगर लोडर, 60 नगर हत्थू ठेला, फावड़ा, फावड़ी, पचई अन्य सफाई उपकरण व सामग्री क्रय कर सीमित संसाधनों से नगर में बेहतर सफाई व्यवस्था तथा सफाई व्यवस्था में नित नए सुधार/प्रयास निरन्तर जारी हैं.

3.जलपूर्ति : नगर में पेयजल की सुविधा हेतु लगभग 10 किमी. पाइप लाइन का विस्तार किया गया, एक नग मिनी नलकूपों की स्थापना, क्लोरीनेशन हेतु इलेक्ट्रानिक डोजर की स्थापना. नगर पालिका द्वारा अपने सीमित संसाधनों से नागरिकगणों को बेहतर पेयजल आपूर्ति के लिए कृत संकल्प, विशेष अवसरों पर जनरेटर द्वारा पेयजल आपूर्ति.

4.मार्ग प्रकाश : नगर की पथ प्रकाश व्यवस्था हेतु 200 नग सोडियम लाइट, सोलर लाइट व 400 नग सी.एफ.एल. क्रय की गई तथा नगर के प्रमुख स्थानों पर सोडियम लाइट की स्थापना नगर के समस्त हाईमास्ट की मरम्मत करा कर नगर में उत्तम पथ प्रकाश व्यवस्था.

प्रस्तावित योजनायें

1. नगर के लगभग अवशेष विकास कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण किए जाने का लक्ष्य.
2. नगर की जल निकासी हेतु बड़े नालों का निर्माण कराये जाने का लक्ष्य.
3. नगर के पार्कों/सार्वजनिक स्थलों का जीर्णोद्धार/सौन्दर्यीकरण कराये जाने का लक्ष्य.

अच्छी सेवा तथा सुविधा के लिए नागरिकों से अपील है कि:-

1.पालिकों के करों यथा गृहकर, जलकर, जलमूल्य तथा किराया दुकान का समय से भुगतान कर छूट का लाभ उठायें तथा अधिकार से बचें.
2.पालिका की अनुज्ञाओं का समय से नवीनीकरण करायें.
3.सफाई के उपरान्त कूड़ा कचरा सड़क पर न फेंके.
4.जल ही जीवन है, जल की बचत करें. आवश्यकता अनुसार ही कम से कम पानी का प्रयोग करें तथा प्रयोग के उपरान्त पानी की टोटियों को खुला न छोड़ें.
5.सड़कों पर अतिक्रमण न करें.
6.सड़कों/खड़न्जा आदि पर जानवरों को न बांधे तथा पशुओं को आवारा खुला न छोड़ें.
7.जन्म-मृत्यु का पंजीकरण(21 दिन के अन्दर) अवश्य कराये.

विनोद कुमार गुप्ता
अधिशासी अधिकारी/उपजिलाधिकारी
समस्त कर्मचारीगण

मीनाक्षी अग्रवाल
अध्यक्ष
समस्त सभासदगण

नगरपालिका परिषद, गोला गोकर्णनाथ-खारी.